

वाणिज्य बैंकों के कार्य और उनका कार्य-निष्पादन

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बेहतर रहा। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) के बैंकिंग कारोबार ने पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण में 22.9 प्रतिशत और जमाराशि में 18.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। तदनुसार 2010-11 में एससीबी का बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात बढ़कर 76.5 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 73.6 प्रतिशत था। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण मार्जिन पर बढ़ते दबाव के बावजूद एससीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ 2009-10 के 1.05 प्रतिशत से बढ़ कर 1.10 प्रतिशत हो गया। बासेल I और II संरचनाओं के तहत पूंजी-जोखिम भारांकित आस्ति अनुपात 2010-11 में क्रमशः 13.0 प्रतिशत और 14.2 प्रतिशत था जो कि 9 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यकता से काफी ऊपर था। सकल गैर निष्पादक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात 2009-10 के 2.39 प्रतिशत से कम होकर 2010-11 में 2.25 प्रतिशत रह गया जो कि बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में सुधार का द्योतक है। बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार होने के बावजूद वित्तीय समावेशन लगातार काफी कम बना रहा। बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी।

1. परिचय

बैंकों का कार्य निष्पादन वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन की गतिशीलता से प्रेरित था

4.1 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र, जो कि भारतीय वित्तीय क्षेत्र को दर्शाता है, द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के सबसे बुरे परिणाम किसी सीमा तक सह लेने के बावजूद इसे संकटोत्तर समय के दौरान चुनौतीपूर्ण समष्टिआर्थिक वातावरण से गुजरना था। वित्तीय संकट से पहले वैश्विक वित्तीय क्षेत्र सामान्यतः यूरोपीय सरकारी ऋण संकट और यूरो जोन तथा अमरीका में भी वृद्धि में सुधार की धीमी गति से परेशान था। इसके विपरीत 2010-11 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने उनके पश्चिमी प्रतिपक्षियों की तुलना में बेहतर निष्पादन दिया। किंतु संकटोत्तर समय के दौरान भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से अनेक को मुद्रास्फीति को सहने योग्य स्तर पर बनाये रखते हुए आर्थिक वृद्धि में सुधार लाने की चुनौती का सामना करना पड़ा। मुद्रास्फीति को सहने योग्य स्तर पर बनाये रखने के लिए

रिजर्व बैंक ने भी 2010-11 के दौरान मौद्रिक कड़ाई की। तदनुसार 2010-11 के दौरान वाणिज्य बैंकों के कार्य और निष्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में आये निष्पादन वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन की गतिशीलता से प्रेरित था।

बैंकों ने चुनौतीपूर्ण परिचालनात्मक वातावरण में कार्य किया

4.2 2010-11 के दौरान उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण न केवल ऋण वृद्धि में मंदी संबंधी चिंता उभरी बल्कि उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता में सामान्य रूप से संभाव्य कमजोरी के आधार पर आस्ति गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी बढ़ी। कड़े ब्याज दर वातावरण ने 2010-11 में मार्जिन कम रहने की संभावना के चलते वाणिज्य बैंकों की लाभ संभावना कम कर दी। वर्ष के दौरान एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिक ऋण लेने के कारण भी क्षेत्रवार ऋण में तेजी के संभाव्य निर्माण के माध्यम से वित्तीय मजबूती संबंधी चिंता उभार दी। 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में

सहभागी होने के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा भारी उधार लेने, सरकारी व्यय में कमी आने और उच्च मुद्रास्फीति के कारण लोगों द्वारा अपने पास रखी गयी मुद्रा की व्यापक मात्रा से 2010-11 में चलनिधि की काफी कमी हो गयी। इसके अलावा बासेल II के तहत पूंजी स्तरीकरण के उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की आवश्यकता भी एक ऐसी चुनौती थी जो कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर छाया हुई थी। इसके साथ ही और अधिक नवोन्मेषी बनना अति आवश्यक था ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकीय विकासों से कदम मिलाकर चला जा सके, ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारी जा सके और बैंकिंग सुविधा रहित गांवों को लाभदायक कारोबारी क्षेत्र बनाकर वित्तीय समावेशन की गति बढ़ायी जा सके।

4.3 इस पृष्ठभूमि में यह अध्याय अन्य बातों के साथ-साथ ऋण नियोजन, लाभप्रदता, सुदृढ़ता मानदंड और क्षेत्रीय पहुंच के संदर्भ में 2010-11 में भारत में वाणिज्य बैंकों के परिचालनों और निष्पादन का विश्लेषण करता है। यह अध्याय भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उभरते मुद्दों को रेखांकित करने के लिए 83 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों¹, 1,82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के चार बैंकों के 2010-11 के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों का विश्लेषण करता है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रीय परिचालन

एससीबी के समेकित तुलनपत्रों ने उच्च वृद्धि दर्ज की

4.4 एससीबी के समेकित तुलनपत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। यह पिछले दो वर्षों में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत है और वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव कम होने का संकेत है। एससीबी के समेकित तुलनपत्रों में उच्च वृद्धि में सभी बैंक समूहों का योगदान था जिसका अपवाद निजी क्षेत्र के पुराने बैंक थे जिन्होंने वृद्धि में कुछ गिरावट दर्ज की थी। सर्वाधिक वृद्धि निजी

क्षेत्र के नये बैंकों ने दर्ज की जिनके बाद सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का स्थान था। फिर भी मार्च 2011 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में से तीन चौथाई भाग पीएसबी का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंकों (15 प्रतिशत) का स्थान था। सबसे कम भाग निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का था (लगभग चार प्रतिशत) जिनके बाद विदेशी बैंकों (लगभग सात प्रतिशत) का स्थान था।

तुलनपत्र का देयता पक्ष पूंजी, उधार और अन्य देयताओं से प्रेरित था

4.5 तुलनपत्र के देयता पक्ष में वृद्धि मुख्यतः पूंजी, उधार और अन्य देयताओं तथा प्रावधानीकरण से प्रेरित थी। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से शेयर बाजार से निधि जुटाना 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की पूंजी में वृद्धि होने के मुख्य कारण थे। 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्रों में विशेष बात बचत बैंक जमाराशि तथा मांग जमाराशि में वृद्धि में गिरावट आना और सावधि जमाराशि वृद्धि बढ़ना था। इसका कारण प्रचलित उच्च ब्याज दरें हो सकता है जिससे बचत और मांग जमाराशि की तुलना में सावधि जमाराशि अधिक आकर्षक हो गयी थी।

तुलनपत्र का आस्ति पक्ष ऋणों और अग्रिमों से प्रेरित था

4.6 तुलनपत्र के आस्ति पक्ष में वृद्धि मुख्यतः ऋणों और अग्रिमों से प्रेरित थी। कड़े ब्याज दर वातावरण के बावजूद सभी बैंक समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। 2010-11 में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों की ऋण वृद्धि पिछले वर्ष के उनके निष्पादन की तुलना में विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। उल्लेखनीय रूप से बैंकिंग क्षेत्र की निवेश वृद्धि में पिछले वर्ष की

¹ इनमें सरकारी क्षेत्र के 26 बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और इसके पांच सहयोगी बैंक, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आईडीबीआई बैंक लि.), निजी क्षेत्र के 7 नये बैंक, निजी क्षेत्र के 14 पुराने बैंक और 36 विदेशी बैंक शामिल हैं।

सारणी IV.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2011 के अंत में				विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक		
1	2	3	4	5	6	7
1. पूंजी	19,055	4,805	1,396	3,409	35,383	59,243
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	2,71,196	1,33,784	22,425	1,11,359	45,668	4,50,648
3. जमा राशियां	43,72,985	10,02,759	2,64,157	7,38,602	2,40,689	56,16,432
3.1. मांग जमा	4,10,109	1,58,929	24,222	1,34,707	72,900	6,41,939
3.2. बचत बैंक जमा राशियां	10,83,001	2,29,130	49,667	1,79,463	39,650	13,51,782
3.3. सावधि जमा	28,79,874	6,14,699	1,90,268	4,24,432	1,28,138	36,22,712
4. उधार	3,95,144	1,85,984	10,967	1,75,017	92,797	6,73,925
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	2,35,438	70,844	10,066	60,778	76,992	3,83,273
कुल देयताएं / आस्तियां	52,93,817	13,98,176	3,09,011	10,89,166	4,91,528	71,83,522
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	3,52,379	86,111	18,173	67,938	20,293	4,58,783
2. बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	1,32,225	31,616	3,908	27,708	27,365	1,91,206
3. निवेश	13,28,534	4,22,020	92,617	3,29,403	1,65,499	19,16,053
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क+ ख)	10,82,515	2,63,181	64,603	1,98,578	1,11,960	14,57,657
क) भारत में	10,74,411	2,62,252	64,603	1,97,649	1,11,960	14,48,624
ख) भारत के बाहर	8,103	929	-	929	-	9,033
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	3,098	89	51	38	2	3,189
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	2,42,920	1,58,750	27,962	1,30,787	53,537	4,55,207
4. ऋण और अग्रिम	33,05,632	7,97,534	1,84,647	6,12,886	1,95,539	42,98,704
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	1,83,405	33,013	9,875	23,138	25,182	2,41,600
4.2 केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि.	13,97,114	2,03,756	84,039	1,19,717	91,172	16,92,042
4.3 सावधि ऋण	17,25,113	5,60,765	90,733	4,70,032	79,185	23,65,063
5. अचल आस्तियां	36,156	12,980	2,509	10,470	4,958	54,093
6. अन्य आस्तियां	1,38,892	47,915	7,156	40,760	77,874	2,64,681

-: नगण्य

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। इस सामान्य प्रवृत्ति का एकमात्र अपवाद निजी क्षेत्र के नये बैंक थे जिन्होंने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में निवेश में उच्च वृद्धि दर्ज की (सारणी IV.1 और IV.2)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख देयताएं

जमाराशि

जमाराशि में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.7 जमाराशि जो कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं का 78 प्रतिशत होती है, ने हाल के वर्षों की प्रवृत्ति के विपरीत 2010-11 में उच्च वृद्धि दर्ज की। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के नये बैंकों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में अधिक जमाराशि संग्रह करना था। जमाराशि वृद्धि में तेजी का प्रमुख कारण सावधि जमाराशियां थीं। पहले कहे अनुसार इसका कारण उच्च ब्याज दर वातावरण हो

सकता है जिससे सावधि जमाराशि दरें बढ़ गयी थीं। जहां सावधि जमाराशि की तेज वृद्धि तुलनपत्र की स्थिरता की दृष्टि से अच्छी बात हो सकती है क्योंकि यह खुदरा जमाराशि का आधार बढ़ाती है और आस्ति देयता असंतुलन कम करती है; वहीं यह बैंकिंग क्षेत्र का ब्याज-व्यय बढ़ा सकती है जिससे लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

कुल वृद्धिशील जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा कम हुआ

4.8 विपरीत रूप से चालू खाता और बचत खाता (सीएसएसए) जमाराशियां, जो कि न्यूनतम लागत स्रोत हैं, का हिस्सा 2010-11 में कम हो गया। यह देखना महत्वपूर्ण है कि 1 अप्रैल 2010 से बचत जमाराशियों पर दैनिक उत्पाद आधार पर प्रतिलाभ बढ़ने के बावजूद 2010-11 में सभी बैंक समूहों में पिछले वर्ष की तुलना में बचत जमाराशि संग्रह में गिरावट आयी। इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण निधि

सारणी IV.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि

(प्रतिशत)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2009-10		2010-11		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. पूंजी	0.1	40.7	7.3	5.6	8.7	9.7	6.7	4.1	19.7	15.9	12.3	21.9
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	16.8	19.2	21.0	15.9	15.9	18.7	22.0	15.4	12.3	18.2	17.5	18.1
3. जमा राशियां	18.6	18.4	11.7	21.9	15.4	14.9	10.4	24.6	8.4	3.7	16.8	18.3
3.1. मांग जमा	18.4	11.3	33.5	18.1	22.5	12.2	35.9	19.2	12.7	6.8	20.9	12.4
3.2. बचत बैंक जमा राशियां	25.8	22.1	32.8	23.0	26.2	14.0	34.9	25.8	26.5	8.8	26.9	21.8
3.3. सावधि जमा	16.2	18.2	1.3	22.5	12.0	15.5	-3.1	25.8	2.2	0.6	12.9	18.2
4. उधार	21.4	25.9	8.5	24.5	40.6	26.4	6.9	24.4	-11.9	36.0	12.2	26.8
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	4.2	21.4	8.5	20.9	8.4	-1.0	8.5	25.5	-29.7	16.9	-4.6	20.4
कुल देयताएं / आस्तियां	17.9	19.2	12.0	21.5	15.8	14.9	10.9	23.5	-2.2	12.9	15.0	19.2
1. आरबीआई के पास नकदी और शेष	20.8	30.1	32.0	13.5	27.7	7.4	33.3	15.2	22.1	6.3	23.1	25.4
2. आरबीआई के पास नकदी और शेष बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर मुद्रा	-12.9	15.6	13.9	-18.2	-43.3	-31.3	38.0	-16.0	-34.2	33.1	-11.6	10.1
3. निवेश	20.0	9.3	15.5	19.2	15.3	10.9	15.6	21.7	22.2	3.9	19.3	10.8
3.1 सरकारी प्रतिभूतियां (क +ख)	19.0	7.4	10.6	9.1	13.4	6.2	9.7	10.1	17.5	-4.7	17.3	6.6
क) भारत में	18.8	7.4	10.6	8.8	13.4	6.2	9.7	9.7	17.5	-4.7	17.2	6.6
ख) भारत के बाहर	48.2	-3.0	72.6	464.8	-	-	72.6	464.8	-	-	48.6	6.1
3.2 अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-36.8	-38.2	43.4	-71.4	56.2	-82.2	-31.7	74.8	-41.7	-57.1	-34.6	-40.2
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियां	28.4	20.1	27.6	41.0	20.5	24.9	29.5	45.0	37.7	28.1	29.2	27.6
4. ऋण और अग्रिम	19.6	22.4	9.9	26.1	19.9	19.8	7.1	28.1	-1.3	19.8	16.6	22.9
4.1 खरीदे गए और भुनाए गए बिल	10.4	30.3	30.7	20.2	19.1	10.3	37.2	25.0	46.9	18.2	16.3	27.5
4.2 कैंश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, आदि.	22.9	26.9	9.6	28.4	20.8	23.4	2.5	32.1	2.5	24.8	19.9	27.0
4.3 सावधि ऋण	18.1	18.2	9.0	25.7	19.2	17.8	7.0	27.3	-13.4	14.9	14.4	19.8
5. अचल आस्तियां	2.2	4.9	3.6	26.8	8.0	6.5	2.4	32.8	2.6	2.0	2.5	9.1
6. अन्य आस्तियां	-0.2	32.9	-11.6	21.6	7.4	12.6	-14.5	23.3	-30.1	14.0	-14.1	24.7

-: नगण्य

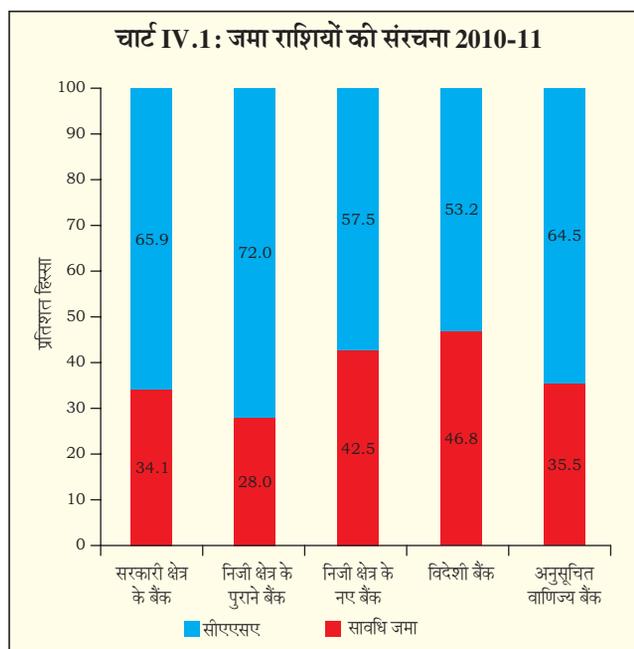
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्र।

का अधिक ब्याज दरों के कारण सावधि जमाराशि में अंतरित हो जाना था। किंतु अप्रैल 2011 में बचत जमाराशि दर 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.0 प्रतिशत करने और अक्टूबर 2011 में बचत जमाराशि पर ब्याज दर विनियमन हटाने से आगे इसमें सुधार होने की अपेक्षा है। किंतु ब्याज दर विनियमन हटाने से प्रतिस्पर्धी वातावरण में बचत जमाराशि पहले जैसी कम लागत वाली नहीं रह जाएगी। वृद्धि में गिरावट के अनुरूप कुल वृद्धिशील जमाराशि में चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों का हिस्सा पिछले वर्ष के 48 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में कम होकर 36 प्रतिशत रह गया। बैंक समूह स्तर पर किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों में सर्वाधिक हिस्सा विदेशी बैंकों का था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंक और पीएसबी का स्थान था (चार्ट IV.1)।

अदावी जमाराशियों की वृद्धि में गिरावट आयी

4.9 रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती अदावी जमाराशियों के प्रति चिंता प्रकट की और अगस्त 2008 में एससीबी को सूचित

किया कि वे ऐसे ग्राहकों को ढूंढने के अधिक प्रयास करें। परिणामस्वरूप 2008 से अदावी जमाराशियों की वृद्धि दर में कमी

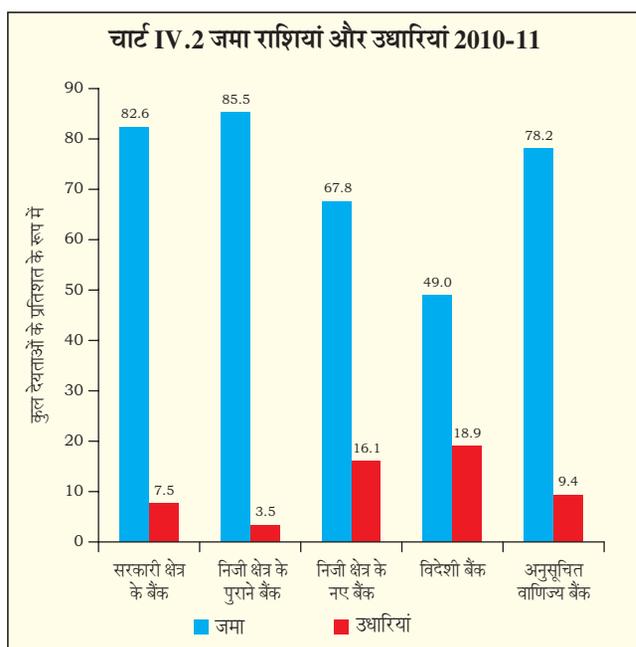


आयी। अदावी जमाराशियों की वृद्धि दर दिसंबर 2008 के 18 प्रतिशत और दिसंबर 2009 के 15 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2010 में 5 प्रतिशत रह गयी। महत्त्वपूर्ण रूप से चालू खाते और मीयादी जमाराशि खाते की अदावी जमाराशि पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2010 के अंत में कम हो गयी। किंतु कुल जमाराशि में अदावी जमाराशि का हिस्सा पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी लगभग 0.02 प्रतिशत बना रहा।²

उधार

उधार में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.10 उधार, जो कि बैंकिंग क्षेत्र की कुल देयताओं का नौ प्रतिशत है, ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि दर्ज की। बैंक समूह स्तर पर कुल देयताओं में उधार के हिस्से में काफी भिन्नता देखी गयी। उधार पर विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों की निर्भरता अन्य बैंक समूहों की तुलना में अधिक थी (चार्ट IV.2)।



² जमाराशि के आंकड़े एससीबी की जमाराशि और ऋण की तिमाही सांख्यिकी से लिये गये।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रमुख आस्तियां

बैंक ऋण

ऋण और अग्रिम वृद्धि बढ़ी

4.11 यह उल्लेखनीय है कि कड़ी मौद्रिक नीति के संदर्भ में ऋण उठाव में धीमेपन, वर्ष-दर-वर्ष, की व्यापक चिंता के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋण और अग्रिम में वृद्धि हुई। जहां हाल के वित्तीय संकट से आर्थिक रूप से बाहर निकलने से ऋण की मांग में वृद्धि हुई, वहीं आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से जमाराशि में उच्च वृद्धि और पूंजी में वृद्धि से उच्च ऋण वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की प्रवृत्ति दर्शाते हुए 2010-11 में अल्पावधि ऋण की तुलना में सावधि ऋण कम दर पर बढ़े। 2010-11 में निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने सावधि जमाराशि संग्रह की तदनुरूपी उच्च वृद्धि के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में सावधि ऋण में उच्च वृद्धि दर्ज की।

निवेश

निवेश वृद्धि में गिरावट आयी

4.12 उच्च ऋण वृद्धि के निभाव के कारण प्रतिभूतियों में निवेश की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो गयी। 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र के कुल निवेश का लगभग तीन चौथाई भारत में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में था जो कि मुख्यतः रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एसएलआर अपेक्षा पूरी करने और अल्पावधि मुद्रा बाजार से निधि जुटाने के लिए था। किंतु भारत में धारित सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकिंग क्षेत्र के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई जो कि 18 दिसंबर 2010 से एसएलआर अपेक्षा 25 प्रतिशत से कम करके 24 प्रतिशत करने के अनुरूप थी।

एसएलआर से भिन्न निवेश में गिरावट आयी

4.13 एससीबी के एसएलआर से भिन्न निवेश में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की तुलना में मार्च 2011 में कमी आयी। इसका

प्राथमिक कारण वाणिज्यिक पत्रों में निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आना था। वाणिज्यिक पत्रों में निवेश अल्पकालिक अधिशेष से आर्थिक लाभ लेने के लिए बैंकिंग क्षेत्र का अल्पकालिक निवेश होता है। ऐसे निवेश में गिरावट से 2010-11 के दौरान कड़ी चलनिधि स्थिति का पता चलता है। दूसरी ओर शेयरों में बैंकों के निवेश में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ बांडों/डिबेंचरों में बैंकों के निवेश में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ वृद्धि हुई (सारणी IV.3)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां³

अंतरराष्ट्रीय देयताओं में कम वृद्धि हुई

4.14 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताएं अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में कम दर पर बढ़ीं। फिर भी बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताएं हाल की पूर्ववर्ती अवधि जैसे ही 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय आस्तियों की तुलना में लगातार

लगभग दोगुनी बनी रहीं। बैंकिंग क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में वृद्धि में अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों के शेयरों, अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमा राशि और विदेशी मुद्रा उधार में वृद्धि का मुख्य योगदान था। (सारणी IV.4)।

अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में उच्च वृद्धि दर्ज हुई

4.15 अंतरराष्ट्रीय आस्तियों में हुई वृद्धि मुख्य रूप से निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण, निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिलों और नोस्ट्रो शेषों से प्रेरित थी (सारणी IV.5)।

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे⁴

समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में उच्च वृद्धि हुई

4.16 बैंकिंग क्षेत्र के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय दावों की क्षेत्रवार संरचना से पता चला कि यह मुख्यतः बैंकों पर दावे थे जिससे बैंकों के कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि हुई (सारणी IV.6)।

सारणी IV.3 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर एसएलआर निवेश

(राशि करोड़ रुपये में)

लिखत	25 मार्च 2011 को	कुल की तुलना में प्रतिशत	7 अक्टूबर 2011 को	कुल की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	12,310 (-51.1)	5.4	21,244 (-50.2)	8.1
2. शेयर	41,316 (37.2)	18.2	38,941 (15.0)	14.8
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	8,965	4.0	8,377	3.2
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	32,351	14.3	30,564	11.6
3. बांड / डिबेंचर	93,975 (49.7)	41.5	1,09,089 (47.0)	41.4
क) जिसमें से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	27,946	12.3	35,013	9.2
ख) जिसमें से, निजी कंपनी क्षेत्र	66,029	29.2	74,077	28.1
4. म्यूच्युअल फंड की इकाइयां	47,603 (-10.0)	21.0	61,806 (2.3)	23.5
5. वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए लिखत*	31,296 (-4.0)	13.8	32,326 (12.3)	12.3
कुल निवेश (1 से 5)	2,26,500 (11.3)	100.0	2,63,406 (9.8)	100.0

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े वर्ष पूर्व की तदनु रूप अवधि में प्रतिशत भिन्नता को दर्शाते हैं।

स्रोत: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत 42 (2) खंड की विवरणियां।

³ भौगोलिक रूप से भारत में स्थित सभी वाणिज्य बैंकों की शाखाओं की अंतरराष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां।

⁴ देशी वाणिज्य बैंकों की सभी शाखाओं (भारत और विदेश में स्थित) की अंतरराष्ट्रीय आस्तियां।

सारणी IV.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं - प्रकार - वार
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2010	2011	प्रतिशत घट-बढ़	
			2010	2011
1	2	3	4	5
1. जमा और उधार	3,38,574	3,78,221	4.8	11.7
जिसमें से:	(74.9)	(74.9)		
विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा (बैंक [एफसीएनआर (बी)] योजना विदेशी मुद्रा उधार *	72,234 (16.0)	77,413 (14.8)	-0.8	7.2
अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) जमा	74,354 (16.4)	95,419 (18.3)	-1.4	28.3
अनिवासी साधारण (एनआरओ) रुपया जमा	1,22,380 (27.1)	1,21,229 (23.2)	-1.7	-0.9
2. प्रतिभूति/बांड के अपने निर्गम	5,439	4,575	-20.8	-15.9
	(1.2)	(0.9)		
3. अन्य देयताएं	1,08,166	1,38,658	91.3	28.2
जिसमें से:	(23.9)	(26.6)		
एडीआर / जीडीआर	30,391 (6.7)	34,699 (6.7)	193.4	14.2
अनिवासियों के पास बैंकों की इक्विटीज	50,313 (11.1)	73,159 (14.0)	165.8	45.4
भारत में विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषण योग्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय देयताएं	27,462 (6.1)	30,799 (5.9)	0.8	12.2
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	4,52,179	5,21,454	17.0	15.3

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार तथा बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार शामिल है।
टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं की तुलना में प्रतिशत हैं।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

4.17 भारत से भिन्न देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में वृद्धि मुख्यतः जर्मनी, यूएई और यूएसए पर बैंकों के दावों से प्रेरित

थी। इसके विपरीत यूके और हांगकांग पर बैंकों के दावों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी (सारणी IV.7)।

सारणी IV.5: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ - प्रकार से
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये)

मद	2010	2011	प्रतिशत घट-बढ़	
			2010	2011
1	2	3	4	5
1. ऋण और निवेश	2,37,181	2,78,741	8.0	17.5
जिसमें से:	(96.3)	(96.8)		
क) अनिवासियों को उधार*	10,196 (4.1)	14,414 (5.0)	22.2	41.4
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा उधार**	1,23,476 (50.1)	1,40,083 (48.6)	23.5	13.4
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	50,496 (20.5)	61,321 (21.3)	13.3	21.4
घ) नोस्ट्रो शेष@	52,135 (21.2)	62,343 (21.6)	-21.6	19.6
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	39	179	-48.7	359.0
	(0.0)	(0.1)		
3. अन्य आस्तियाँ @@	9,139	9,147	-6.1	0.1
	(3.7)	(3.2)		
कुल अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ	2,46,359	2,88,067	7.4	16.9
	(100.0)	(100.0)		

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया उधार और विदेशी मुद्रा उधार को शामिल किया गया है।
** : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों से दिए गए उधार और विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण (पीसीएफसी) तथा एफसी दिए गए उधार और भारत के बैंकों में जमा राशियां आदि।
@ : विदेश में किए गए प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ।
@@ : भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्त लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय आस्तियाँ।
टिप्पणियाँ : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

सारणी IV.6 : भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण - परिपक्वता और क्षेत्रवार
(मार्च के अंत में)

अवशिष्ट परिपक्वता / क्षेत्र	(राशि करोड़ रुपये)	
	2010	2011
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	2,33,071	2,46,413
क) परिपक्वता - वार		
1) अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	1,44,638 (62.1)	1,53,893 (62.5)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष और ऊपर)	81,939 (35.2)	87,247 (35.4)
3) अनाबंटित	6,494 (2.8)	5,273 (2.1)
ख) क्षेत्र वार		
1) बैंक	98,191 (42.1)	1,09,142 (44.3)
2) बैंकेतर सार्वजनिक	1,442 (0.6)	870 (0.4)
3) बैंकेतर निजी	1,33,438 (57.3)	1,36,401 (55.4)

टिप्पणियाँ : 1) कोष्ठकमें दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
2) अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू नहीं (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3) बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आईएफसी, ईसीबी आदि) और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4) मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व, 'बैंकेतर सार्वजनिक क्षेत्र' में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य/केंद्रीय सरकारों की कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य / केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियों/संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर सार्वजनिक' क्षेत्र में केवल राज्य/केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देशगत जोखिम आधार।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण-जमाराशि तथा निवेश-जमाराशि अनुपात

बैंकों ने उच्च बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात की सूचना दी

4.18 ऋण-जमाराशि अनुपात और निवेश-जमाराशि अनुपात की प्रवृत्ति ने 2010-11 में निवेश की तुलना में ऋण को तरजीह मिलना दर्शाया। 2010-11 में बकाया ऋण-जमाराशि अनुपात 77 प्रतिशत पर अधिक था जो कि पिछले वर्ष 74 प्रतिशत था। इसके विपरीत 2010-11 में बकाया निवेश-जमाराशि अनुपात 34 प्रतिशत पर कम था जो कि पिछले वर्ष 36 प्रतिशत था। बैंक समूहों में 200-11 में सर्वाधिक निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने ऋण-जमाराशि अनुपात दर्ज किया जिनके बाद विदेशी बैंकों का स्थान था। किंतु निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा सूचित उच्च ऋण-जमाराशि अनुपात को सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है क्योंकि निधि के लिए

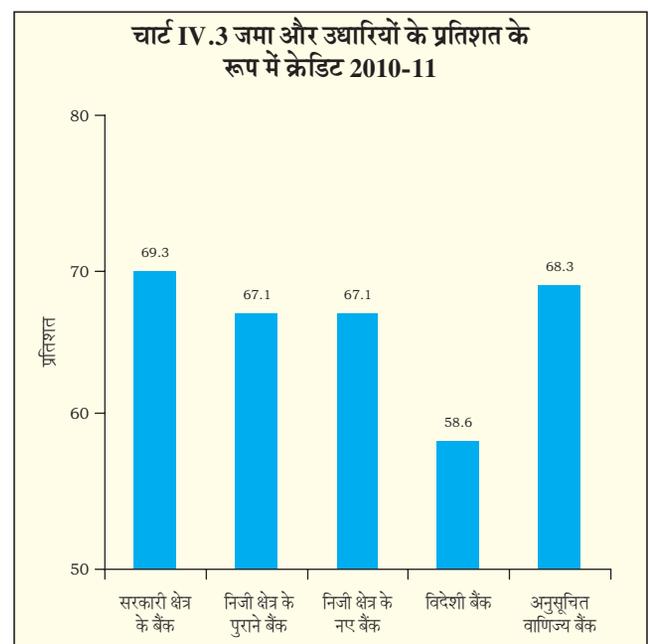
सारणी IV.7: भारत को छोड़कर अन्य देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे
(मार्च के अंत में)

मद	(राशि करोड़ रूप में)	
	2010	2011
1	2	3
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे	2,33,071	2,46,413
	(100.0)	(100.0)
जिसमें से:		
क) संयुक्त राज्य अमरीका	53,394 (22.9)	54,818 (22.2)
ख) यूनाइटेड किंगडम	36,141 (15.5)	34,370 (13.9)
ग) सिंगापुर	18,437 (7.9)	18,546 (7.5)
घ) जर्मनी	12,179 (5.2)	14,164 (5.7)
ङ) हांगकांग	18,978 (8.1)	18,376 (7.5)
च) संयुक्त अरब अमीरात	13,536 (5.8)	15,498 (6.3)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों में प्रतिशत अंश हैं।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश जोखिम आधार।

जमाराशि पर इन बैंक समूहों की निर्भरता अन्य बैंक समूहों की तुलना में कम है। ये बैंक समूह निधि की बड़ी मात्रा उधार के माध्यम से जुटाते हैं (चार्ट IV.2 देखें)। अतः किसी बैंक समूह तुलना के लिए अधिक अर्थपूर्ण अनुपात जमाराशि और उधार के प्रतिशत के रूप में क्रेडिट होगा। इस अनुपात के संदर्भ में पीसीबी प्रथम स्थान पर हैं जिनके बाद निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंकों का स्थान है (चार्ट IV.3)।

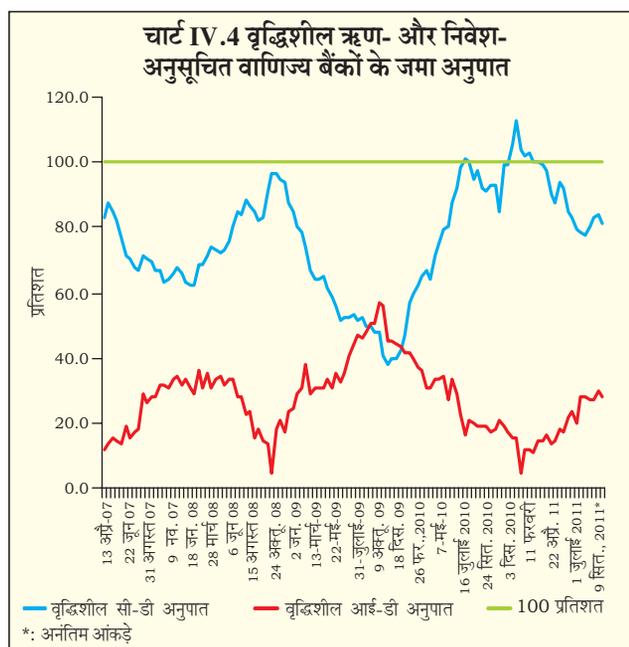


4.19 100 प्रतिशत से अधिक का वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात अर्थव्यवस्था में ओवरहीटिंग का एक सामान्य संकेतक है। 2010-11 की मजबूत ऋण वृद्धि के कारण 2010-11 की तीसरी तिमाही में ऋण-जमाराशि अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर चला गया। किंतु उसके बाद वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात में कमी आयी। तदनुसार वर्ष के उत्तरार्ध में वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात में सुधार हुआ (चार्ट IV.4)।

बैंकों की आस्तियों और देयताओं का अवधिपूर्णता प्रोफाइल

आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना में विशेष अंतर नहीं हुआ

4.20 बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल में बेमेल होना चिंता का विषय होता है क्योंकि इससे दीर्घावधि आस्तियों का अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषण होता है। आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना में दर्शाया कि मार्च 2011 के अंत में बैंकिंग क्षेत्र कि कुल जमाराशि और उधार का



लगभग आधा हिस्सा अल्पकालिक था। किंतु इसी अवधि में लगभग एक चौथाई कुल ऋण और अग्रिम तथा आधे से अधिक कुल निवेश दीर्घकालिक थे। आस्तियों और देयताओं की अवधिपूर्णता प्रोफाइल-वार संरचना में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में विशेष अंतर

सारणी IV.8: बैंक समूह-वार चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की परिपक्वता प्रोफाइल

(मार्च के अंत में)

(प्रत्येक मद के अंतर्गत कुल का प्रतिशत)

देयताएं / आस्तियाँ	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
I. जमाराशियाँ												
क) वर्ष तक	48.9	48.2	47.7	46.1	47.6	45.3	47.7	46.4	63.7	64.2	49.4	48.5
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	27.5	28.6	38.4	38.6	36.8	40.6	39.0	37.9	26.8	26.9	29.4	30.3
ग) 3 वर्ष से अधिक	23.6	23.2	13.9	15.2	15.6	14.1	13.3	15.6	9.5	9.0	21.2	21.1
II. उधार राशियाँ												
क) 1 वर्ष तक	42.0	40.1	34.7	42.4	49.0	54.5	33.9	41.7	74.6	78.7	44.2	46.2
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	11.0	12.5	23.9	16.2	15.6	12.5	24.4	16.4	14.7	14.8	15.3	13.9
ग) 3 वर्ष से अधिक	46.9	47.4	41.4	41.4	35.3	33.0	41.7	41.9	10.7	6.5	40.5	40.0
III. ऋण और अग्रिम												
क) 1 वर्ष तक	38.0	36.0	37.1	37.6	40.5	41.9	36.0	36.3	61.1	68.1	38.9	37.8
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	33.8	36.2	34.2	36.4	36.8	38.4	33.4	35.8	20.1	17.0	33.3	35.4
ग) 3 वर्ष से अधिक	28.2	27.7	28.7	26.0	22.7	19.7	30.6	27.8	18.8	15.0	27.8	26.8
IV. निवेश												
क) 1 वर्ष तक	18.8	18.1	38.1	37.3	24.4	28.7	42.4	39.7	76.4	79.0	28.1	27.6
ख) 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	12.2	12.7	21.6	22.4	8.8	12.2	25.6	25.3	15.2	14.6	14.4	15.0
ग) 3 वर्ष से अधिक	69.0	69.2	40.2	40.2	66.8	59.1	32.0	35.0	8.4	6.4	57.5	57.3

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलना पत्र।

बाक्स IV.1: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता असंतुलन: विस्तार और निरंतरता

दीर्घकालिक आस्तियों और देयताओं के अवधिपूर्णता प्रोफाइल के विश्लेषण से पता चलता है कि समग्र स्तर पर दीर्घकालिक आस्तियों का वित्तपोषण अल्पकालिक देयताओं से किया जाता है। दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घकालिक देयताएं घटाकर गणना किया गया एएलएम हाल के वर्षों में कभी भी नकारात्मक नहीं हुआ जिसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घकालिक ऋण घटक में देखी गयी उच्च वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र में असंतुलन बढ़ रहा है। एएलएम सकारात्मक अंतर का समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि बैंकिंग क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक के समूह में एएलएम सकारात्मक अंतर सर्वाधिक था जिसके बाद 3-5 वर्ष और 1-3 वर्ष का स्थान था। सितंबर 2010 के अंत में कुल एएलएम सकारात्मक अंतर में 5 वर्ष से अधिक के समूह में एएलएम सकारात्मक अंतर 42 प्रतिशत था जिसके बाद 3-5 वर्ष (31 प्रतिशत) और 1-3 वर्ष (27 प्रतिशत) का स्थान था।

मार्किज द्वारा विकसित पद्धति (2004) अपनाकर एएलएम सकारात्मक अंतर की निरंतरता का विश्लेषण किया गया। तदनुसार एएलएम सकारात्मक अंतर की निरंतरता का अनुमान माध्य रिवर्शन की अनुपस्थिति के आधार पर निकाला गया है, अर्थात्

$$\gamma = 1 - \left(\frac{n}{T} \right)$$

जहां एन का अर्थ टी+1 ऑब्जर्वेशन के साथ समय अंतरा के दौरान माध्य को श्रृंखला द्वारा जितनी बार क्रॉस किया गया वह है। सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध हो गया है कि सिमेट्रिक जीरो मीन व्हाइट नॉइस प्रोसेस में ई (वाई) = 0.5. इस प्रकार यदि वाई का मूल्य 0.5 के करीब है तो इसका अर्थ यह है कि कोई विशेष निरंतरता नहीं है। दूसरी ओर यदि वाई का मूल्य 0.5 से काफी अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि विशेष निरंतरता है। सिमेट्रिक जीरो मीन व्हाइट नॉइस प्रोसेस (शून्य निरंतरता) की धारणा के तहत निरंतरता वाई की नाप के सांख्यिकी महत्त्व की जांच के लिए निम्नलिखित सूत्र प्रयोग में लाया जाता है:

$$\left[\frac{\gamma - 0.5}{0.5} \right] \cap N(0;1)$$

नहीं हुआ जो आस्ति-देयता में बेमेल की निरंतरता दर्शाता है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति-देयता बेमेल की सीमा और निरंतरता का विश्लेषण बाक्स IV.1 में दिया गया है (सारणी IV.8)।

4.21 2010-11 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घावधि आस्तियों का लगभग 20 प्रतिशत अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषित हुआ था। अल्पावधि देयताओं से वित्तपोषित दीर्घावधि आस्तियों का प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम हो गया (सारणी IV.9)।

4.22 वित्तपोषण पक्ष में बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 23 प्रतिशत अल्पावधि देयताओं का प्रयोग 20 प्रतिशत दीर्घावधि आस्तियों के वित्तपोषण के लिए किया गया। दीर्घावधि आस्तियों के वित्तपोषण के लिए प्रयुक्त अल्पावधि देयताओं का प्रतिशत हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ कम हो गया (सारणी IV.9)।

सारणी :आस्ति देयता बेमेल (एएलएम) पॉजिटिव गैप की निरंतरता की नाप-बकेट-वार

टाइम बकेट	निरंतरता (γ)	महत्त्व (γ - 0.5)/(0.5/√T)
एक से तीन वर्ष	0.60	1.483 ^b (0.0606)
तीन से पांच वर्ष	0.47	-0.404 ^b (0.3264)
पांच वर्ष से अधिक	0.47	-0.404 ^b (0.3264)
कुल	0.47	0.405^b (0.3264)

b: 5 प्रतिशत स्तर पर शून्य निरंतरता की शून्य परिकल्पना की स्वीकार्यता।

टिप्पणी: विश्लेषण के लिए प्रयुक्त आब्जर्वेशनों की संख्या 55 है।

सभी एससीबी के लिए पूरी नमूना अवधि अर्थात् मार्च 2006 से सितंबर 2010 के दौरान एएलएम सकारात्मक अंतर के लिए वाई का मूल्य 0.47 है जो कि 0.5 से थोड़ा कम है। यह दर्शाता है कि समग्र स्तर पर संदर्भाधीन अवधि के दौरान एएलएम सकारात्मक अंतर में कोई विशेष निरंतरता नहीं थी। निरंतरता का समूह-वार विश्लेषण दर्शाता है कि किसी भी समय समूह में 5 प्रतिशत स्तर में कोई विशेष निरंतरता नहीं थी। किंतु 10 प्रतिशत स्तर में "एक वर्ष से तीन वर्ष" के समय समूह में निरंतरता थी (सारणी)। इस प्रकार सारांश के रूप में समग्र स्तर पर ही सही किंतु एएलएम सकारात्मक अंतर में विशेष निरंतरता नहीं थी, लेकिन "एक वर्ष से तीन वर्ष" के समय समूह में यह विशेष थी जिस पर सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है।

संदर्भ:

मार्किज, कार्लोस रोबालो (2004), "इन्फ्लेशन पर्सिस्टेंस: फॅक्ट्स ऑर आर्टफॅक्स?", बैंकिंग पेपर सं.371, जून, यूरोपीय केंद्रीय बैंक।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालन

बैंकों के तुलनपत्रेतर परिचालनों में लगातार वृद्धि हुई

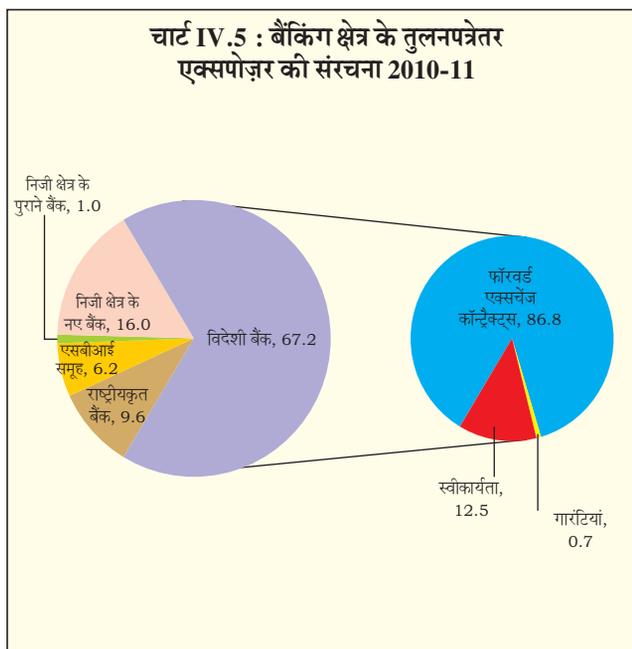
4.23 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीएस) भारी वृद्धि से संबद्ध जोखिम को दर्शाया। ओबीएस के जोखिमपूर्ण और अनिश्चित स्वरूप को पहचानते हुए रिजर्व बैंक ने अगस्त 2008 में ओबीएस संबंधी विवेकसम्मत मानदंडों को कड़ा किया।

4.24 बैंकिंग क्षेत्र का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर, जो कि पिछले दो वर्षों में कम हो गया था, 2010-11 में 31 प्रतिशत बढ़ा। 2010-11 में कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का तीन चौथाई से अधिक भाग वायदा विनिमय संविदाएं थीं। विदेशी बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र के कुल तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के दो

सारणी IV.9: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता बेमेल

क्र. बैंक समूह/वर्ष सं.	प्रतिशत			
	अल्पावधिक देयताओं द्वारा वित्त पोषित दीर्घकालिक आस्तियां*	दीर्घकालिक आस्तियों** का वित्त पोषण करने वाली अल्पावधिक देयताओं का प्रतिशत	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1 सरकारी क्षेत्र के बैंक	22.6	22.0	28.5	27.9
1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक#	24.1	22.3	27.3	24.6
1.2 एसबीआई समूह	19.7	21.4	31.8	38.2
2 निजी क्षेत्र के बैंक	14.4	15.7	19.6	21.0
2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	18.9	13.4	23.8	17.0
2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक	13.1	16.3	18.2	22.1
3 विदेशी बैंक	-16.2	-25.0	-6.4	-9.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	19.7	19.5	23.4	23.3

*: (दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घकालिक देयताएं घटाकर)*100 के रूप में गणना की गयी।
 **: (दीर्घकालिक आस्तियों से दीर्घ कालिक देयताएं घटाकर) अल्पकालिक देयताओं*100 के रूप में गणना की गयी।
 #: आईटीबीआई बैंक लि. सहित



तिहाई से अधिक बना रहा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस का विस्तृत विश्लेषण बाक्स IV.2 में दिया गया है (परिशिष्ट सारणी IV.1 और चार्ट IV.5)।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वित्तीय निष्पादन

लाभप्रदता

समेकित निवल लाभ में उच्च वृद्धि हुई

4.25 एक ओर उच्च ब्याज व्यय के कारण लाभप्रदता संबंधी व्यापक चिंताओं और दूसरी ओर उच्च अनर्जक आस्तियों और परिणामी उच्च प्रावधानीकरण अपेक्षाओं तथा कम ब्याज आय के बावजूद एससीबी के निष्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ।

4.26 बैंकिंग क्षेत्र के समेकित निवल लाभ में 2009-10 में हुई गिरावट के विपरीत 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जिसका प्राथमिक कारण ब्याज आय में उच्च वृद्धि था। 1 जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली लागू करने, जो कि कंपनी क्षेत्र को सब-प्राइम उधार देने पर रोक लगाती है, से 2010-11 में उच्च ब्याज आय में मदद मिली होगी और ऋण वृद्धि भी मजबूत रही। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण

2010-11 में ब्याज व्यय भी अधिक होने के बावजूद यह ब्याज आय वृद्धि की तुलना में काफी कम था। तदनुसार एससीबी की निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ।

"अन्य आय" वृद्धि में कमी आयी

4.27 "अन्य आय" में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र की व्यापार आय में गिरावट इस गिरावट का एक मुख्य कारण थी। किंतु "अन्य आय" में समग्र गिरावट के बावजूद "अन्य आय" का एक प्रमुख घटक अर्थात् कमीशन और दलाली में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई।

परिचालन व्यय की वृद्धि उच्च दर पर हुई

4.28 विपरीत रूप से, बैंकिंग क्षेत्र का परिचालन व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च दर पर बढ़ा जिसका मुख्य कारण पिछले एक वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में वेतन वृद्धि लागू होना था। इसके अलावा प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण सकल

**बाक्स IV.2: लाभप्रदता बनाम जोखिम:
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर का विश्लेषण**

तुलनपत्रेतर एक्सपोजर (ओबीएस) से चिंता उभरती है क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता पर इसका प्रभाव अनिश्चित है। चूक की स्थिति में तुलनपत्रेतर एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है जैसा कि हाल के वैश्विक वित्तीय संकट से प्रकट हुआ था। पिछले दस वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में और विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में काफी वृद्धि हुई। वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ के कारण ओबीएस पर नीति को अगस्त 2008 में कड़ा किया गया। परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में 2008-09 और 2009-10 में गिरावट आयी। किंतु सुधार की शुरुआत से बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस में 2010-11 में पुनः सकारात्मक वृद्धि हुई (चार्ट क)।

तथ्यतः विनिमय दर में घट-बढ़ और साथ ही उच्च ब्याज दर वातावरण से बैंकों के ग्राहकों से वायदा संविदाओं की मांग बढ़ती है जो कि बैंकिंग क्षेत्र के ओबीएस एक्सपोजर का सबसे बड़ा घटक है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ बैंकिंग क्षेत्र से ऐसी जोखिम प्रबंधन सेवाओं की मांग बढ़ती है। दूसरी ओर बैंकों की दृष्टि से ओबीएस एक्सपोजर, जो कि मूलतः शुल्क-आधारित सेवाएं हैं, से बैंकों की सकल आय में वृद्धि होती है, हालांकि इसमें जोखिम अधिक होती है। इस प्रकार यदि कोई बैंक अधिक जोखिम उठाता है तो उसे अधिक शुल्क आय का ओबीएस एक्सपोजर लाभ मिलता है।

"अन्य आय" उत्पत्ति में ओबीएस एक्सपोजर की भूमिका की समीक्षा पैनल डाटा रिगेशन विश्लेषण का उपयोग करके की गयी थी। पैनल डाटा रिगेशन बैंक समूह स्तर पर किया गया था। प्रयुक्त बैंक समूह-वार डाटा भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति की रिपोर्ट से लिया गया है।

"अन्य आय" का लॉग निर्भर चर के रूप में लिया गया। ओबीएस एक्सपोजर, तुलनपत्रीय आस्तियां और "अन्य आय" का पहला लॉग स्वतंत्र चर थे। इस प्रकार सांकेतिक रूप से अध्ययन में प्रयुक्त मॉडल को निम्नवत् लिखा जा सकता है:

$$\pi_{it} = c + \sum_{k=1}^K \beta_k X_{it}^k + \varepsilon_{it}$$

Where

$$\varepsilon_{it} = v_i + u_{it}$$

बैंक समूह की "अन्य आय", समय t में है जिसमें $i=1, \dots, N; t=1, \dots, T, c$ निरंतर टर्म है, X_{it} स्पष्टिकरणात्मक चर हैं और β_k व्यवधान है और v_i न देखा गया बैंक विशेष का प्रभाव है और u_{it} आईडियोसिन्करेटिक चूक है। हाउसमेंन जांच सांख्यिकी महत्त्वपूर्ण नहीं थी। इसलिए रैंडम इफेक्ट मॉडल के परिणाम दिये गये हैं। रिगेशन परिणाम नीचे दिये गये हैं (सारणी)।

सारणी: "अन्य आय" पर ओबीएस का प्रभाव

(नमूना अवधि: पांच बैंक समूहों में 2002 से 2010 के बीच प्राप्त विचार-50)
निर्भर वेरिएबल : "अन्य आय"

व्याख्यात्मक वेरिएबल	कोएफिसिएंट	टी-मूल्य
इंटरसेप्ट	-1.188	-1.750*
तुलन पत्र आस्तियां	0.365	3.715***
तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर	0.085	2.189**
"अन्य आय" का प्रथम लैग	0.480	4.172***
आर-स्क्वायर्ड: 0.89		
समायोजित आर-स्क्वायर्ड: 0.88		
डी डब्ल्यू सांख्यिकी: 1.44		

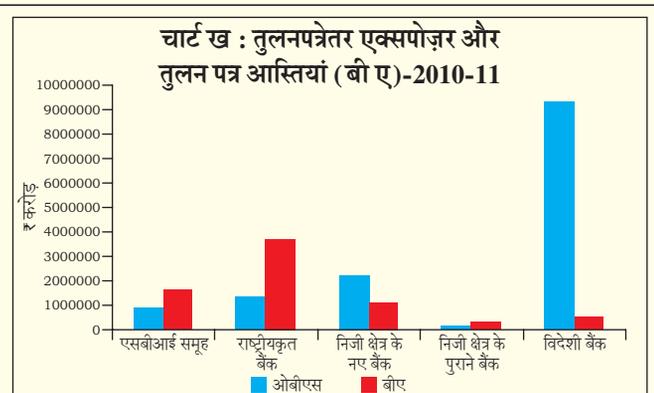
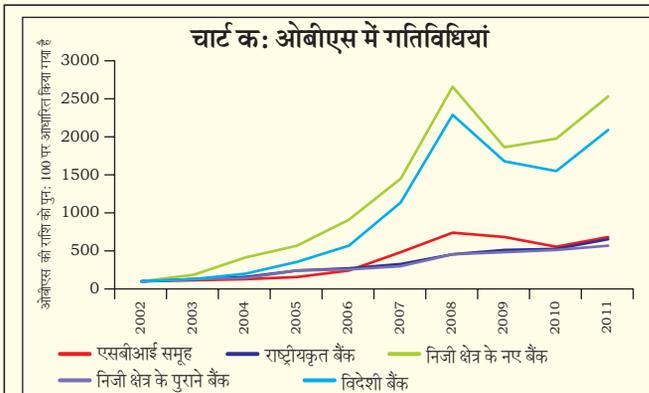
*: दस प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

**: पांच प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

***: एक प्रतिशत के स्तर पर महत्त्वपूर्ण।

परिणामों ने दर्शाया कि ओबीएस एक्सपोजर के एक प्रतिशत वृद्धि से बैंकिंग क्षेत्र की "अन्य आय" में 0.08 प्रतिशत वृद्धि होती है। इस प्रकार बेहतर "अन्य आय" और लाभ प्राप्त के लिए बैंक ओबीएस एक्सपोजर संचय का लाभ मिलता है।

दूसरी ओर इस ओबीएस एक्सपोजर से जुड़ी जोखिम को नापना कठिन है। किंतु यह उल्लेखनीय है कि मार्च 2011 के अंत में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कुल ओबीएस एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की कुल तुलनपत्रीय आस्तियों से अधिक था। इसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक थे। पीएसबी और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों ओबीएस एक्सपोजर अन्य बैंक समूहों की तुलना में कम था। इस प्रकार विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंकों की चूक की स्थिति में ये एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं (चार्ट ख)।



सारणी IV.10 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आय और व्यय का रुझान

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2009-10		2010-11	
	राशि	प्रतिशत घटबढ़	राशि	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
1. आय	4,94,446	6.63	5,71,230	15.53
क) ब्याज आय	4,15,179	6.87	4,91,667	18.42
ख) अन्य आय	79,267	5.38	79,564	0.37
2. व्यय	4,37,337	6.42	5,00,899	14.53
क) व्यय किया गया ब्याज	2,72,083	3.37	2,98,891	9.85
ख) परिचालन व्यय	1,00,028	11.66	1,23,129	23.09
जिसमें से : वेतन बिल	55,248	15.16	71,950	30.23
ग) प्रावधानिकरण और अनुषंगी व्यय	65,226	12.17	78,879	20.93
3. परिचालन लाभ	1,22,335	10.31	1,49,210	21.97
4. वर्ष में निवल लाभ	57,109	8.26	70,331	23.15
5. निवल ब्याज आय (1क-2क)	1,43,096	14.24	1,92,776	34.72
ज्ञापन मद:				
1. निवल ब्याज मार्जिन	2.17		2.92	

स्रोत : संबंधित बैंकों के लाभ और हानि विवरण ।

अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) में वृद्धि (निरपेक्ष संदर्भ में) था। उच्च ब्याज दर वातावरण के कारण निवेश मूल्यहास में मूल्यस से भी बैंकिंग क्षेत्र की प्रावधानीकरण अपेक्षा में वृद्धि हुई। मई 2011 में एनपीए की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा बढ़ने के कारण भविष्य में इसमें और वृद्धि होने की अपेक्षा है (सारणी IV.10)।

4.29 2010-11 में बैंकिंग क्षेत्र में लाभप्रदता बनाये रखने में मदद करने वाला एक कारक यह था कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प को पुनः खोलने से उभरी देयता तक विनियामक व्यवहार बढ़ाना और फरवरी 2011 में उपदान सीमा में वृद्धि करना था। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति दी कि वे इन घटनाओं से उभरी कुल देयताओं का शोधन पांच वर्ष की अवधि में कर सकते हैं जिससे कुल देयताओं का 1/5 भाग ही चालू वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया।⁵

आस्तियों पर प्रतिलाभ में कुछ सुधार हुआ

4.30 परिणामस्वरूप, बैंकिंग क्षेत्र के समेकित निवल लाभ में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई जबकि पिछले कुछ समय से इसमें गिरावट की प्रवृत्ति बनी हुई थी। एसबीबी की आस्तियों पर प्रतिलाभ भी बढ़कर 2010-11 में 1.10 प्रतिशत हो गया जो कि 2009-10 में 1.05 प्रतिशत था जिसका मुख्य कारण उच्च निवल ब्याज मार्जिन था। इक्विटी पर प्रतिलाभ में भी उक्त अवधि में सुधार हुआ। किंतु एसबीआई समूह इस सामान्य प्रवृत्ति का अपवाद था। एसबीआई समूह द्वारा दर्ज आस्तियों पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ में कुछ गिरावट आने का आंशिक कारण टीजर ब्याज दरों पर दिये गये आवास ऋणों की प्रावधानीकरण अपेक्षा था। ऐसे ऋणों के पुनर्मूल्यन पर लाभ बढ़ाने की जोखिम बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2010 में ऐसे ऋणों (मानक आस्तियों के रूप में श्रेणीबद्ध) पर प्रावधानीकरण अपेक्षा बढ़ा दी थी (सारणी IV.11 और चार्ट IV.6)।

कार्यकुशलता

4.31 दूसरी ओर, जहां उच्च निवल ब्याज मार्जिन लाभप्रदता बढ़ाती है वहीं दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था में वित्तीय मध्यस्थता की

सारणी: IV.11 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक समूह/ वर्ष	आस्तियों पर प्रतिफल		इक्विटी पर प्रतिफल	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक	0.97	0.96	17.47	16.90
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*	1.00	1.03	18.30	18.20
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	0.91	0.79	15.92	14.11
2	निजी क्षेत्र के बैंक	1.28	1.43	11.94	13.70
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.95	1.12	12.29	14.10
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	1.38	1.51	11.87	13.62
3	विदेशी बैंक	1.26	1.74	7.34	10.28
	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1.05	1.10	14.31	14.96

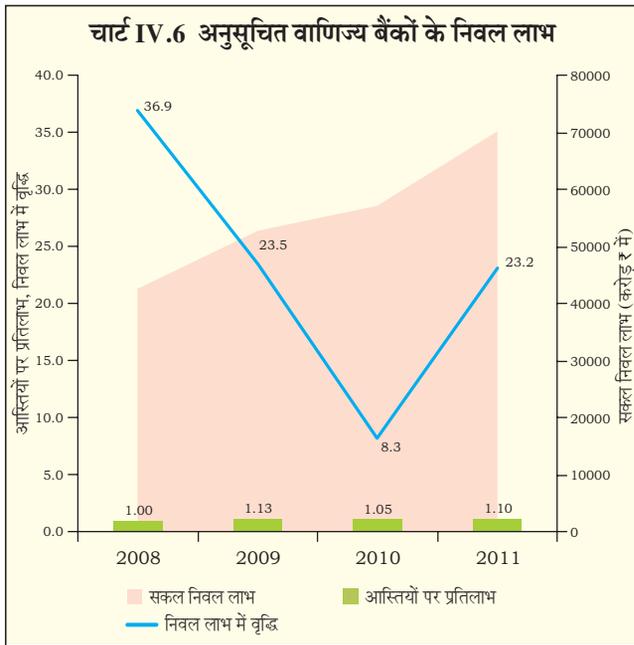
*: राष्ट्रीयकृत बैंकों में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

टिप्पणियाँ: 1) आस्तियों पर प्रतिफल = निवल प्रतिफल / औसत कुल आस्तियाँ।

2) इक्विटी पर प्रतिफल = निवल लाभ / औसत कुल इक्विटी।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

⁵ बैंकों की आरक्षित निधि का प्रारंभिक शेष आगे लाये गये अशोधित व्यय की सीमा तक कम किया जाएगा। घटना के अपवादत्मक स्वरूप को देखते हुए अशोधित व्यय टियर I पूंजी से नहीं घटाया जाएगा।



लागत भी बढ़ती है। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थता की कार्यकुशलता बढ़ाने और लाभप्रदता बनाये रखने के लिए ब्याजेतर आय बढ़ाने के

लिए निवल ब्याज मार्जिन में सुधार लाना आवश्यक है। पिछले एक दशक में बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता का विश्लेषण बाक्स IV.3 में दिया गया है।

निधि लागत में गिरावट आयी

4.32 सामान्य अपेक्षा के विपरीत, एससीबी की निधि लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी जिसका प्राथमिक कारण जमाराशि कि लागत में गिरावट आना था (सारणी IV.12)।

निधि पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ

4.33 विपरीत रूप से, निधि पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। किंतु अग्रिमों पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। इस प्रवृत्ति का एक कारण सकल गैर निष्पादक ऋणों में निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि

सारणी IV.12: निधियों की लागत और निधियों पर प्रतिफल - बैंक समूहवार

(प्रतिशत)

क्रम सं.	बैंक समूह/वर्ष	जमा की लागत	उधार की लागत	निधि की लागत	अग्रिमों पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	निधि पर प्रतिफल	अंतर
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-5)
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक							
	2009-10	5.68	1.50	5.35	9.10	6.65	8.34	2.99
	2010-11	5.12	2.31	4.89	9.09	6.80	8.41	3.52
	1.1 राष्ट्रीयकृत बैंक *							
	2009-10	5.64	1.65	5.37	9.18	6.81	8.46	3.09
	2010-11	5.13	2.36	4.93	9.20	6.85	8.50	3.57
	1.2 भारतीय स्टेट बैंक समूह							
	2009-10	5.75	1.28	5.32	8.93	6.33	8.10	2.78
	2010-11	5.09	2.22	4.80	8.84	6.67	8.21	3.41
2	निजी क्षेत्र के बैंक							
	2009-10	5.36	1.95	4.83	9.89	6.23	8.60	3.77
	2010-11	4.97	2.31	4.56	9.67	6.53	8.56	4.00
	2.1 निजी क्षेत्र के पुराने बैंक							
	2009-10	6.28	1.87	6.13	10.95	6.09	9.22	3.10
	2010-11	5.63	2.24	5.50	10.42	6.20	8.98	3.48
	2.2 निजी क्षेत्र के नए बैंक							
	2009-10	5.01	1.96	4.42	9.56	6.28	8.40	3.99
	2010-11	4.73	2.31	4.27	9.43	6.62	8.44	4.17
3	विदेशी बैंक							
	2009-10	3.10	2.01	2.83	9.99	6.39	8.30	5.47
	2010-11	3.30	2.56	3.11	8.75	7.39	8.11	5.00
	सभी एससीबी							
	2009-10	5.49	1.70	5.10	9.29	6.54	8.39	3.29
	2010-11	5.01	2.34	4.73	9.18	6.79	8.42	3.69

*: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

टिप्पणी:

- 1) जमा की लागत = जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों का औसत।
- 2) उधारों की लागत = उधारों पर प्रदत्त ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के उधारों का औसत।
- 3) निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज + उधारों पर अदा किया गया ब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष की जमाराशियों + उधारों का औसत)।
- 4) अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों का औसत।
- 5) निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / चालू और पूर्व वर्ष के निवेशों का औसत।
- 6) निधियों पर प्रतिलाभ = (अग्रिमों पर अर्जित ब्याज + निवेशों पर अर्जित ब्याज) / (चालू और पूर्व वर्ष के अग्रिमों + निवेशों का औसत)।
- 7) *आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलनपत्रों से गणना की गई।

बॉक्स IV.3: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की निवल ब्याज मार्जिन: कार्यकुशलता बनाम लाभप्रदता

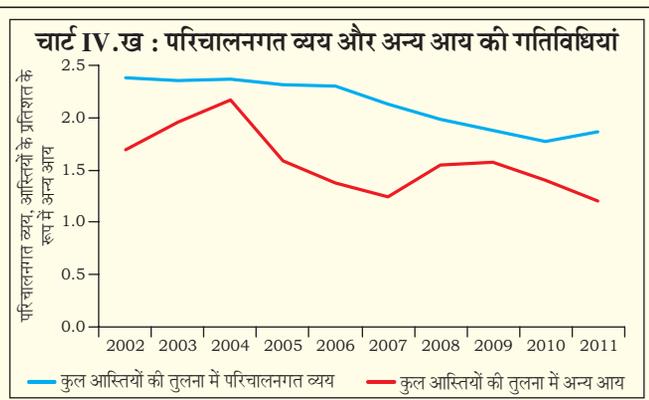
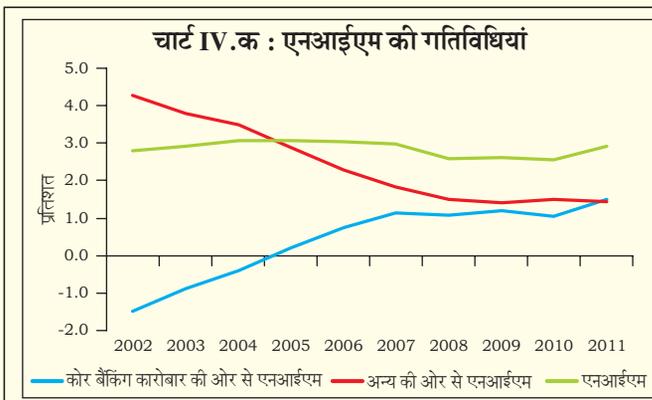
जहां बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए लाभप्रदता बनाये रखना अनिवार्य है, वहीं आर्थिक विकास की दृष्टि से कार्यकुशल वित्तीय मध्यस्थता महत्वपूर्ण है। बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता निर्धारण की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम), परिचालन व्यय और "अन्य आय" महत्वपूर्ण हैं। बैंकिंग क्षेत्र की कार्यकुशलता के आकलन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक संकेतक एनआईएम है। एनआईएम बैंकिंग कारोबार करते समय बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ली गयी मार्जिन दर्शाता है। इस संदर्भ में जहां कार्यकुशलता की दृष्टि से एनआईएम को कम करना जरूरी है, वहीं लाभप्रदता की दृष्टि से इसे बढ़ाना जरूरी है। अतः एक संतुलित कार्य यह होगा कि एनआईएम को कम किया जाए जिससे वित्तीय मध्यस्थता की कार्यकुशलता बढ़ेगी और लाभप्रदता बनाये रखने के लिए अन्य क्षेत्रों से आय बढ़ानी होगी परिचालन व्यय कम करने होंगे (सुब्बाराव, 2010)।

भारत में पिछले एक दशक के दौरान एनआईएम 2.5 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत के दायरे में था। एनआईएम में 2010-11 के दौरान सुधार हुआ जबकि 2004-2010 के दौरान इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी थी। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का एनआईएम विश्व की कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में निरंतर अधिक बना हुआ है। कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम (अर्थात औसत कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण और अग्रिम से ब्याज आय से जमाराशि पर ब्याज व्यय घटाकर आये हुए अंतर के रूप में) और अन्य से एनआईएम (मुख्यतः अन्य सभी ब्याज आय

और ब्याज व्यय के बीच का अंतर) के बीच का विभाजन दर्शाता है कि कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम में पिछले एक दशक के दौरान काफी वृद्धि हुई। इसके विपरीत अन्य से एनआईएम में गिरावट आई जिससे उक्त अवधि के दौरान कुल एनआईएम कमोबेश स्थिर बना रहा। कोर बैंकिंग कारोबार से एनआईएम में वृद्धि दर्शाती है कि वित्तीय मध्यस्थता की लागत में पिछले एक दशक के दौरान वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल एनआईएम कम करने के लिए बैंकिंग कारोबार से एनआईएम को कम करने की आवश्यकता है (चार्ट क)।

पहले दशक अनुसार लाभप्रदता के हित में यह महत्वपूर्ण है कि आस्ति अनुपात के रूप में परिचालन व्यय कम किया जाए और "अन्य आय" बढ़ायी जाए। कुल औसत आस्ति की तुलना में परिचालन व्यय में पिछले एक वर्ष में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी जिसका मुख्य कारण कम लागत की प्रौद्योगिकीय प्रगति था। किंतु कुल औसत आस्ति-"अन्य आय" अनुपात में भी पिछले एक वर्ष में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी (चार्ट ख)। इस प्रकार वित्तीय मध्यस्थता में लाभप्रदता बनाये रखने और कार्यकुशलता सुधारने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में "अन्य आय" बढ़ाना और एनआईएम घटाना महत्वपूर्ण है।

संदर्भ: डी.सुब्बाराव (2010), "फाइव फ्रंटियर इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग", "बैंकॉन 2010", मुंबई में दिसंबर में दिया गया भाषण।

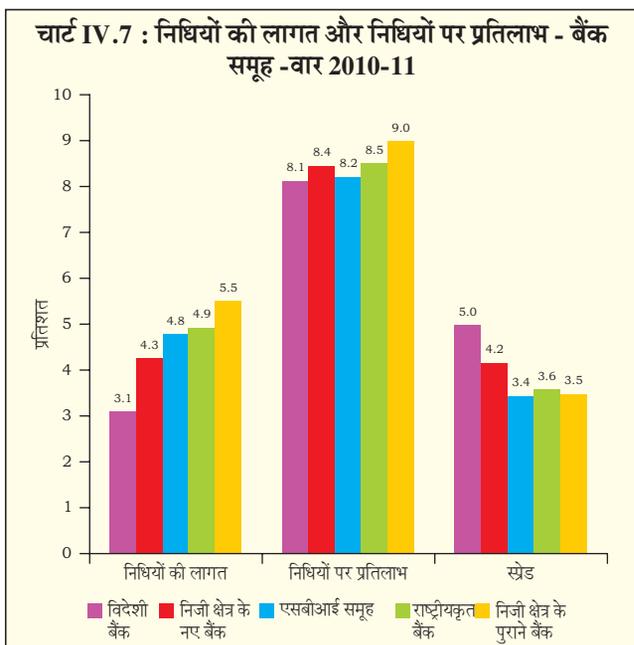


होना हो सकता है। सारांश के रूप में निधि पर प्रतिलाभ में वृद्धि और निधि की लागत में गिरावट से अंतर में वृद्धि हुई। बैंक समूह स्तर पर जहां निधि पर प्रतिलाभ सामान्यतः तुलनीय है वहीं निधि की लागत में काफी अंतर था। विदेशी बैंकों द्वारा दर्ज निधि की न्यूनतम लागत के कारण 2010-11 में वे उच्चतम अंतर दर्ज कर सके। हाल के वर्षों में कम व्यय वाली सीएसएसए जमाराशियों के उच्च हिस्से के कारण विदेशी बैंक जमाराशि की कम लागत और अंततः निधि की कम लागत दर्ज कर सके (चार्ट IV.1 देखें) (चार्ट IV.7)।

4. सुदृढ़ता संकेतक

सुदृढ़ता संकेतक अच्छी स्थिति की ओर संकेत करते हैं

4.34 बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता भारत जैसे बैंकों के प्रभुत्व वाले देश में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। तदनुसार बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता के विभिन्न पहलुओं, नामतः पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, लीवरेज, ऋण में तेजी और चलनिधि का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है।



पूंजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर)

बासेल I और II के तहत सीआरएआर निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त अधिक रहा

4.35 आरआरबी और एलएबी छोड़कर सभी एससीबी बासेल II संरचना में अंतरित हो जाने के बावजूद बॉकस्टॉप उपाय के रूप में बासेल I भी समांतर रूप से चल रहा है। बासेल I के तहत सभी बैंकों का सीआरएआर 2010-11 में 9 प्रतिशत के निर्धारित मानदंडों से पर्याप्त ऊपर रहा (सारणी IV.13)।

सारणी IV.13: बासेल I और II के अंतर्गत जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात - बैंक समूह वार

(मार्च के अंत में)

बैंक समूह	(प्रतिशत)			
	बासेल I		बासेल II	
	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5
सरकारी क्षेत्र के बैंक	12.1	11.8	13.3	13.1
राष्ट्रीयकृत बैंक*	12.1	12.2	13.2	13.5
भारतीय स्टेट बैंक समूह	12.1	11.0	13.5	12.3
निजी क्षेत्र के बैंक	16.7	15.1	17.4	16.5
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	13.8	13.3	14.9	14.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	17.3	15.5	18.0	16.9
विदेशी बैंक	18.1	17.7	17.3	17.0
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	13.6	13.0	14.5	14.2

* : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।

4.36 किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सीआरएआर कम हो गया जिसका मुख्य कारण टियर II सीआरएआर अनुपात में कमी आना था। 2010-11 में बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों ने सर्वाधिक सीआरएआर दर्ज किया जिनके बाद निजी क्षेत्र के बैंकों और पीसीबी का स्थान था। 2010-11 में बासेल II के तहत भी एससीबी का सीआरएआर न्यूनतम अपेक्षा से अधिक था। इसका अर्थ यह है अल्पावधि से मध्यावधि में एससीबी को ऋण देने में पूंजी की समस्या नहीं थी (सारणी IV.14)।

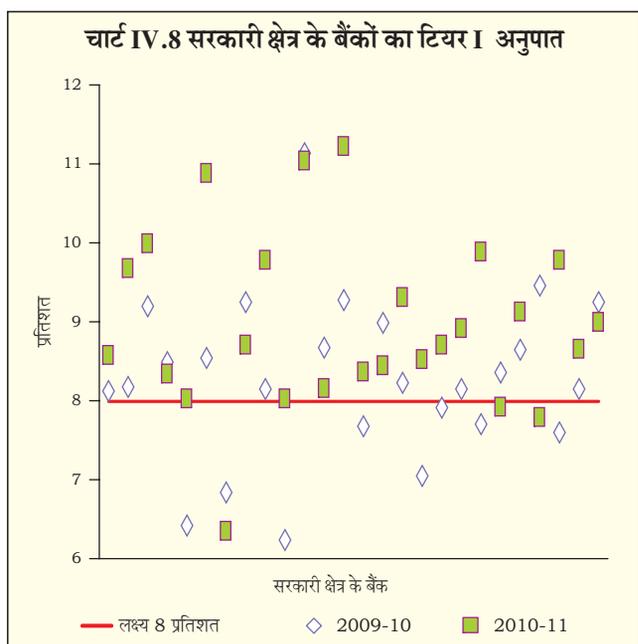
4.37 बासेल II लागू करते समय रिजर्व बैंक ने बासेल II के तहत न्यूनतम पूंजी के प्रतिशत को बासेल I के तहत न्यूनतम पूंजी के प्रतिशत को विवेकसम्मत आधार के रूप में निर्धारित किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत बासेल II के तहत न्यूनतम बासेल I के तहत की न्यूनतम पूंजी के पहले वर्ष 100 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 90 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 80 प्रतिशत होनी चाहिए ताकि बासेल II संरचना के अनुपालन की गुणवत्ता से उभरने वाली किसी भी जोखिम को सीमित किया जा सके। दिसंबर 2010 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 मार्च 2013 तक समानांतर व्यवस्था जारी रखें और विवेकसम्मत आधार 80 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय रूप से 2009-10 में, बासेल II लागू करने का तीसरा वर्ष, (अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति वाले सभी विदेशी बैंक और देशी बैंक) यह अनुपात 99.1 प्रतिशत था जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर था। 2010-11 में यह और बढ़कर 99.4 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में सरकार की योजना है कि

सारणी IV.14: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घटकवार पूंजी पर्याप्तता

(मार्च के अंत में)

मद	(राशि करोड़ रुपये में)			
	बासेल I		बासेल II	
	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5
क. पूंजी निधियां (i + ii)	5,72,582	6,74,662	5,67,381	6,70,389
i) टियर I पूंजी	3,97,666	4,76,615	3,95,100	4,74,581
ii) टियर II पूंजी	1,74,916	1,98,047	1,72,281	1,95,808
ख. जोखिम भारित आस्तियां	42,16,565	51,81,583	39,01,395	47,24,933
ग. सीआरएआर (ख के % के रूप में क)	13.6	13.0	14.5	14.2
जिसमें से: टियर I	9.4	9.2	10.1	10.0
टियर II	4.1	3.8	4.4	4.1

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों पर आधारित।



टियर I अनुपात बढ़ाकर 8 प्रतिशत से अधिक किया जाए ताकि इन बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। 2010-11 में मात्र तीन बैंकों का टियर I अनुपात 8 प्रतिशत से कम था (चार्ट IV.8)।

भारतीय बैंक प्रस्तावित बासेल II संरचना से आसानी से तालमेल बिठा सकते हैं

4.38 प्रस्तावित बासेल II संरचना, जो कि 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू होगी, के साथ भी भारतीय बैंक मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में नये पूंजी नियमों से तालमेल करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करेंगे। बैंकों द्वारा उनकी ऑफसाइट विवरणियों में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर किया गया शीघ्र अनुमान दर्शाता है कि बासेल III के तहत भारतीय बैंकों का सीआरएआर 11.7 प्रतिशत होगा (30 जून 2010 को) जबकि प्रस्तावित बासेल III के तहत अपेक्षित सीआरएआर 10.5 प्रतिशत है।

अनर्जक आस्तियां

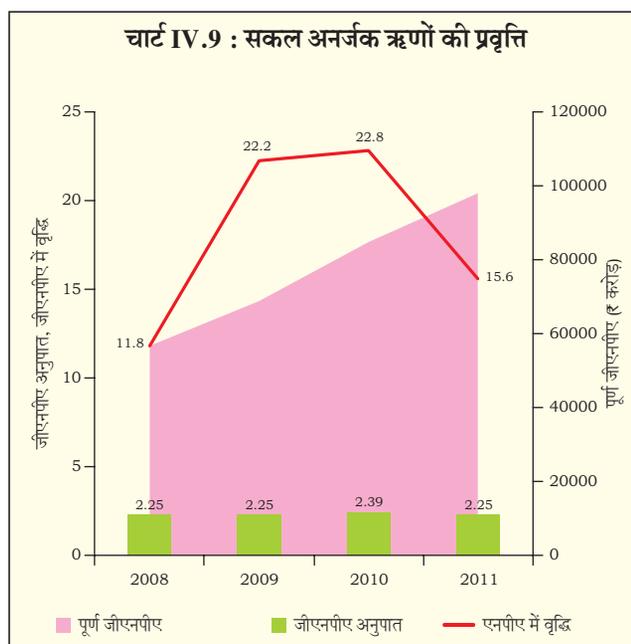
जीएनपीए-सकल अग्रिम अनुपात में सुधार हुआ

4.39 बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ। सकल एनपीए-सकल अग्रिम अनुपात 2010-11 में कम होकर 2.25 प्रतिशत रह गया जो कि पिछले वर्ष

2.39 प्रतिशत था। किंतु जीएनपीए पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में निरपेक्ष संदर्भ में बढ़ा हालांकि इसकी गति कम थी। आस्ति गुणवत्ता में सुधार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में स्पष्ट था। किंतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आयी। इसका मुख्य कारण एसबीआई समूह की आस्ति गुणवत्ता में गिरावट आना था। बैंक समूहों के बीच 2010-11 में एसबीआई समूह ने सर्वाधिक जीएनपीए अनुपात दर्ज किया जिसके बाद विदेशी बैंकों का स्थान था। किंतु विदेशी बैंकों ने सकल गैर निष्पादक ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट दर्ज की (सारणी IV.15 और चार्ट IV.9)।

बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले वर्ष की बकाया जीएनपीए का दस प्रतिशत बढ़े खाते में डाला

4.40 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र ने बकाया सकल गैर निष्पादक ऋणों (मार्च 2010 के अंत में) का लगभग दस प्रतिशत बढ़े खाते में डाला जिससे गैर निष्पादक ऋणों की वृद्धि सीमित रखने में मदद मिली। बढ़े खाते में डालने की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम थी किंतु 2008 और 2009 की तुलना में यह अनुपात अधिक था। इसने यह दर्शाया कि पिछले दो वर्षों के दौरान एसपीए को बढ़े खाते डालना बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता को



सारणी IV. 15: अनर्जक आस्तियों का रुझान - बैंक समूहवार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सकल एनपीए								
2009-10 के लिए अंतिम शेष	59,926	36,394	23,532	17,639	3,622	14,017	7,133	84,698
2010-11 के लिए प्रारंभिक शेष	59,433	36,394	23,039	17,340	3,323	14,017	7,133	83,906
2010-11 के दौरान जोड़	58,226	35,514	22,712	8,657	2,412	6,245	3,527	70,410
2010-11 के लिए वसूली	37,160	25,974	11,186	5,417	1,804	3,613	5,514	48,091
2010-11 के लिए बढ़ी खाता डाले गए	5,884	1,712	4,172	2,338	231	2,107	77	8,299
2010-11 के लिए अंतिम शेष	74,614	44,222	30,392	18,240	3,699	14,541	5,068	97,922
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए								
2009-10	2.19	1.95	2.70	2.74	2.32	2.87	4.26	2.39
2010-11	2.23	1.89	3.00	2.25	1.97	2.33	2.54	2.25
निवल एनपीए								
2009-10 के लिए अंतिम शेष	29,375	16,813	12,562	6,371	1,137	5,234	2,977	38,723
2010-11 के लिए अंतिम शेष	36,071	21,281	14,790	4,430	982	3,448	1,312	41,813
निवल अग्रिम के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए								
2009-10	1.09	0.91	1.46	1.01	0.78	1.08	1.82	1.11
2010-11	1.09	0.92	1.49	0.56	0.53	0.56	0.67	0.97

* : आइडीबीआई बैंक लि. सहित।

टिप्पणी: स्टेट बैंक समूह के 2009-10 में सकल अनर्जक आस्तियों के अंतिम शेष और 2010-11 की सकल अनर्जक अस्तियों के प्रारंभिक शेष बीच अंतर इसलिए है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया है। पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अंतर प्रमुख दो कारणों से है : पहला, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय और दूसरा सिटी यूनिन बैंक द्वारा 2009-10 की सकल अनर्जक आस्तियों के अंतिम शेष में 5.27 करोड़ रुपये के आरक्षित ब्याज को शामिल करने और 2010-11 में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रारंभिक शेष में इसे शामिल न करने के कारण है।

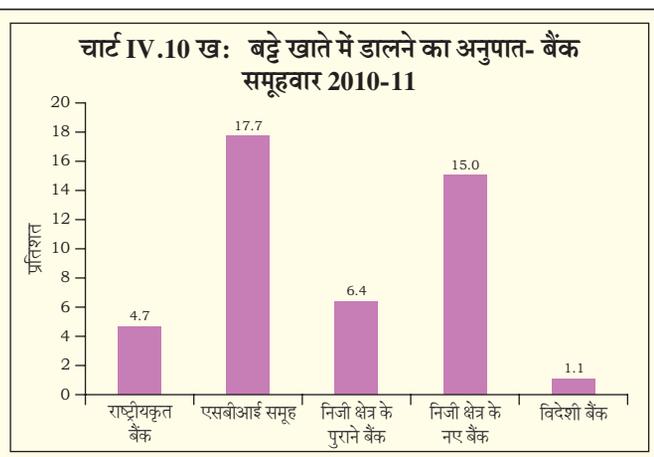
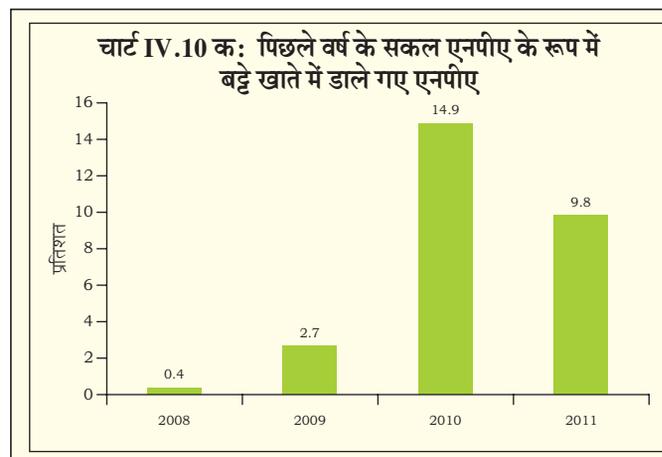
स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

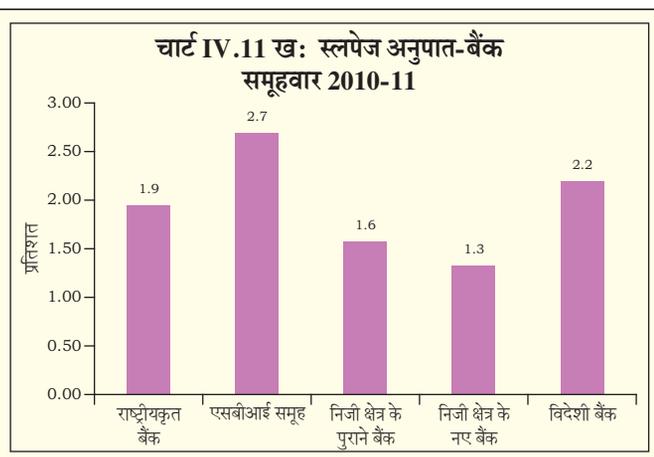
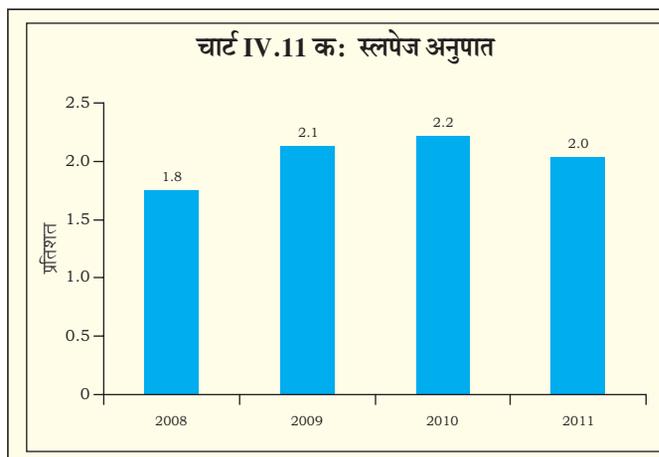
सहनीय स्तर पर बनाये रखने का महत्वपूर्ण कारक था। बढ़े खाते डाली गयी बकाया जीएनपीए का कुल बकाया जीएनपीए में प्रतिशत (मार्च 2010 के अंत में) विशेष रूप से एसबीआई समूह और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामले में अधिक था (चार्ट IV.10क और IV.10ख)।

4.41 पिछले वर्ष की बकाया मानक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान सकल एनपीए के जोड़ के रूप में गणना किया गया स्लिपेज अनुपात आस्ति गुणवत्ता का एक और महत्वपूर्ण संकेतक है। 2008 से लगातार बढ़े हुए स्लिपेज अनुपात में 2010-11 में सुधार

हुआ जो मुख्यतः वृद्धि में सुधार दर्शाता है। बैंक समूह स्तर पर निजी क्षेत्र के नये बैंकों ने 2010-11 में न्यूनतम स्लिपेज अनुपात दर्ज किया (चार्ट IV.11क और IV.11ख)।

4.42 जीएनपीए में सुधार बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण घटक है। 2010-11 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र ने विभिन्न वसूली माध्यमों से बकाया जीएनपीए (मार्च 2010 के अंत में) का 57 प्रतिशत भाग वसूल किया। विदेशी बैंकों ने सर्वाधिक वसूली अनुपात दर्ज किया जिनके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान था (चार्ट IV.12क और IV.12ख)।



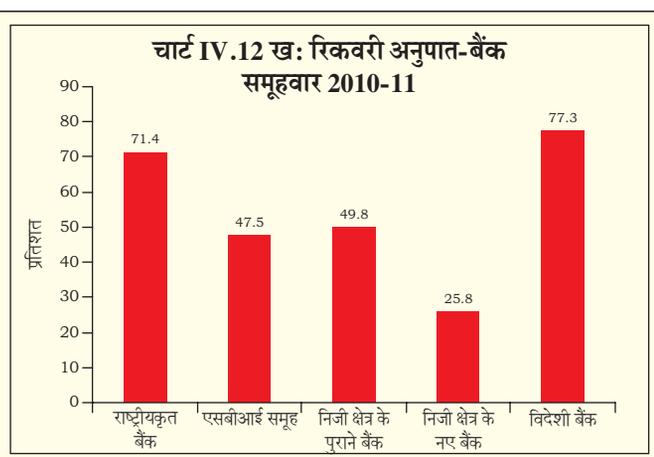
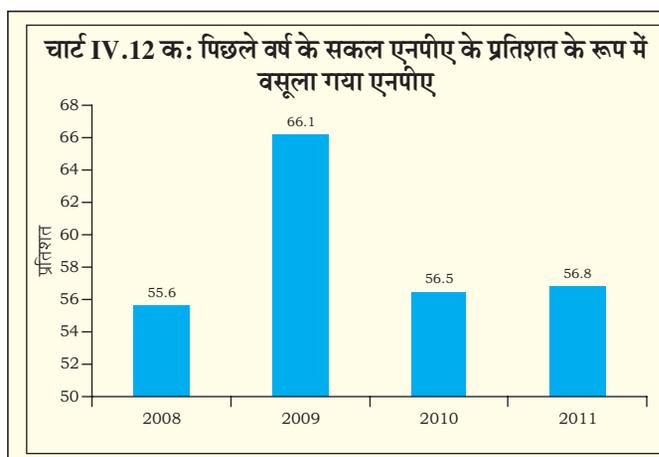


4.43 सरफाइसी (SARFAESI) अधिनियम, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) और लोक अदालत ऐसे विविध माध्यम हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र में एसपीए की वसूली के लिए उपलब्ध हैं। 2010-11 में सरफाइसी अधिनियम के तहत संदर्भित मामलों में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अलावा संबंधित कुल राशि में से एक तिहाई से अधिक राशि की वसूली 2010-11 में हुई। 2010-11 में डीआरटी को संदर्भित मामलों में 114 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई। लोक अदालत में तेजी से वसूली होने के कारण वसूली के अन्य माध्यमों की तुलना में लोक अदालत में अधिक मामले आते हैं। किंतु 2010-11 में लोक अदालत को भेजे गये मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी। इसके अलावा 2010-11 में कुल राशि से वसूली गयी राशि का प्रतिशत डीआरटी की तुलना में लोक अदालत में कम था हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई थी (सारणी IV.16)।

4.44 रिजर्व बैंक ने जून 2011 के अंत में चौदह प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निमाण कंपनियों (एससी/आरसी) को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किये। इनमें से रिजर्व बैंक में पंजीकृत तेरह एससी/आरसी ने कार्य शुरू किया। 2010-11 में एससी/आरसी द्वारा अधिग्रहित आस्तियों का बही मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत बढ़ा। 2010-11 में एससी/आरसी द्वारा जारी कुल प्रतिभूति रसीदों में से 71 प्रतिशत का अंशदान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किया गया (सारणी IV.17)।

मानक आस्तियों के पुनर्निधारण से सकल गैर निष्पादक ऋणों की सीमित रखने में सहायता मिली

4.45 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अग्रिमों का पुनर्निधारण करने से बैंकिंग क्षेत्र का जीएनपीए अनुपात कम होने में सहायता मिली। अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव बाक्स IV.4 में दर्शाया गया है।



सारणी IV.16: विभिन्न चैनलों के माध्यम से वसूल किया गया अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का एनपीए

(राशि करोड़ रुपये में)

वसूली चैनल	2009-10				2010-11			
	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	वसूली की राशि*	स्तंभ (3) के % रूप में स्तंभ (4)	भेजे गए मामलों की संख्या	शामिल राशि	*वसूली की गई राशि	स्तंभ (7) के रूप में स्तंभ (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i) लोक अदालत	778,833	7,235	112	1.55	616,018	5,254	151	2.87
ii) डीआरटी	6,019	9,797	3,133	32.00	12,872	14,092	3,930	27.89
iii) सरफाइसी अधिनियम	78,366#	14,249	4,269	30.00	118,642#	30,604	11,561	37.78

*: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि से तात्पर्य है, जो दिए गए वर्ष के दौरान और पूर्व वर्षों के दौरान भेजे गए मामलों के संबंध में हो सकता है।
#: जारी नोटिसों की संख्या
डीआरटी - ऋण वसूली न्यायाधिकरण

4.46 देशी बैंकों के सकल एनपीए में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया। जहां पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के सकल एनपीए- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम का अनुपात सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बढ़ गया, वहीं इसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों में यह कम हो गया (सारणी IV.18 और चार्ट IV.13)।

कृषि क्षेत्र ने देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए में 44 प्रतिशत का योगदान दिया

4.47 2010-11 में कृषि क्षेत्र ने देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए में 44 प्रतिशत का योगदान दिया। पिछले चार वर्षों (2006-07 से 2009-10) के दौरान कृषि क्षेत्र को ऋण में हुई उच्च वृद्धि से 2010-11 में कृषि एनपीए में वृद्धि हुई जिसका कारण ऋण गुणवत्ता में कमी

आना था। देशी बैंकों के कृषि अग्रिम के प्रति कृषि एनपीए, जो कि कृषि ऋण माफी और राहत योजना, 2008 लागू करने के कारण 2008-09 में कम हो गया था, में उसके बाद वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। 2010-11 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कृषि एनपीए अनुपात में उच्च वृद्धि दर्ज की (चार्ट IV.13 और IV.14 तथा परिशिष्ट सारणी IV.2 (क), IV.2 (ख) और IV.2 (ग)।

4.48 इसी प्रकार, दुर्बल घटकों के अग्रिम के प्रति दुर्बल घटकों के एनपीए में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पीआरबी में वृद्धि देखी गयी। एसएमई क्षेत्र को देय संपार्श्विकमुक्त ऋण की सीमा मई 2010 में 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के बावजूद एसएमई क्षेत्र का एनपीए अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो

सारणी IV.17: एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूतिकृत वित्तीय आस्तियों के विवरण

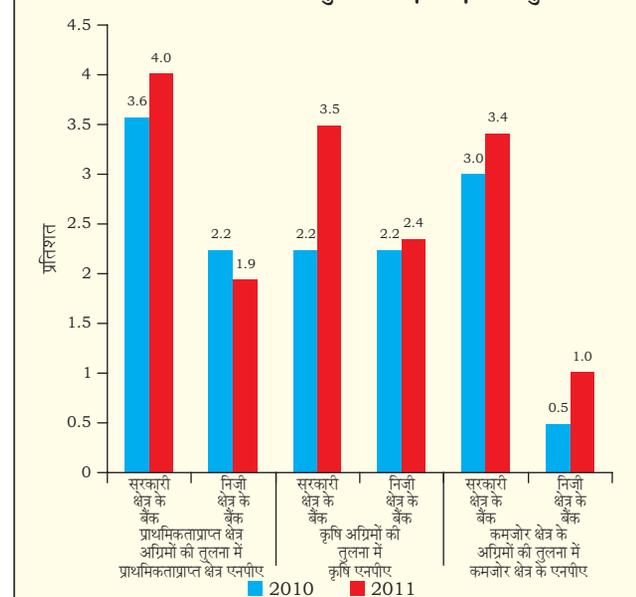
(राशि करोड़ रुपये में)

मद	जून 2010 के अंत में	जून 2011 के अंत में
1	2	3
1 अर्जित आस्तियों का बही मूल्य	62,217	74,088
2 एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों के द्वारा अभिदत्त प्रतिभूति रसीदें	14,051	15,859
(क) बैंक	10,314	11,233
(ख) एससी /आरसी	2,940	3,384
(ग) एफआईआई	-	39
(घ) अन्य (अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता)	797	1,203
4 पूरी तरह से शोधित प्रतिभूति रसीदों की राशि	4,556	6,704

-: शून्य / नगण्य।

स्रोत : प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) द्वारा प्रस्तुत तिमाही विवरण।

चार्ट IV.13: अग्रिमों की तुलना में एनपीए का अनुपात



बाक्स IV.4: अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव

2007 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद में अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र में गिरावट, यदि कोई हो, को नियंत्रण में रखने के लिए रिजर्व बैंक ने सक्रिय रूप से अनेक उपाय किये। इन उपायों में एक यह था कि बैंकों को एक बारगी उपाय के रूप में उनके अग्रिमों को पुनर्निधारित करने की अनुमति दी गयी। तदनुसार रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा अग्रिमों को पुनर्निधारित करने पर अगस्त 2008 में दिशानिर्देश जारी किये जिनके द्वारा बैंकों को अनुमति दी गयी कि वे मानक, अवमानक और संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत सक्षम संस्थाओं के खाते पुनर्निधारित कर सकते हैं। अगस्त 2008 में यह निर्धारित करने के बावजूद कि मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत खातों को पुनर्निधारित पर तुरंत अवमानक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाए, 1 सितंबर 2008 को मानक रहे सभी खातों को जनवरी 2009 में असाधारण/विशेष विनियामक ट्रीटमेंट दी गयी। असाधारण/विशेष विनियामक ट्रीटमेंट मानक खातों को पुनर्निधारण के बाद मानक मानने की अनुमति देती है बशर्ते कुछ शर्तें पूरी की जाएं। मानक खातों को दी गयी विशेष विनियामक ट्रीटमेंट से बैंकिंग क्षेत्र को सकल गैर-निष्पादक अग्रिमों की वृद्धि सीमित रखने में मदद मिली। किंतु इस बात की चिंता निरंतर बनी रही कि वैश्विक वित्तीय संकट के कारण ये उधारकर्ता अस्थायी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना कर रहे थे जिससे पुनर्निधारित मानक खाते कुछ समय बाद पुनः गैर-निष्पादक आस्तियों

की श्रेणी में न आ जाएं। इस प्रकार अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव पुनर्निधारित मानक खाते पुनः गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में आ जाने में दिखेगा।

बैंक समूहों द्वारा सितंबर 2008 से अग्रिमों के पुनर्निधारण पर आंकड़ों से पता चलता है कि मानक अग्रिमों के पुनर्निधारण में सबसे आगे पीएसबी थे। प्रणाली स्तर पर सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारित मानक अग्रिम मार्च 2009 के अंत के 2.16 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 2.66 प्रतिशत हो गये। मानक अग्रिमों के पुनर्निधारण का बैंकिंग क्षेत्र की आस्ति गुणवत्ता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए पुनः गैर-निष्पादक आस्तियों की श्रेणी में न आ जाने वाले पुनर्निधारित मानक अग्रिमों के प्रतिशत के लिए विभिन्न मूल्य हिसाब में लेने से विभिन्न स्थितियां सामने आयी हैं। ये परिणाम नीचे सारणी में दिये गये हैं।

इस चरम धारणा के तहत कि यदि पुनर्निधारित नहीं किया गया होता तो पूरे पुनर्निधारित मानक अग्रिम एनपीए बन गये होते, सकल एनपीए अनुपात सूचित 2.35 प्रतिशत के जो एनपीए अनुपात के बजाय मार्च 2011 के अंत में 5.01 प्रतिशत जितना अधिक रहा होता (सारणी)।

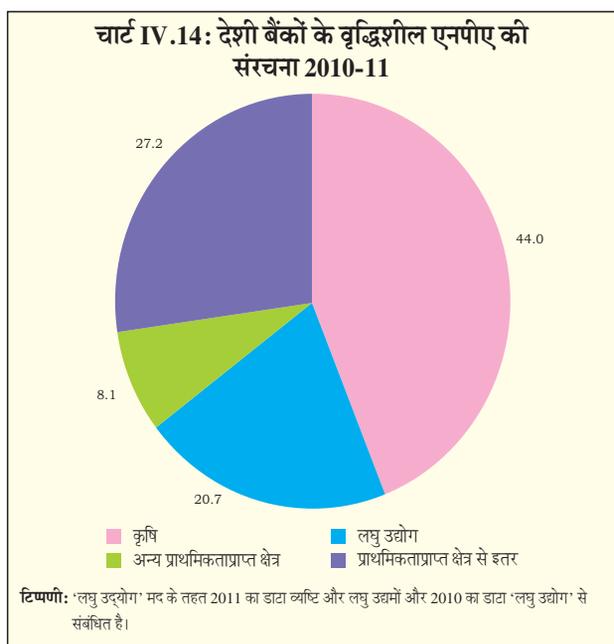
सारणी : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर पुनर्संरचना के प्रभाव

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			वर्ष-दर -वर्ष वृद्धि		
	मार्च 2009	मार्च 2010	मार्च 2011	2008 की तुलना में 2009	2009 की तुलना में 2010	2010 की तुलना में 2011
1	2	3	4	5	6	7
कुल सकल अग्रिम	27,93,572	32,71,896	40,12,079	19.79	17.12	22.62
मानक अग्रिम	27,25,350	31,90,080	39,17,991	19.73	17.05	22.82
जिसमें से पुनर्संरचित	60,379	97,834	1,06,859	192.98	60.19	10.53
कुल सकल अनर्जक आस्तियां	68,222	81,816	94,088	22.17	19.93	14.84
कुल सकल अग्रिमों की तुलना में कुल सकल अनर्जक आस्तियां	2.44	2.50	2.35			
सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में पुनर्संरचित मानक अग्रिम						
सकल अग्रिम का %	2.16	2.99	2.66			
परिदृश्य-I- अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 15 प्रतिशत						
परिदृश्य-I अनर्जक आस्तियां	77,279	96,491	1,10,116	31.13	24.64	14.19
परिदृश्य-I अनर्जक आस्ति अनुपात	2.77	2.94	2.74			
परिदृश्य-II -अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 25 प्रतिशत						
परिदृश्य-II अनर्जक आस्तियां	83,317	1,05,996	1,20,684	36.59	27.22	13.86
परिदृश्य-II अनर्जक आस्ति अनुपात	2.98	3.24	3.01			
परिदृश्य-III -अनर्जक आस्तियों को परिवर्तित करने वाले पुनर्संरचित मानक अग्रिम का 100						
परिदृश्य-III अनर्जक आस्तियां	1,28,601	1,78,537	2,00,860	68.21	38.83	12.50
परिदृश्य-III अनर्जक आस्ति अनुपात	4.60	5.46	5.01			

गया। सारांश के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के एनपीए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सामान्यतः अधिक थे (सारणी IV.18, चार्ट IV.13 तथा परिशिष्ट सारणी IV.3 (क) और IV.3 (ख)।



जीएनपीए के लिए प्रावधानीकरण में उच्च वृद्धि हुई

4.49 जीएनपीए वृद्धि के समरूप, एनपीए प्रावधानीकरण में भी पिछले वर्ष की 22 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में

अधिक अर्थात् 25 प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रावधानीकरण में वृद्धि दर्शाते हुए बकाया प्रावधानीकरण-सकल एनपीए अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ (सारणी IV.19)।

निवल एनपीए में कम वृद्धि हुई

4.50 निवल एनपीए में पिछले वर्ष की 23 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 2010-11 में कम अर्थात् 8 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप निवल एनपीए-निवल अग्रिम अनुपात 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कम हो गया।

मानक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में सुधार हुआ

4.51 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सकल एनपीए अनुपात कम होने के अनुरूप, उक्त अवधि में मानक आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में भी सुधार हुआ। किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में संदिग्ध आस्ति-सकल अग्रिम अनुपात में वृद्धि हुई।

सारणी IV.18: देशी बैंकों का क्षेत्रवार एनपीए*

(करोड़ रुपये)

वर्ष	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से						गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		जिसमें से		कुल एनपीए	
	राशि	प्रतिशत	कृषि		लघु उद्योग#		अन्य		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
सरकारी क्षेत्र के बैंक														
2010	30,848	53.8	8,330	14.5	11,537	20.1	10,981	19.2	26,453	46.2	524	0.9	57,301	100.0
2011	41,245	58.1	14,487	20.4	14,340	20.2	12,417	17.5	29,802	41.9	278	0.4	71,047	100.0
राष्ट्रीयकृत बैंक **														
2010	19,908	56.1	5,741	16.2	8,668	24.4	5,499	15.5	15,562	43.9	280	0.8	35,470	100.0
2011	25,678	59.8	9,220	21.5	10,424	24.3	6,034	14.1	17,229	40.2	273	0.6	42,907	100.0
भारतीय स्टेट बैंक समूह														
2010	10,940	50.1	2,589	11.9	2,869	13.1	5,482	25.1	10,890	49.9	244	1.1	21,830	100.0
2011	15,567	55.3	5,268	18.7	3,916	13.9	6,383	22.7	12,573	44.7	6	0.02	28,140	100.0
निजी क्षेत्र के बैंक														
2010	4,792	27.6	2,023	11.6	1,139	6.6	1,630	9.4	12,592	72.4	-	-	17,384	100.0
2011	4,823	26.8	2,172	12.1	1,298	7.2	1,353	7.5	13,147	73.2	153	0.9	17,971	100.0
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक														
2010	1,613	44.7	269	7.4	475	13.2	869	24.1	1,999	55.3	-	-	3,612	100.0
2011	1,599	43.3	417	11.3	551	14.9	631	17.1	2,095	56.7	153	4.1	3,694	100.0
निजी क्षेत्र के नए बैंक														
2010	3,179	23.1	1,754	12.7	664	4.8	760	5.5	10,594	76.9	-	-	13,773	100.0
2011	3,224	22.6	1,755	12.3	746	5.2	722	5.1	11,053	77.4	-	-	14,277	100.0
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक														
2010	35,640	47.7	10,353	13.9	12,676	17.0	12,611	16.9	39,045	52.3	524	0.7	74,685	100.0
2011	46,068	51.8	16,660	18.7	15,638	17.6	13,370	15.5	42,950	48.2	431	0.5	89,017	100.0

#: 2011 के आंकड़ों का संबंध 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों' से है इसलिए इनकी तुलना 2010 के आंकड़ों से नहीं की जा सकती।

* : विदेश बैंक शामिल नहीं।

- : शून्य / नगण्य

प्रतिशत - कुल एनपीए का प्रतिशत।

** आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑफ साइट विवरणियों (देशी) पर आधारित।

सारणी IV.19: अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों की प्रवृत्तियां - बैंक समूह-वार

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	भारतीय स्टेट बैंक समूह	निजी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनपीए के लिए प्रावधान								
मार्च 2010 अंत में	28,187	17,818	10,369	10,848	2,066	8,782	4,178	43,213
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	29,133	15,720	13,413	6,854	1,149	5,705	2,755	38,742
घटाए: बढ़ा खाते डाले गए, वर्ष के दौरान अतिरक का प्रतिलेखन	20,641	12,348	8,293	4,150	749	3,401	3,126	27,917
मार्च 2011 अंत में	36,680	21,190	15,490	13,552	2,466	11,086	3,808	54,040
ज्ञापन:								
सकल एनपीए	74,614	44,222	30,392	18,240	3,699	14,541	5,068	97,922
सकल एनपीए (प्रतिशत) की तुलना में बकाया प्रावधानों का अनुपात								
मार्च 2010 के अंत में	47.4	48.9	45.0	62.4	61.3	62.7	58.7	51.5
मार्च 2011 के अंत में	49.2	47.9	51.0	74.3	66.7	76.2	75.1	55.2

* : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

स्रोत: संबंधित बैंकों के तुलन पत्र।

सकल अग्रियों के अनुपात के रूप में अवमानक आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी जिसका कारण एक ओर वृद्धि संभावना और दूसरी ओर ऋण गुणवत्ता में सुधार हो सकता है (सारणी IV.20)।

लीवरेज अनुपात

लीवरेज अनुपात अपरिवर्तित बना रहा

4.52 2010-11 के दौरान तुलनपत्र में उच्च वृद्धि के बावजूद लीवरेज अनुपात पिछले वर्ष जैसा ही 6.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित

रहा जिसका कारण बैंकिंग क्षेत्र के पूंजी आधार में हुई तदनु रूप वृद्धि था।

ऋण तेजी

उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद ऋण में तेजी का कोई सबूत नहीं है

4.53 बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में ऋण में अस्थायी वृद्धि की निगरानी महत्वपूर्ण है। बाक्स IV.5 में दिया गया विश्लेषण दर्शाता है कि 2010-11 की मजबूत ऋण वृद्धि से समग्र

सारणी IV.20: ऋण आस्तियों का वर्गीकरण - बैंक समूहवार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	बैंक समूह	वर्ष	मानक आस्तियां		अवमानक आस्तियां		संदिग्ध आस्तियां		हानि आस्तियां	
			राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*	राशि	प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2010	26,73,534	97.81	28,791	1.05	25,383	0.93	5,750	0.21
		2011	32,72,914	97.77	34,973	1.04	33,180	0.99	6,463	0.19
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक**	2010	18,27,061	98.05	18,520	0.99	15,034	0.81	2,841	0.15
		2011	22,91,111	98.11	21,758	0.93	19,282	0.83	3,183	0.14
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	2010	8,46,473	97.30	10,271	1.18	10,349	1.19	2,909	0.33
		2011	9,81,803	97.00	13,215	1.31	13,898	1.37	3,280	0.32
2	निजी क्षेत्र के बैंक	2010	6,26,472	97.27	8,842	1.37	6,590	1.02	2,166	0.34
		2011	7,93,590	97.76	4,530	0.56	10,795	1.33	2,864	0.35
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2010	1,52,745	97.69	1,395	0.89	1,637	1.05	580	0.37
		2011	1,83,601	98.03	1,253	0.67	1,815	0.97	626	0.33
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	2010	4,73,727	97.13	7,447	1.53	4,953	1.02	1,586	0.33
		2011	6,09,989	97.68	3,277	0.52	8,980	1.44	2,238	0.36
3	विदेशी बैंक	2010	1,60,311	95.74	4,929	2.94	1,440	0.86	758	0.45
		2011	1,94,256	97.46	1,865	0.94	2,110	1.06	1,087	0.55
	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2010	34,60,317	97.61	42,562	1.20	33,413	0.94	8,674	0.24
		2011	42,60,760	97.75	41,368	0.95	46,085	1.06	10,415	0.24

* : सकल अग्रियों के प्रतिशत के रूप में।

** : आईडीबीआई बैंक लि. शामिल है।

टिप्पणी: पूर्णांकन के कारण घटक मदों के जोड़ में अंतर हो सकता है।

स्रोत: संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत डीएसबी विवरणी (बीएसए)।

और उप-क्षेत्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में तेजी की कोई घटना नहीं हुई (बाक्स IV.5)।

चलनिधि

स्वायत्त कारणों से बैंकों ने कड़ी चलनिधि की स्थिति में कार्य किया

4.54 2010-11 के दौरान बैंक कड़ी चलनिधि की स्थिति में कार्य कर रहे थे। रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा

(एलएएफ) विंडो, जो कि लगभग 18 माह तक अधिशेष की स्थिति में थी, मई 2010 के अंत में घाटे की स्थिति में आ गयी और 2010-11 की शेष अवधि में घाटे की स्थिति में ही रही। रिज़र्व बैंक में केंद्र का अधिशेष और संचलन में मुद्रा जैसे स्वायत्त कारक 2010-11 में चलनिधि की स्थिति के मुख्य प्रेरक थे। चलनिधि की स्थिति 2011-12 के दौरान अब तक घाटे की स्थिति में बनी रही। चलनिधि की कड़ी स्थिति और रिज़र्व बैंक द्वारा नितीगत दरों में लगातार वृद्धि दर्शाते हुए मांग दर लंबी अवधि तक अनौपचारिक

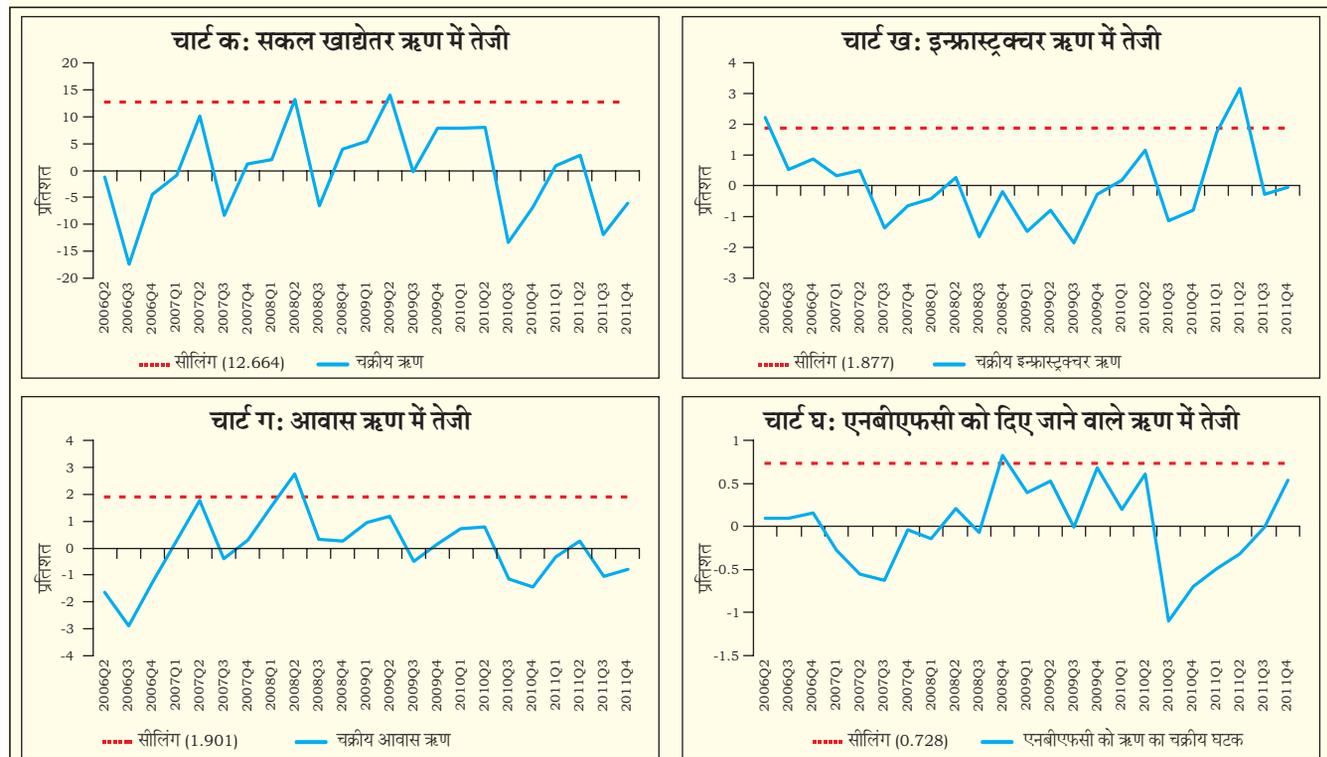
बाक्स IV.5: मजबूत ऋण वृद्धि और ऋण में तेजी-भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2010-11 के दौरान देखी गयी मजबूत ऋण वृद्धि अर्थव्यवस्था में ऋण-तेजी विकसित होने संबंधी चिंताएं उभारीं। ऋण गुणवत्ता में गिरावट के कारण ऋण तेजी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। ऋण तेजी के विश्लेषण के लिए यहां कोरीसेली एट.एल.(2006) द्वारा विकसित पद्धति प्रयोग में लायी गयी। इस पद्धति के अनुसार ऋण तेजी या बुलबुला उस समय मौजूद होता है जब ऋण का चक्रिय घटक चक्रिय ऋण के मानक अंतर से 1.5 गुना अधिक होता है। ऋण का चक्रिय घटक हॉडरिक-प्रेसकॉट फिल्टर से प्राप्त किया गया था। कुल खाद्येतर ऋण में मजबूत वृद्धि के साथ ही एनबीएफसी को ऋण और इन्फ्रास्ट्रक्चर को ऋण जैसे क्षेत्रों में भी 2010-11 में उच्च वृद्धि होने के कारण उप-क्षेत्रीय स्तर पर भी विश्लेषण किया गया। इसके परिणाम चार्ट क, ख, ग और घ में दिये गये हैं।

परिणामों ने दर्शाया कि उच्च ऋण वृद्धि के बावजूद समग्र स्तर पर 2010-11 में अर्थव्यवस्था में कोई भी ऋण तेजी नहीं थी। किंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण के चक्रिय घटक ने 2010-11 के प्रारंभ में चक्रिय ऋण के मानक अंतर के 1.5 बार की उच्चतम सीमा पार कर ली हालांकि उसके बाद उसमें कमी आयी। इसके अलावा एनबीएफसी को ऋण में 2010-11 में वृद्धि हुई जिस पर आगे सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता है (चार्ट क, ख, ग और घ)।

संदर्भ:

कोरीसेली, फैब्रिजियो, फैंबियो मूसून और देबोरा रिवोल्टला (2006), "हाउसहोल्ड क्रेडिट इन द न्यू यूरोप: लेंडिंग बूम ऑर सस्टेनेबल ग्रोथ?", चर्चा पत्र सं.5520, आर्थिक नीति अनुसंधान केंद्र, लंदन, यूके।



एलएएफ गलियारे के निम्न दायरे में रहने के बाद मई 2010 के अंत से मजबूत हुई और 2010-11 की दूसरी छमाही में सामान्यतः अनौपचारिक गलियारे के ऊपरी दायरे के ऊपर बनी रही। संपार्श्विकृत घटक (अर्थात् सीबीएलओ और बाजार रिपो) में दरें मांग दर के अनुरूप बनी रहीं किंतु इस अवधि में सामान्यतः इससे नीचे बनी रही। बैंक और प्राथमिक व्यापारी संपार्श्विकृत घटक में उधारकर्ताओं के प्रमुख समूह थे। जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का औसत निर्गम 2010-11 के दौरान उच्च बना रहा। 2010-11 के दौरान औसत निर्गम लगभग 33,000 करोड़ रुपये पर उच्च था जो कि 2009-10 के दौरान 17,000 करोड़ रुपये था। मुद्रा बाजार के अन्य घटकों में दर वृद्धि के अनुरूप औसत सीडी निर्गम के संबंध में प्रभावी ब्याज दर मार्च 2010 के अंत के 6.07 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 9.96 प्रतिशत हो गयी।

5. बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन

कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि में सुधार हुआ

4.55 वर्ष-दर-वर्ष आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि में सुधार हुआ। यह पिछले चार वर्षों के दौरान देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत था। 2010-11 के दौरान इस समग्र ऋण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक सेवा क्षेत्र को ऋण और निजी ऋण थे। सेवा क्षेत्र के भीतर गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को ऋण की वृद्धि दर सर्वाधिक थी जिसके बाद पर्यटन, होटल और रेस्तरा तथा व्यावसायिक सेवा का स्थान था। निजी ऋणों के बीच उच्चतम ऋण वृद्धि शेयरों की जमानत पर अग्रिमों में देखी गयी जिसके बाद एफसीएनआर(बी)/एनआरएनआर जमाराशि की जमानत पर अग्रिम और वाहन ऋणों का स्थान था।

कृषि और उद्योग को ऋण वृद्धि में कमी आयी

4.56 कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को ऋण वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कमी आयी। कृषि ऋण में तेज गिरावट का आंशिक कारण फरवरी-मार्च 2011 में किये गये परिभाषात्मक परिवर्तन था। यह उल्लेखनीय है कि कृषि ऋण की मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षा में छूट के लिए जून 2010 में सीमा में वृद्धि करने (50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये) के बावजूद कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी। औद्योगिक ऋण वृद्धि में समग्र कमी आने के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कमी आयी। किंतु कुल खाद्येतर ऋण वृद्धि और औद्योगिक ऋण वृद्धि की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की ऋण वृद्धि काफी अधिक थी। इस उच्च वृद्धि में मुख्य योगदान दूरसंचार क्षेत्र का था जिसका मुख्य कारण 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सहभागिता के लिए दिया गया ऋण था। यह एकबारगी कार्य होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को ऋण में आगे कमी आ सकती है। किंतु प्रायोगिक अनुमान दर्शाते हैं कि ये दीर्घकाली ऋण बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति देयता असंतुलन बढ़ाते हैं (सारणी IV.21)।⁶

कुल खाद्येतर ऋणों में सेवा क्षेत्र और निजी ऋण का हिस्सा बढ़ा

4.57 उच्च वृद्धि दरों के अनुरूप कुल बकाया खाद्येतर ऋणों में सेवा क्षेत्र और निजी ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2011 के अंत में बढ़ा। इसके विपरीत कुल खाद्येतर ऋणों में कृषि ऋण का हिस्सा कम हो गया। कृषि क्षेत्र जो कि जनसंख्या के बड़े भाग को रोजगार मुहैया कराता है, को मार्च 2011 के अंत में कुल खाद्येतर ऋण का मात्र 13 प्रतिशत भाग मिला था।

⁶ शून्य हायपोथेसिस

	एफ-सांख्यिकी	पी-मूल्य
इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डज नॉट ग्रैंगर काज एएलएम	2.524***	0.09
इंफ्रास्ट्रक्चर लोन डज नॉट ग्रैंगर काज एएलएम गॉप इन द “मोर दैन फाइव इयर”	4.096**	0.02

****: दस प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण। **: पांच प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण।

सारणी IV.21: सकल बैंक ऋण का सेक्टर-वार विनियोजन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2009-10		2010-11	
	राशि	प्रतिशत घट-बढ़	राशि	प्रतिशत घट-बढ़
1	2	3	4	5
1. कृषि तथा संबद्ध गतिविधियाँ	4,16,133	22.9	4,60,333	10.6
2. उद्योग	13,11,451	24.4	16,20,849	23.6
जिसमें से:				
बुनियादी सुविधा संबंधी ऋण	3,79,888	40.7	5,26,655	38.6
3. व्यक्तिगत ऋण	5,85,633	4.1	6,85,372	17.0
जिसमें से: आवास क्रेडिट कार्ड	3,00,929	7.7	3,46,110	15.0
बकाया	20,145	-28.1	18,098	-10.2
शिक्षा	36,863	29.0	43,710	18.6
4. सेवाएं	7,26,790	12.5	9,00,801	23.9
जिसमें से:				
पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	19,410	42.5	27,729	42.9
वाणिज्यिक स्थावर संपदा उधार	92,128	-0.3	1,11,836	21.4
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1,13,441	14.8	1,75,577	54.8
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	30,40,007	16.8	36,67,355	20.6

टिप्पणी: 1) डेटा अनंतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं।
2) कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में आई मंदी प्रमुख रूप से फरवरी-मार्च 2011 से प्रभावी परिभाषात्मक परिवर्तनों के कारण थी।

स्रोत: सेक्टरोल एंड इंडीस्ट्रियल डिप्लायमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट रिटर्न (मासिक)।

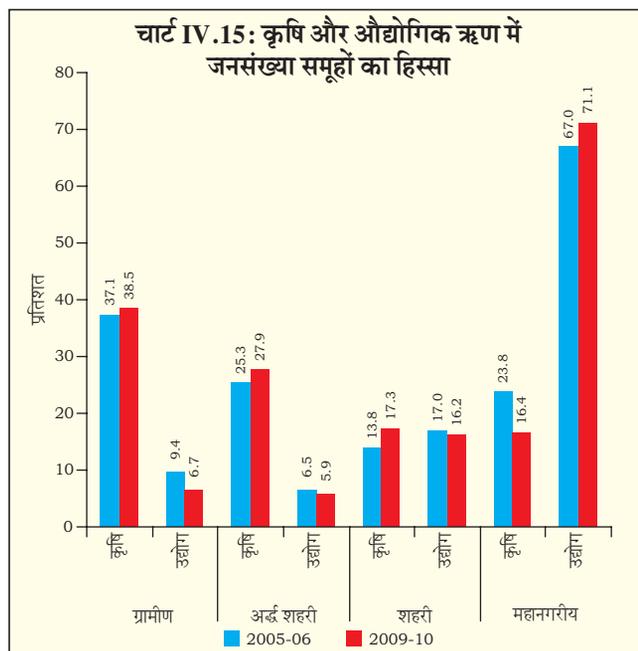
4.58 मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार कुल कृषि ऋण का लगभग 39 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को और 28 प्रतिशत भाग अर्धशहरी क्षेत्रों में संवितरित हुआ था। कुल कृषि ऋण में ग्रामीण अर्धशहरी और शहरी क्षेत्रों के हिस्से में 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान वृद्धि हुई वहीं महानगरीय क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट हुई (चार्ट IV.15)।⁷

4.59 बकाया खाद्येतर ऋण में औद्योगिक ऋण का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 कम हो गया। किंतु इस गिरावट के बावजूद 2010-11 में कुल खाद्येतर ऋण का लगभग आधा हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र को गया। कुल औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा 2009-10 के 29 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 33 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र को ऋण, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11

⁷ बेसिक सांख्यिकी विवरणी के विभिन्न अंकों से लिये गये आंकड़ों पर आधारित।

⁸ बेसिक सांख्यिकी विवरणियाँ 2009-10 से लिये गये आंकड़ों पर आधारित।

चार्ट IV.15: कृषि और औद्योगिक ऋण में जनसंख्या समूहों का हिस्सा



69 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, का कुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में हिस्सा बढ़ गया।

4.60 मार्च 2010 के अंत में कुल औद्योगिक ऋण के 70 प्रतिशत से अधिक भाग महानगरीय क्षेत्रों में संवितरित किया गया था जिससे अन्य जनसंख्या समूहों के लिए कम भाग बचा था (चार्ट IV.15)।⁸

नीतिगत कड़ाई के बावजूद आवास ऋण में उच्च वृद्धि हुई

4.61 निजी ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह स्मरण होगा कि निजी ऋण में वृद्धि 2000 के मध्य के उच्च ऋण वृद्धि के दौर के पीछे का एक प्रमुख कारण था। अन्य अनेक कारणों से भी इसकी निगरानी आवश्यक है। पहला, आवास ऋण ब्याज दर वृद्धि के प्रति संवेदनशील होने के कारण उधारकर्ताओं द्वारा चूक की संभावना को बढ़ा सकते हैं। वस्तुतः दिसंबर 2010 में रिजर्व बैंक ने अति लीवरेजिंग रोकने के लिए आवास ऋण संबंधी विवेकसम्मत मानदंड कड़े किये थे। किंतु नीतिगत कड़ाई के बावजूद आवास ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। यह कड़ाई वर्ष के अंतिम दौर में होने के

कारण हो सकता है कि इसका असर बाद में दिखे। दूसरा, निजी ऋण (आवास और वाहन ऋण छोड़कर) का बड़ा भाग बेजमानती ऋण होता है और यह बैंकिंग क्षेत्र में जीएनपीए को प्रभावित कर सकती है। तीसरा, अधिकतर निजी ऋण दीर्घावधि ऋण होते हैं और प्रायोगिक विश्लेषण दर्शाता है कि इससे दीर्घावधि समूहों में आस्ति देयता बेमेल उत्पन्न होते हैं⁹।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण

समग्र स्तर पर, बैंकिंग क्षेत्र ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋण का लक्ष्य पूरा किया

4.62 प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार¹⁰ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 18 प्रतिशत वृद्धि हुई। किंतु कृषि अग्रिम वृद्धि 2010-11 में कम होकर 9 प्रतिशत रह गयी जो कि पिछले वर्ष 23 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी समग्र स्तर पर बैंकों ने अपने एएनबीसी का 40 प्रतिशत से अधिक भाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को उधार दिया था। कृषि के लिए एएनबीसी के 18 प्रतिशत का निर्धारित उप-लक्ष्य भी 2010-11 में बैंकों ने पूरा किया (सारणी IV.22)।

कुछ पीएसबी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके

4.63 किंतु एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का बैंक-वार डाटा दर्शाता है कि 26 पीएसबी में से सात 2010-11 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र का एएनबीसी के 40 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करने में समर्थ नहीं थे। इसके अलावा यह चिंता की बात है कि 2010-11 में 26 पीएसबी में से 18 कृषि अग्रिमों का लक्ष्य पूरा

सारणी IV.22: सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2010	2011अ	2010	2011अ
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम^a	8,63,777	10,28,615	2,14,669	2,48,828
	(41.6)	(41.3)	(45.8)	(46.6)
जिसमें से, कृषि	3,72,463	4,14,991	90,737	92,136
	(17.9)	(16.5)	(19.4)	(15.7)
जिसमें से, व्यक्ति और लघु उद्यम	2,76,319	3,76,625	64,825	87,857
	(13.3)	(15.1)	(13.8)	(16.4)

अ: अनंतिम

#: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े निवल बैंक ऋण / समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) / तुलनपत्रेतर एक्सपोजर के कर्ज के बराबर राशि (सीईओबीएसई) जो भी अधिक हो, की तुलना में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

करने में समर्थ नहीं थे। निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच 2010-11 में मात्र एक बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। किंतु निजी क्षेत्र के दस बैंक 2010-11 में कृषि अग्रिमों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके (चार्ट IV.16क और IV.16ख, और परिशिष्ट सारणी IV.4क, IV.4ख, IV.5क और IV.5ख)।

4.64 विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों के कुछ अलग मानदंड हैं क्योंकि इस संबंध में उनका लक्ष्य एएनबीसी का 32 प्रतिशत है। इसके अलावा विदेशी बैंकों के लिए निर्यात ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का एक भाग होता है। 2010-11 में समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य प्राप्त किया। किंतु 2010-11 में बैंक स्तर पर कुछ बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधारों का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके। इसके अलावा समग्र स्तर पर विदेशी बैंकों द्वारा 12 प्रतिशत का निर्यात ऋण का लक्ष्य पूरा करने के बावजूद बैंक स्तर पर

⁹ शून्य हायपोथेसिस

पर्सनल लोन डज नॉट ग्रॉगर कॉज एएलएम

एफ-सांख्यिकी

2.841**

पी-मूल्य

0.04

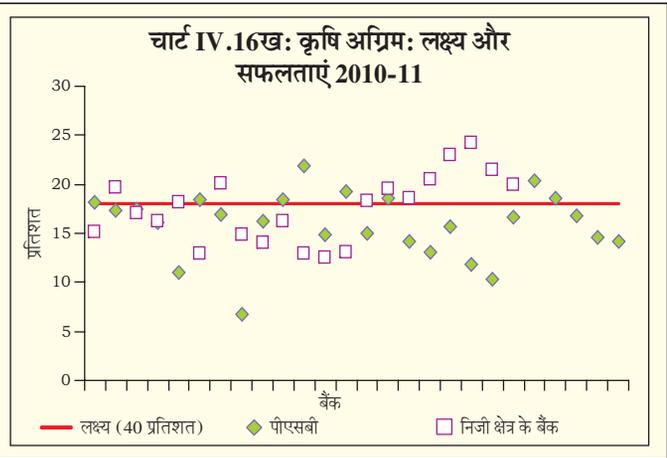
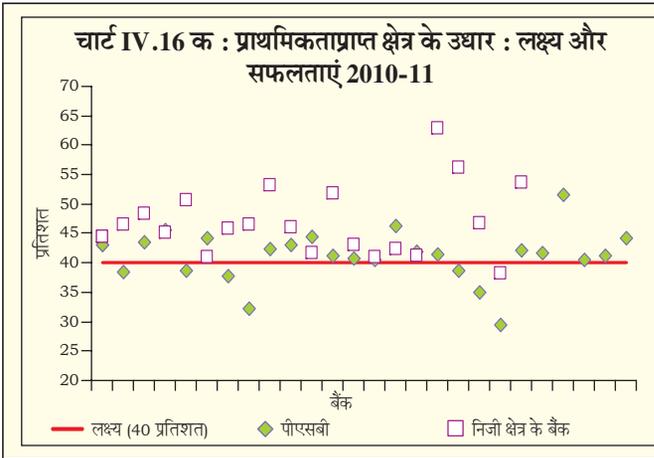
पर्सनल लोन डज नॉट ग्रॉगर कॉज एएलएम इन द “श्री टू फाइव इयर”

4.340**

0.02

** : पांच प्रतिशत स्तर पर महत्वपूर्ण।

¹⁰ मौजूदा मानदंडों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों को पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो का 50 प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना होता है।



कुछ बैंक यह लक्ष्य पूरा नहीं कर सके (सारणी IV.23, चार्ट IV.17क और IV.17ख, और परिशिष्ट सारणी IV.4ग और IV.5ग)।

खुदरा ऋण

खुदरा ऋण घटक में उच्च वृद्धि हुई

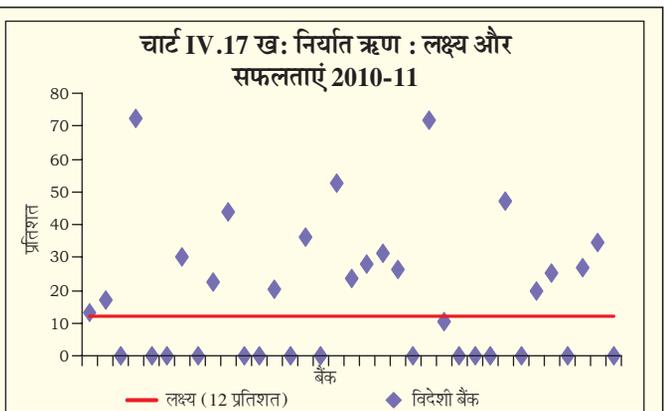
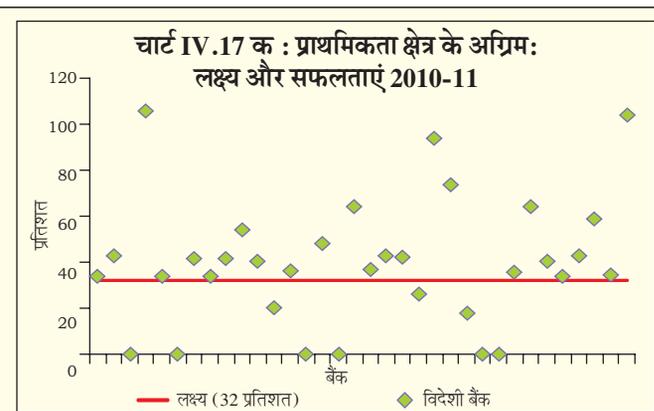
4.65 बैंकिंग क्षेत्र का खुदरा ऋण घटक, जिसमें हाल की अवधि में गिरावट हुई थी, में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सर्वाधिक वृद्धि उपभोक्ता टिकाऊ माल में दर्ज हुई जिसके बाद ऑटो ऋण का स्थान था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आवास ऋण में 16 प्रतिशत की कम वृद्धि हुई। महत्वपूर्ण रूप से आवास ऋण बैंकिंग क्षेत्र के कुल खुदरा पोर्टफोलियो का निरंतर लगभग आधा बना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करने

वाला एकमात्र उप-घटक क्रेडिट कार्ड रिसिवेबल्स था (सारणी IV.24)।

संवेदनशील क्षेत्रों का ऋण

संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण में उच्च वृद्धि हुई

4.66 संवेदनशील क्षेत्रों का ऋण अर्थात् ऋण बाजार के प्रति एक्सपोजर, स्थावर संपदा क्षेत्र को प्रत्यक्ष और परोक्ष उधार और पण्य क्षेत्र को ऋण वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें मूल्य घट-बढ़ होती रहती है जिससे ऋणों और अग्रिमों में तेजी आ जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण में उच्च वृद्धि हुई। 2010-11 में एसबीआई समूह द्वारा सूचित संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण इस उद्योग के 22 प्रतिशत के औसत की तुलना में 41 प्रतिशत पर विशेष रूप से उल्लेखनीय था। इसका मुख्य कारण स्थावर संपदा ऋण में वृद्धि था।



टिप्पणी: प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य 2011-12 से उन बैंकों पर लागू होगा जिन्होंने अपना कार्य 2010-11 में शुरू किया है। शून्य मूल्य का यह भी एक कारण है।

सारणी IV.23 : विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2010		2011अ	
	राशि	एएनबीसी/सीईओबीएसई की तुलना में प्रतिशत	राशि	एएनबीसी/सीईओबीएसई की तुलना में प्रतिशत
1	2	3	4	5
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम#	59,960	36.0	66,527	40.0
जिसमें से, निर्यात ऋण	33,396	20.1	42,487	25.5
जिसमें से: व्यक्ति और लघु उद्यम*	21,147	12.7	21,501	12.9

अ: अर्न्तम
 #: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार व्यापक वर्ग में छोटे उद्यम, खुदरा व्यापार, माइक्रोक्रेडिट, शिक्षा और आवास शामिल है।
 *: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर नए दिशा निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार लघु और सूक्ष्म उद्यमों की संशोधित परिभाषा को ध्यान में रखा गया है।
 टिप्पणी: एएनबीसी/सीईओबीएसई - समायोजित निवल बैंक ऋण / तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के बराबर ऋण राशि, जो भी अधिक हो।

4.67 उच्च वृद्धि के बावजूद कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम हो गया जिसका कारण कुल ऋणों और अग्रिमों की वृद्धि में संतुलन होना था। 2010-11 में कुल ऋणों और अग्रिमों में संवेदनशील क्षेत्रों के ऋण और स्थावर संपदा के ऋण का हिस्सा विदेशी बैंकों के मामले में सर्वाधिक था जिनके बाद निजी क्षेत्र के नये बैंकों का स्थान था (परिशिष्ट सारणी IV.6)।

6. पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों से जुटाये गये संसाधनों में वृद्धि हुई

4.68 पिछले दो वर्षों में देखी गयी प्रवृत्ति के विपरीत बैंकों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों से जुटाये गये संसाधनों में 2010-11 में काफी

सारणी IV.24: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		प्रतिशत घट-बढ़	
	2010	2011	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	3,15,862	3,67,364	20.0	16.3
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	3,032	4,555	-44.2	50.2
3. क्रेडिट कार्ड प्राप्तियां	21,565	18,655	-28.0	-13.5
4. ऑटो ऋण	78,346	1,00,155	-6.6	27.8
5. अन्य व्यक्तिगत ऋण	2,03,947	2,53,243	-3.5	24.2
कुल खुदरा ऋण (1 से 5)	6,22,752 (19.0)	7,43,972 (18.5)	4.9	19.5

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल उधारों और अग्रिम में खुदरा उधारों के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं। कुल उधारों और अग्रिमों की राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ऑफ साइट विवरणियों (देशी) में दिए गए अनुसार हैं।

स्रोत: ऑफ साइट विवरणी (घरेलू) पर आधारित।

वृद्धि हुई विशेष रूप से मार्च 2011 के दौरान जब कुल संसाधनों का 70 प्रतिशत भाग जुटाया गया था। एफआईआई अंतर्वाहों की पुनर्बहाली और गौण बाजार में कम सुधार के कारण बैंक संसाधन जुटा पाये। बैंकों द्वारा राइट इश्यू के माध्यम से पूंजी जुटायी गयी थी और इस वृद्धि में सर्वाधिक हिस्सा पीएसबी का था (सारणी IV.25)।

4.69 बैंकों द्वारा निजी स्थानन के माध्यम से जुटाये गये संसाधन पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 40 प्रतिशत कम हो गये जिसका मुख्य कारण निजी क्षेत्र के बैंक थे जिन्होंने 64 प्रतिशत गिरावट दर्ज की थी (सारणी IV.26)।

4.70 2010-11 के दौरान बैंकों ने वैश्विक पूंजी बाजारों से संसाधन नहीं जुटाये। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि में धीमे सुधार का वातावरण, यूरो झोन में सरकारी ऋण समस्या की निरंतरता और एमईएनए क्षेत्र में राजनैतिक तनाव ने यूरो निर्गमों के माध्यम

सारणी IV.25: बैंकिंग क्षेत्र के सार्वजनिक निर्गम

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		कुल		कुल योग
	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण	
1	2	3	4	5	6	7	8=(6+7)
2009-10	325	-	313	-	638	-	638
2010-11	4,332	-	915	-	5,247	-	5,247

-: शून्य / नगण्य

सारणी IV.26: निजी प्लेसमेंट के माध्यम से बैंकों द्वारा जुटाए गए संसाधन

(राशि करोड़ रुपये में)

श्रेणी	2009-10		2010-11	
	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि	निर्गमों की संख्या	जुटाई गई राशि
1	2	3	4	5
निजी क्षेत्र के बैंक	18	17,101	5	6,063
सरकारी क्षेत्र के बैंक	63	23,762	25	20,916
कुल	81	40,863	30	26,979

टिप्पणी: 2010-11 के आंकड़े अनंतिम हैं।

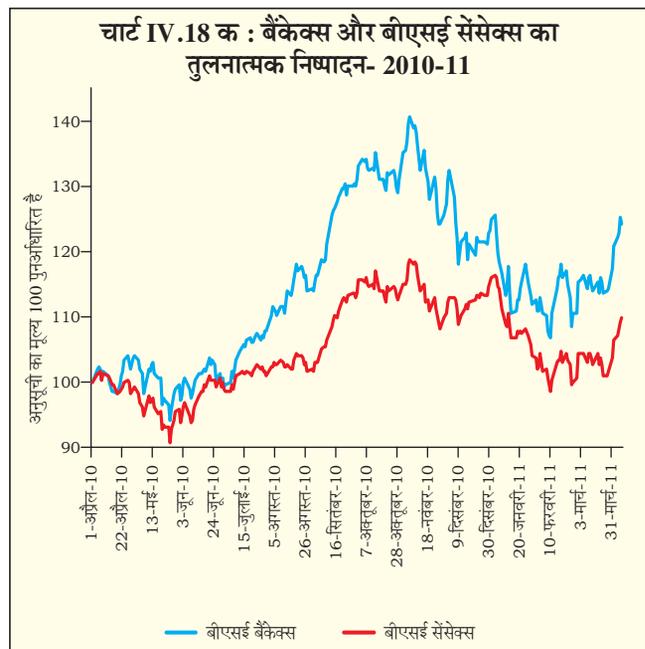
स्रोत: मर्चेन्ट बैंकर और वित्तीय संस्थाएं।

से समग्र संसाधन जुटाव पर नकारात्मक प्रभाव डाला (सारणी IV.27)।

गौण बाजार में बैंकिंग शेयरों का निष्पादन

चिंताओं के बावजूद बीएसई बैंकेक्स बीएसई सेंसेक्स से आगे निकल गया

4.71 देशी शेयर बाजार, जिसने 2009-10 में काफी लाभ दर्ज किया था, 2010-11 में भी निरंतर लाभदायक बना रहा हालांकि इसकी गति धीमी थी। निवल ब्याज मार्जिन और बढ़ते प्रावधानीकरण की चिंता के बावजूद पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी बीएसई बैंकेक्स बीएसई सेंसेक्स से आगे निकल गया जो ऋण मांग में अच्छी वृद्धि के कारण बाजार-भावना का सकारात्मक होना दर्शाता है (चार्ट IV.18)।



बीएसई बैंकेक्स में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में अधिक घट-बढ़ हुई

4.72 38 सूचीबद्ध बैंकों में से चार बैंकों ने पिछले वर्ष की तुलना में उनके शेयरों में मूल्यों में गिरावट दर्ज की। बीएसई बैंकेक्स में बीएसई सेंसेक्स की तुलना में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में अधिक घट-बढ़ हुई जो कि इन शेयरों में लेनदेन में जोखिम दर्शाती है (सारणी IV.27)।

4.73 2010-11 में 38 बैंकों में से नौ बैंकों का मूल्य-आय (पी/ई) अनुपात पिछले वर्ष की तुलना में कम था। बैंक शेयरों में 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कुल पण्यावर्त में उनके शेयरों में वृद्धि हुई। यह हिस्सा 2011-12 में (अप्रैल और जून के दौरान) और बढ़ा। इसी प्रकार कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ा। किंतु कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक शेयरों का हिस्सा मार्च 2011 के अंत की तुलना में जून 2011 के अंत में कम हो गया (सारणी IV.28 और परिशिष्ट सारणी IV.7)।

7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में शेयरधारिता पद्धति

पीएसबी में सरकारी शेयरधारिता सांविधिक अपेक्षा से पर्याप्त अधिक थी

4.74 2010-11 में पीएसबी में सरकारी शेयरधारिता मोटे तौर पर 57 प्रतिशत और 85 प्रतिशत के बीच थी हालांकि न्यूनतम सांविधिक अपेक्षा 51 प्रतिशत है (सारणी IV.29 और चार्ट IV.19)।

सारणी IV.27: बैंकिंग क्षेत्र द्वारा यूरो निर्गम माध्यम से संसाधन जुटाना

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2009-10	2010-11
1	2	3
यूरो निर्गम	843	-
(i) एडीआर	-	-
क) निजी	-	-
ख) सार्वजनिक	-	-
(ii) जोडीआर	843	-
क) निजी	843	-
ख) सार्वजनिक	-	-
(iii) एफसीसीबी	उ. न.	उ. न.

उ.न.: उपलब्ध नहीं.

-: शून्य / नगण्य

एफसीसीबी: विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

एडीआर/जोडीआर: अमरीकी / वैश्विक निक्षेपगार रसीदे।

सारणी IV.28: जोखिम -प्रतिफल निष्पादन, टर्नओवर और बैंक स्टॉक्स का पूंजीकरण

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12#
1	2	3	4	5
1. प्रतिफल*				
बीएसई बैंकेक्स	-41.8	137.2	24.9	-3.6
बीएसई सेसेक्स	-37.9	80.5	10.9	-2.3
2. अस्थिरता@				
बीएसई बैंकेक्स	23.0	16.5	10.3	4.3
बीएसई सेसेक्स	24.2	11.9	6.3	3.3
3. कुल कारोबार में बैंक स्टॉक के कारोबार का हिस्सा	9.61	8.28	9.48	9.96
4. कुल बाजार पूंजीकरण में बैंक स्टॉक के पूंजीकरण का हिस्सा**	8.41	10.03	11.91	11.55

*: अंक दर अंक आधार पर सूचकांक में प्रतिशत घटबढ़।

@: घटबढ़ के सह गुणांक के रूप में परिभाषित।

** : अवधि के अंत में

#: अप्रैल - जून 30, 2011

स्रोत: बीएसई

4.75 पीएसबी में विदेशी शेयरधारिता पिछले वर्ष जैसे ही 2010-11 में भी निरंतर कम बनी रही। 21 में से बारह पीएसबी के पास 2010-11 में विदेशी शेयरधारिता का दस प्रतिशत से भी कम भाग था जबकि शेष पीएसबी के पास विदेशी शेयरधारिता का 20 प्रतिशत से भी कम भाग था। निजी क्षेत्र के सभी नये बैंकों के पास 30 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता थी। निजी क्षेत्र के 14 पुराने बैंकों में से नौ में 2010-11 में 20 प्रतिशत से अधिक की विदेशी शेयरधारिता थी। किंतु निजी क्षेत्र के सभी बैंकों

सारणी IV.29: निजी शेयर धारिता के प्रतिशत द्वारा वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंक (मार्च 2011 के अंत में)

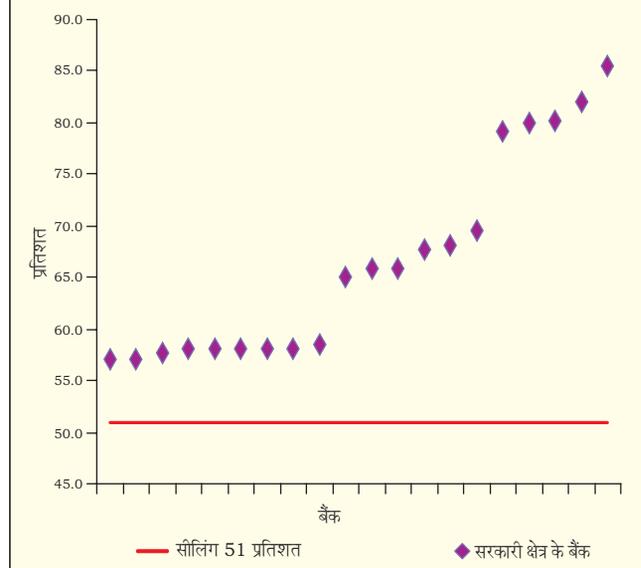
शेयर धारिता की श्रेणी	निजी निवासी शेयर धारिता	निजी अनिवासी शेयर धारिता	कुल निजी शेयर धारिता
1	2	3	4
10 प्रतिशत तक	1	12	-
10 से अधिक और 20 प्रतिशत तक	6	9	4
20 से अधिक और 30 प्रतिशत तक	9	-	1
30 से अधिक और 40 प्रतिशत तक	2	-	6
40 से अधिक और 43 प्रतिशत तक	3	-	10

-: शून्य /नगण्य

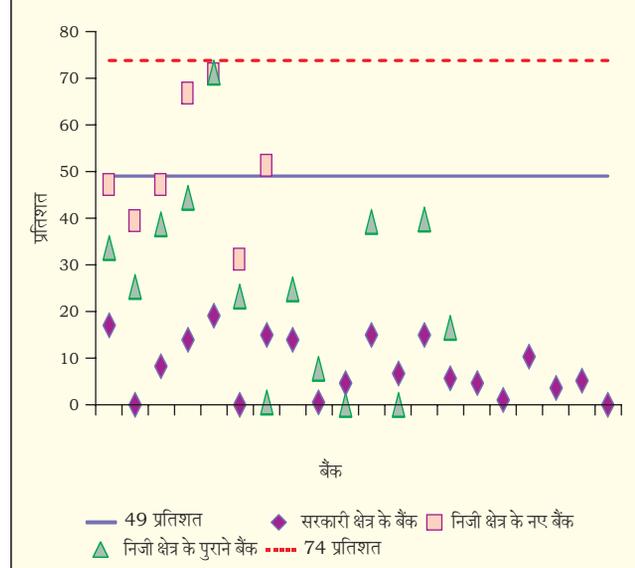
*: 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड सहित।

की विदेशी शेयरधारिता रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक अधिकतम सीमा अर्थात् 74 प्रतिशत से कम थी। यह उल्लेखनीय है कि मात्र चार बैंक नामतः निजी क्षेत्र के तीन नये बैंक और निजी क्षेत्र का एक बैंक की विदेशी शेयरधारिता 2010-11 में 49 प्रतिशत से अधिक है; यह प्रतिशत रिजर्व बैंक द्वारा नये बैंकों के लिए उनके प्रथम पांच वर्षों के परिचालनों के लिए अगस्त 2011 में जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों में दी गयी थी (चार्ट VI.20 और परिशिष्ट सारणी VI.8)।

चार्ट IV.19: सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयर धारिता (मार्च 2011 की समाप्त पर)



चार्ट IV.20: देशी बैंकों में विदेशी शेयरधारिता (मार्च 2011 की समाप्त पर)



8. विदेशी बैंकों के भारत में परिचालन और भारतीय बैंकों के विदेश में परिचालन

विदेशी बैंकों के भारत में परिचालनों में वृद्धि हुई

4.76 अगस्त 2011 के अंत में भारत में 38 विदेशी बैंक (24 देशों से) कार्यरत थे जबकि सितंबर 2010 के अंत में यह संख्या 34 थी। शाखाओं की कुल संख्या भी अगस्त 2011 के अंत में बढ़कर 321 हो गयी जो कि सितंबर 2010 के अंत में 315 थी। इसके अलावा अगस्त 2011 के अंत में भारत में 47 विदेशी बैंक प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से कार्यरत थे जबकि सितंबर 2010 के अंत में यह संख्या 45 थी। विदेशी बैंकों के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा शाखा नेटवर्क स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का था जिसके बाद एचएसबीसी लि., सिटीबैंक और रॉयल बंक ऑफ स्कॉटलैंड एन.वी. का स्थान था।

4.77 सितंबर 2010 और अगस्त 2011 के बीच चार नये बैंकों अर्थात् नैशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक, इंडस्ट्रीयल ऐंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, राबोबैंक इंटरनैशनल और वूरी बैंक को भारत में एक-एक शाखा खोलने की अनुमति दी गयी। सुमितोमो मित्सुइ बैंकिंग कारपोरेशन को भी भारत में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी।

भारतीय बैंकों के विदेशी परिचालनों में वृद्धि हुई

4.78 सितंबर 2010 और अगस्त 2011 के बीच भारतीय बैंकों ने विदेश में एक अनुषंगी तथा एक प्रतिनिधि कार्यालय के साथ ही नौ और शाखाएं खोलीं। इस प्रकार 2010-11 में भारतीय बैंकों (16 पीसीबी और निजी क्षेत्र के 6 बैंक) के विदेश में परिचालन बढ़े जिसमें पिछले वर्ष के 233 कार्यालयों की तुलना में 244 कार्यालयों का नेटवर्क था। अगस्त 2011 के अंत में सबसे बड़े भारतीय बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक का विदेशी कार्यालयों का नेटवर्क सबसे व्यापक था जिसके बाद बैंक ऑफ बडौदा का स्थान था। अगस्त 2011 के अंत में कुल विदेशी कार्यालयों में इन दो बैंकों का संयुक्त हिस्सा 51 प्रतिशत था। निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच अगस्त 2011 के अंत में आईसीआईसीआई बैंक लि. की विदेश में सर्वाधिक उपस्थिति थी। 2010-11 में एसबीआई ने विदेश में पांच नये कार्यालय

खोलकर विदेशी परिचालनों का सर्वाधिक विस्तार किया (सारणी VI.30)।

9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में प्रौद्योगिकीय विकास

प्रौद्योगिकीय उन्नयन जारी रहा

4.79 हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास के कारण बैंकिंग की गति और गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ है। कंप्यूटीकरण और कोर बैंकिंग समाधान बैंकिंग सेवाओं की कार्यकुशलता सुधारने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम था। निजी क्षेत्र के नये बैंक और अधिकतर विदेशी बैंक, जिन्होंने उदारीकरण के बाद नब्बे के दशक के मध्य में अपने परिचालन शुरू किये थे, प्रौद्योगिकी अपनाने के पुरोधा थे। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों और पीएसबी के लिए उनके पुराने रेकार्ड और प्रथाओं के कारण प्रौद्योगिकी अपनाना दुरुह कार्य था। किंतु यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पीएसबी की लगभग 98 प्रतिशत शाखाएं पूर्णतः कंप्यूटीकृत हैं और इनमें से लगभग 90 प्रतिशत शाखाएं कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं।

4.80 इसके अलावा स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) के कारण ग्राहक शाखाओं में गये बिना बैंकिंग कार्य करने में समर्थ हो गये। 2010-11 में एटीएम की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत वृद्धि हुई। किंतु कुल एटीएम में ऑफ साइट एटीएम की संख्या 2009-10 के 45.7 प्रतिशत से कुछ कम होकर 45.3 प्रतिशत रह गयी। मार्च 2011 के अंत में कुल एटीएम में से 65 प्रतिशत से अधिक पीएसबी के थे (सारणी VI.31 और परिशिष्ट सारणी VI.9)।

4.81 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान डेबिट कार्डों की संख्या 25 प्रतिशत की दर पर बढ़ी। एटीएम के मामले में देखी गयी प्रवृत्ति के अनुरूप ही मार्च 2011 के अंत में कुल डेबिट कार्डों में से लगभग तीन चौथाई पीएसबी ने जारी किये थे। बकाया डेबिट कार्डों में पीएसबी का हिस्सा हाल के वर्षों में बढ़ा है जबकि उसी अवधि में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा कम हुआ। किंतु निरपेक्ष संदर्भ में हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के मामले में बकाया डेबिट कार्डों की संख्या में वृद्धि हुई (सारणी VI.32 और चार्ट VI.21)।

सारणी IV.30: भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन
(वास्तविक से परिचालन)

बैंक का नाम	शाखा		सहायक बैंक		प्रतिनिधि कार्यालय		संयुक्त उद्यम बैंक		कुल	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. सरकारी क्षेत्र के बैंक	137	144	20	21	39	39	7	7	203	211
1. इलाहाबाद बैंक	1	1	-	-	1	1	-	-	2	2
2. आंध्रा बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	46	47	9	9	3	3	1	1	59	60
4. बैंक ऑफ इंडिया	24	24	3	3	5	5	1	1	33	33
5. केनरा बैंक	4	4	-	-	1	1	-	-	5	5
6. कॉर्पोरेशन बैंक	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
7. इंडियन बैंक	3	4	-	-	-	-	-	-	3	4
8. इंडियन ओवरसीज बैंक	6	6	1	1	4	4	-	-	11	11
9. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
10. पंजाब नेशनल बैंक	4	4	2	3	4	4	1	1	11	12
11. भारतीय स्टेट बैंक	42	47	5	5	8	8	4	4	59	64
12. सिंडिकेट बैंक	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
13. यूको बैंक	4	4	-	-	2	2	-	-	6	6
14. ग्रिनियन बैंक	1	1	-	-	5	5	-	-	6	6
15. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
16. औरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
II. निजी क्षेत्र के नए बैंक	11	13	3	3	16	17	-	-	30	33
17. ऐक्सिस बैंक	3	3	-	-	2	3	-	-	5	6
18. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	1	2	-	-	2	2	-	-	3	4
19. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	7	8	3	3	8	8	-	-	18	19
20. इंडसइंड बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2
21. फेडरल बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
22. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1
कुल	148	157	23	24	55	56	7	7	233	244

-: शून्य

टिप्पणी: 1) 2010 के आंकड़े सितंबर समाप्ति से संबंधित हैं।
2) 2011 के आंकड़े अगस्त समाप्ति से संबंधित हैं।

बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या में कमी आयी

4.82 क्रेडिट कार्डों के निर्गम ने कागजी मुद्रा अपने पास रखे बिना लेनदेन करना सुगम हो जाता है। क्रेडिट कार्डों की संख्या में कमी आने के बावजूद क्रेडिट कार्डों द्वारा किये गये लेनदेनों से संबंधित मात्रा और

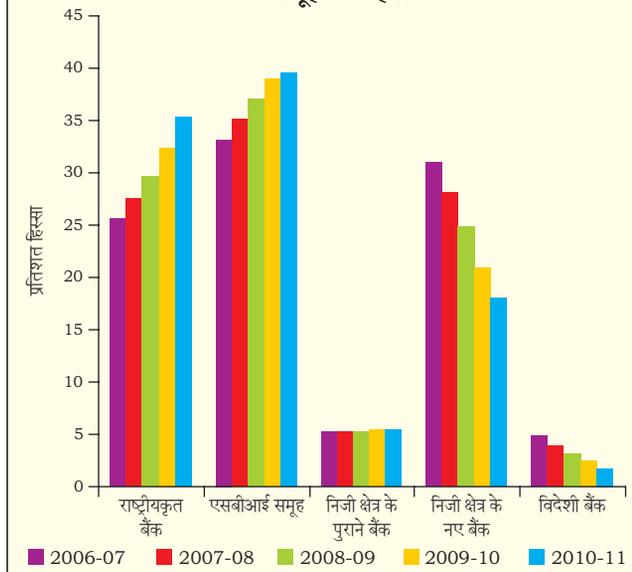
मूल्य में 2010-11 में क्रमशः 13 प्रतिशत और 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। मार्च 2011 के अंत में कुल बकाया क्रेडिट कार्डों में निजी क्षेत्र के

सारणी IV.31: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम
(मार्च 2011 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	ऑन-साइट एटीएम	ऑफ साइट एटीएम	एटीएम की कुल संख्या	कुल एटीएम के प्रतिशत के अनुसार ऑफ साइट एटीएम
1		2	3	4	5
I	सरकारी क्षेत्र के बैंक	29,795	19,692	49,487	39.8
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक*	15,691	9,145	24,836	36.8
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	14,104	10,547	24,651	42.8
II	निजी क्षेत्र के बैंक	10,648	13,003	23,651	55.0
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	2,641	1,485	4,126	36.0
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	8,007	11,518	19,525	59.0
III	विदेशी बैंक	286	1,081	1,367	79.1
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)		40,729	33,776	74,505	45.3

*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

चार्ट IV.21: बकाया डेबिट कार्डों में बैंक समूहों का हिस्सा



सारणी IV.32: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी डेबिट कार्ड
(मार्च 2010 के अंत में)

क्रम सं.	बैंक समूह	बकाया डेबिट कार्डों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1		2	3	4	5	6
I	सरकारी क्षेत्र के बैंक	44.09	64.33	91.7	129.69	170.34
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	19.24	28.29	40.71	58.82	80.27
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	24.85	36.04	50.99	70.87	90.07
II	निजी क्षेत्र के बैंक	27.19	34.1	41.34	47.85	53.58
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	3.94	5.34	7.09	9.81	12.44
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	23.25	28.76	34.25	38.04	41.14
III	विदेशी बैंक	3.70	4.02	4.39	4.43	3.92
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)		74.98	102.44	137.43	181.97	227.84

नये बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक था (सारणी VI.33 और चार्ट VI.22)।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में निरंतर वृद्धि हुई

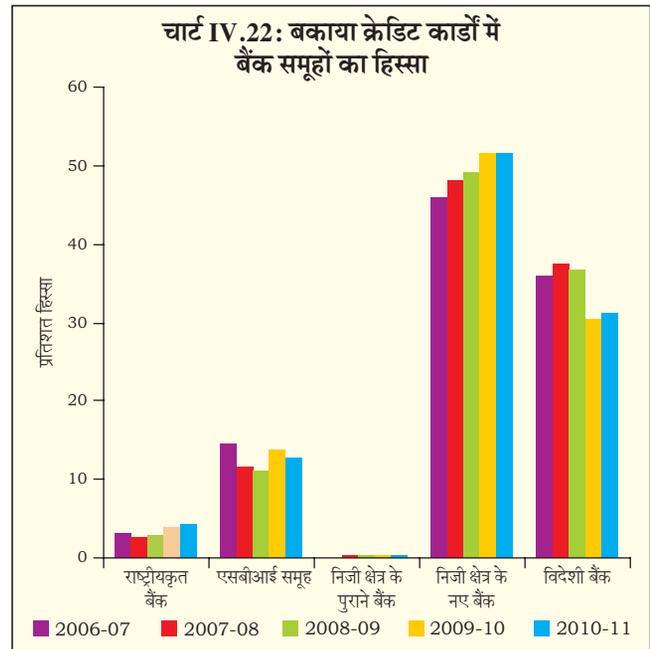
4.83 जमा और नामे के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), खुदरा लेनदेन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (नेफ्ट) और बड़े मूल्यों के लिए रियल टाइम सकल निपटान (आरटीजीएस) जैसी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों से देश भर में वित्तीय लेनदेनों की गति में वृद्धि हुई है।

नेफ्ट के माध्यम से किये गये लेनदेनों की मात्रा में तेज वृद्धि हुई

4.84 इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के खुदरा और बड़े

सारणी IV.33: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड
(मार्च 2010 को समाप्त)

क्रम सं.	बैंक समूह	बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1		2	3	4	5	6
I	सरकारी क्षेत्र के बैंक	4.14	3.93	3.44	3.26	3.08
1.1	राष्ट्रीयकृत बैंक	0.75	0.72	0.72	0.73	0.78
1.2	भारतीय स्टेट बैंक समूह	3.39	3.21	2.72	2.53	2.30
II	निजी क्षेत्र के बैंक	10.68	13.29	12.18	9.5	9.32
2.1	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	0.03	0.04	0.06	0.06	0.04
2.2	निजी क्षेत्र के नए बैंक	10.65	13.25	12.12	9.44	9.28
III	विदेशी बैंक	8.31	10.33	9.08	5.57	5.64
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (I+II+III)		23.12	27.55	24.70	18.33	18.04



मूल्य की प्रणाली ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान वृद्धि दर्ज की जिसमें से नेफ्ट ने अधिक वृद्धि दर्ज की (सारणी VI.34)।

10. ग्राहक सेवा

बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में गिरावट

4.85 बैंकिंग क्षेत्र में जनसामान्य का विश्वास बढ़ाने में ग्राहक संतुष्टि एकीकृत घटक है जो कि मध्य से दीर्घ अवधि में वित्तीय समावेशन में भी सहायता कर सकता है। बैंकिंग में ग्राहक सेवा के महत्त्व को पहचानते हुए रिजर्व बैंक ने 2006 में एक अलग ग्राहक सेवा विभाग बनाया और 15 प्रमुख बैंकिंग केंद्रों में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय खोले। इसकी शुरुआत से ही ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के निपटान में बैंकिंग लोकपाल काफी प्रभावी सिद्ध हुआ है।

4.86 2010-11 में देश भर में बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों में कमी आयी। यह गिरावट विशेष रूप से महानगरीय क्षेत्रों अर्थात् नयी दिल्ली, मुंबई और चेन्नै में अधिक दिखी। किंतु गिरावट की सामान्य प्रवृत्ति के बावजूद भोपाल, पटना, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और गुवाहाटी जैसे केंद्र भी हैं जहां इन शिकायतों में वृद्धि हुई (सारणी VI.35)।

सारणी IV. 34: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों की मात्रा और मूल्य
(मार्च 2011 की समाप्ति पर)

(मात्रा मिलियन में, मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	2009-10		2010-11		2009-10		2010-11	
	मात्रा		प्रतिशत घट-बढ़		मूल्य		प्रतिशत घटबढ़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ईसीएस क्रेडिट	98.1	117.3	11.0	19.5	1,17,613	1,81,686	20.6	54.5
ईसीएस डेबिट	149.3	156.7	-6.7	5.0	69,524	73,646	3.8	5.9
एनईएफटी	66.3	132.3	106.3	99.5	4,09,507	9,39,149	62.5	129.3
आरटीजीएस	33.2	49.3	148.5	48.2	3,94,53,359	4,84,87,234	22.2	22.9

*: कार्डों के माध्यम से किए गए लेनदेनों को छोड़कर

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई

4.87 किंतु पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध शिकायतों में कमी आयी। 2010-11 में प्रतिशाखा शिकायतों की संख्या 22.34 प्रतिशत पर विदेशी बैंकों के मामले में सर्वाधिक थी। 2010-11 में कुल शिकायतों में से लगभग एक चौथाई शिकायतें क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्डों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं जिनके बाद पेंशन (8 प्रतिशत) और ऋण तथा अग्रिम (6 प्रतिशत) का स्थान था। पेंशन और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों (डीएसए) के विरुद्ध शिकायतों में

पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई (सारणी VI.36 और परिशिष्ट सारणी VI.10)।

4.88 यहां यह नोट करना आवश्यक है कि डीएसए संबंधी शिकायतों का केंद्र निजी क्षेत्र के नये बैंक और विदेशी बैंक थे। 2010-11 में डीएसए संबंधी कुल शिकायतों में से 90 प्रतिशत से अधिक निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध थीं। इसके अलावा छुपे प्रभारों संबंधी 50 प्रतिशत से अधिक शिकायतें निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध थीं। ऐसी शिकायतें पीएसबी के मामले में तुलनात्मक रूप से कम थीं। किंतु पेंशन संबंधी 95 प्रतिशत से अधिक शिकायतें पीएसबी के विरुद्ध थीं (चार्ट VI.23)।

सारणी IV.35: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को क्षेत्र वार मिली शिकायतें

बीओ कार्यालय	शिकायतों की संख्या	
	2009-10	2010-11
1	2	3
अहमदाबाद	4,149	5,190
बंगलुरु	3,854	3,470
भोपाल	3,873	5,210
भुवनेश्वर	1,219	1,124
चंडीगढ़	3,234	3,559
चेन्नै	12,727	7,668
गुवाहाटी	528	584
हैदराबाद	5,622	5,012
जयपुर	4,560	3,512
कानपुर	7,832	8,319
कोलकाता	5,326	5,192
मुंबई	10,058	7,566
नई दिल्ली	12,045	10,508
पटना	1,707	2,283
तिरु वनंतपुरम	2,532	2,077
कुल	79,266	71,274

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय।

11. वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार हुआ

4.89 हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन रिजर्व बैंक की शीर्ष प्राथमिकता रहा है। तदनुसार रिजर्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करता आ रहा है कि वे नयी शाखाओं के गठन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से और बीसी मॉडल के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करें। इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में सुधार हुआ (सारणी VI.37)।

वित्तीय समावेशन का कार्य अब भी बहुत पीछे है

4.90 वित्तीय समावेशन का कार्य अब भी बहुत पीछे है। मार्च 2010 के अंत में प्रत्येक 1000 लोगों में से मात्र 98 के

सारणी IV.36: बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों को मिली क्षेत्र वार शिकायतें - 2010-11

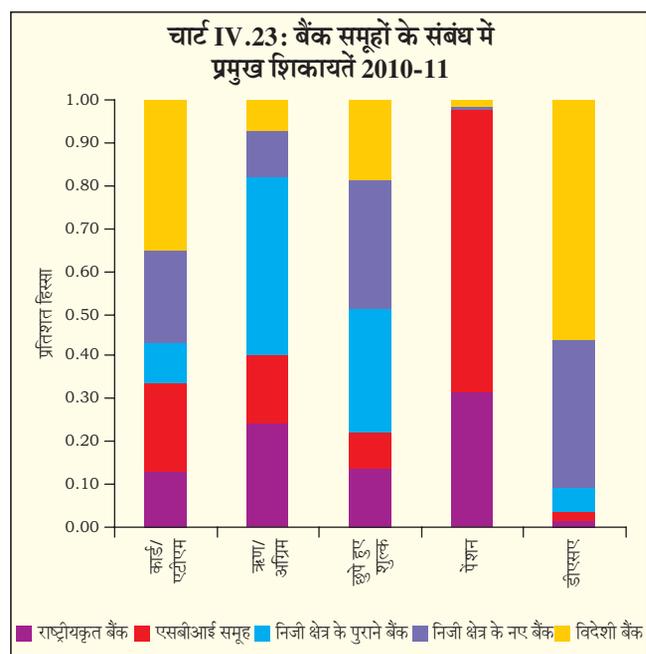
शिकायत का स्वरूप	सरकारी क्षेत्र बैंक	राष्ट्रीयकृत बैंक*	एसबीआई समूह	निजी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य क्षेत्रीय बैंक	शहरी सहकारी बैंक/ ग्रामीण बैंक/ अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (9+10)
जमा खाते	726	379	347	641	50	591	293	1,660	67	1,727
प्रेषण	3,019	1,574	1,445	816	65	751	175	4,010	206	4,216
क्रेडिट/डेबिट/एटीएम कार्ड	9,217	3,343	5,874	4,458	149	4,309	3,196	16,871	245	17,116
ऋण/अग्रिम	3,262	1,891	1,371	832	185	647	199	4,293	271	4,564
बिना पूर्व नोटिस के प्रभार	1,700	995	705	1,836	120	1,716	482	4,018	131	4,149
पेशान	5,746	1,746	4,000	43	1	42	21	5,810	117	5,927
प्रतिबद्धताओं संबंधी विफलता	1,971	1,035	936	747	94	653	161	2,879	83	2,962
प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट	120	58	62	928	12	916	658	1,706	16	1,722
नोट और सिक्के	86	36	50	25	1	24	19	130	16	146
उधारदाताओं की निर्धारित प्रथाओं का अनुपालन	8,799	4,680	4,119	3,378	254	3,124	1,163	13,340	786	14,126
बीसीएसबीआई कोड का अनुपालन	1,260	742	518	812	51	761	204	2,276	69	2,345
अन्य	4,835	2,675	2,160	2,323	167	2,156	440	7,598	606	8,204
विषय के बाहर	1,983	1,263	720	283	30	253	70	2,336	1,734	4,070
कुल शिकायतें	42,724	20,417	22,307	17,122	1,179	15,943	7,081	66,927	4,347	71,274
	(1.9)	(6.94)	(2.3)	(-24.1)	(-15.4)	(-24.6)	(-38.1)	(-11.8)	(30.2)	(-10.1)
प्रति शाखा शिकायतें	0.69	0.45	1.25	1.47	0.25	2.35	22.34	0.90		

*: आईडीबीआई बैंक लि. सहित।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े पूर्व वर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

स्रोत: बैंकिंग लोकपाल के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय।

पास ऋण खाता था और 600 के पास जमा खाते थे¹¹। इससे यह आवश्यकता रेखांकित हो जाती है कि वित्तीय समावेशन अभियान को सुविचारित नीति से मजबूत करना होगा।



¹¹ जमा खातों और ऋण खातों का डाटा बेसिक सांख्यिकी विवरणियां 2009-10 से लिया गया है।

सारणी IV.37: वित्तीय समावेशन में प्रगति

सं.	संकेतक	2009-10	2010-11
1	2	3	4
1	ऋण-जीडीपी	53.4	54.6
2	ऋण-जमा	73.6	76.5
3	प्रति शाखा जनसंख्या	14,000	13,466
4	प्रत्येक एटीएम जनसंख्या	19,700	16,243
5	जमा खाता धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत*	55.8	61.2
6	क्रेडिट खाता धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत*	9.3	9.9
7	डेबिट कार्ड धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत	15.2	18.8
8	क्रेडिट कार्ड धारकों की जनसंख्या का प्रतिशत	1.53	1.49
9	कुल नई बैंक शाखाओं के प्रतिशत के रूप में टायर 3-6 केंद्रों में खोली गई शाखाएं	40.3	55.4
10	कुल नई बैंक शाखाओं के प्रतिशत के रूप में अब तक बिना बैंक की सुविधा वाले केंद्रों में खोली गई शाखाएं	5.6	9.7

*: आंकड़ों का संबंध 2008-09 और 2009-10 से है।

- टिप्पणी: 1) ऋण और जमा से संबंधित आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलन पत्रों से लिए गए हैं।
- 2) बैंक शाखाओं, नई बैंक शाखाओं, टायर 3-6 केंद्रों में खोली गई शाखाओं और बिना बैंक की सुविधा वाले केंद्रों में खोली गई शाखाओं से संबंधित आंकड़े मास्टर ऑफिस फाइल, डीएसआईएम से लिए गए हैं। आंकड़ों का संबंध अप्रैल-मार्च से है।
- 3) शाखाओं के आंकड़ों में 2010-11 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं शामिल हैं।
- 4) 2010-11 से संबंधित जनसंख्या के आंकड़े भारत की 2011 की जनगणना से लिए गए हैं।
- 5) वर्ष 2009-10 से संबंधित प्रत्येक शाखा संबंधी जनसंख्या और प्रत्येक एटीएम के संबंध में जनसंख्या के आंकड़े भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2009-10 से दोहराए गए हैं।
- 6) वर्ष 2009-10 के लिए संकेतक 5-8 की गणना करने हेतु जनसंख्या संबंधी आंकड़े भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2009-10 में यथा उल्लिखित अनुसार प्रत्येक शाखा संबंधी जनसंख्या से लिए गए हैं।
- 7) जमा और ऋण खातों की संख्या से संबंधित आंकड़े आधारभूत सांख्यिकीय विवरणों 2009-10 से लिए गए हैं।
- 8) एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्डों की संख्या से संबंधित आंकड़े भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग से लिए गए हैं।

बैंक शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

बैंक शाखाओं की संख्या में 4,826 की वृद्धि हुई

4.91 पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में एससीबी की 4,826 शाखाएं बढ़ी। महत्वपूर्ण रूप से एससीबी द्वारा खोली गयी शाखाओं में से 22 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 42 प्रतिशत अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोली गयी थी। नयी बैंक शाखाओं में दक्षिणी क्षेत्र, जो कि पहले से अच्छा बैंकयुक्त है, में 2010-11 में नयी शाखाओं का हिस्सा सर्वाधिक था। दूसरी ओर न्यूनतम बैंकयुक्त क्षेत्र, अर्थात् उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 2010-11 में नयी शाखाओं का हिस्सा न्यूनतम था (सारणी VI.38)।

4.92 नयी बैंक शाखाओं के राज्य-वार विवरण से पता चला है कि अप्रैल-मार्च 2010-11 के दौरान खुली नयी बैंक शाखाओं में 11 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे था जिसके बाद महाराष्ट्र (10 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (9 प्रतिशत) और तमिलनाडु (7 प्रतिशत) का स्थान था।

4.93 टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में बैंक शाखाओं की संख्या बढ़ाने की दिसा में किया गया एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय दिसंबर 2009 में शाखा प्राधिकरण नीति को उदार बनाना था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में (अप्रैल-मार्च) एससीबी ने टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में अधिक शाखाएं खोली। 2010-11 अप्रैल-मार्च में

सारणी IV.38: क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों में नई बैंक शाखाओं का वितरण

(2010-11 अप्रैल-मार्च की अवधि के दौरान)

क्षेत्र	नई शाखाओं की संख्या	जनसंख्या समूह	नई शाखाओं की संख्या
1	2	3	4
मध्य क्षेत्र	874 (18.1)	ग्रामीण	1,077 (22.3)
पूर्वी क्षेत्र	650 (13.5)	अर्ध शहरी	2,011 (41.7)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	97 (2.0)	शहरी	865 (17.9)
उत्तरी क्षेत्र	1,120 (23.2)	महानगरीय	873 (18.1)
दक्षिणी क्षेत्र	1,263 (26.2)	-	-
पश्चिमी क्षेत्र	822 (17.0)	-	-
कुल	4,826(100.0)	कुल	4,826 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल नई बैंक शाखाओं का प्रतिशत दर्शाते हैं।

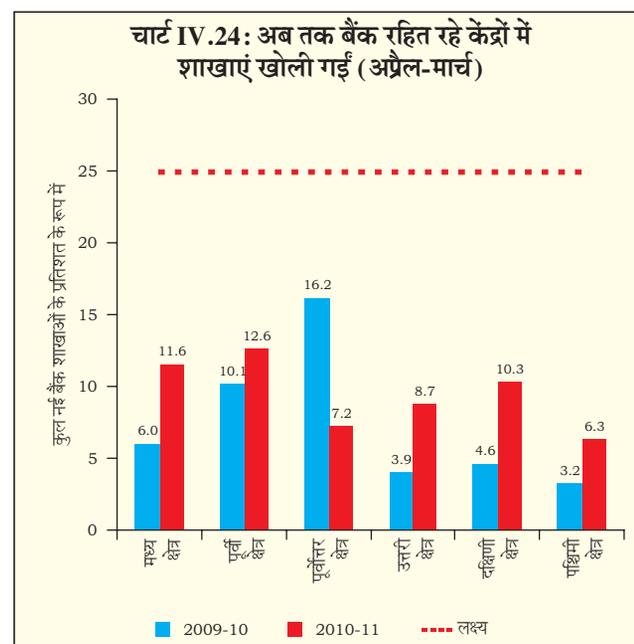
स्रोत: मास्टर ऑफिस फाइल

टियर 3 से टियर 6 वाले केंद्रों में आधे से अधिक नयी शाखाएं खोली गयी (सारणी IV.37)।

अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या बढ़ी

4.94 जुलाई 2011 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपनी कम-से-कम 25 प्रतिशत नयी शाखाएं बैंकरहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलें। अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी शाखाओं की संख्या 2009-10 के 281 से बढ़कर 2010-11 (अप्रैल-मार्च) में 470 हो गयी। 2010-11 में खोली गयी कुल नयी शाखाओं में से लगभग 10 प्रतिशत शाखाएं अब तक बैंकरहित रहे क्षेत्रों में खोली गयी जबकि पिछले वर्ष 6 प्रतिशत खोली गयी थीं। किंतु अद्यतन नीतिगत धारणा के अनुसार 2010-11 में बैंकरहित क्षेत्रों में खोली गयी कुल नयी शाखाओं का हिस्सा कम था (चार्ट IV.24)।

4.95 किये गये उपायों के बावजूद 2010-11 में उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या (आरआरबी की शाखाओं सहित) राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक थी (चार्ट IV.25)।



एटीएम के माध्यम से बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार

लगभग 50 प्रतिशत एटीएम ऑफ साइट स्थानों में खोले गये

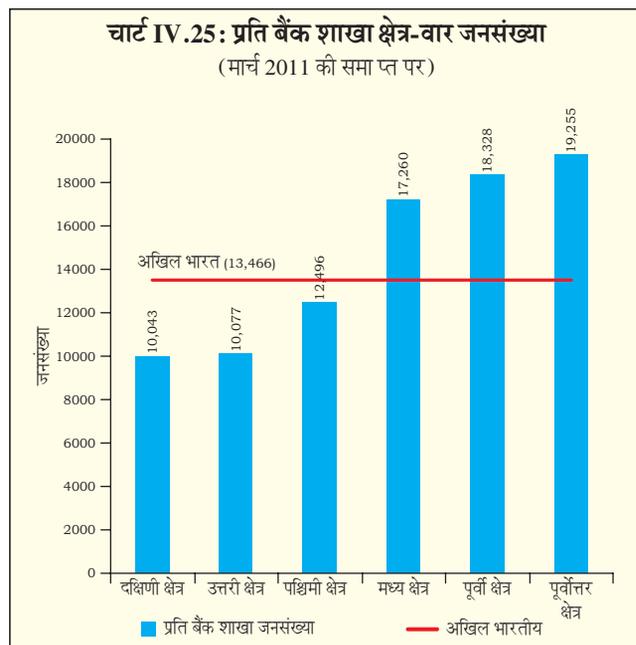
4.96 बैंकिंग पहुंच की दृष्टि से ऑन साइट एटीएम की तुलना में ऑफ साइट एटीएम अधिक संगत हैं। 2010-11 में खोले गये नये एटीएम में से 44 प्रतिशत ऑफ साइट एटीएम थे। 2010-11 में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 63 प्रतिशत और विदेशी बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 98 प्रतिशत नये एटीएम ऑफ साइट स्थानों में थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 41 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों द्वारा खोले गये एटीएम में से 49 प्रतिशत नये एटीएम ऑफ साइट स्थानों में थे।

कुल बकाया एटीएम में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा दस प्रतिशत

4.97 2010-11 में कुल एटीएम में लगभग दस प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में थे जिनमें से स्टेट बैंक समूह का हिस्सा 44 प्रतिशत था जिसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों का स्थान (38 प्रतिशत) था (सारणी IV.39 और चार्ट IV.26)।

एटीएम के अभिनियोजन में उत्तरोत्तर वृद्धि में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का हिस्सा सबसे कम था

4.98 2010-11 में एटीएम के वृद्धिशील अभिनियोजन में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का हिस्सा सबसे कम था (चार्ट IV.27)।



सारणी IV.39 : विभिन्न केन्द्रों में स्थित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के एटीएम की संख्या

बैंक समूह	(मार्च 2011 के अंत में)				
	ग्रामीण केन्द्र	अर्ध शहरी केन्द्र	शहरी केन्द्र	महानगरीय केन्द्र	सभी केन्द्र
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक	5,872	13,278	16,186	14,151	49,487
	(11.9)	(26.8)	(32.7)	(28.6)	(100.0)
राष्ट्रीयकृत बैंक*	2,718	5,680	8,132	8,306	24,836
	(10.9)	(22.9)	(32.7)	(33.4)	(100.0)
भारतीय स्टेट बैंक समूह	3,154	7,598	8,054	5,845	24,651
	(12.8)	(30.8)	(32.7)	(23.7)	(100.0)
निजी क्षेत्र के बैंक	1,262	4,784	7,576	10,029	23,651
	(5.3)	(20.2)	(32.0)	(42.4)	(100.0)
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	332	1,339	1,401	1,054	4,126
	(8.0)	(32.5)	(34.0)	(25.5)	(100.0)
निजी क्षेत्र के नए बैंक	930	3,445	6,175	8,975	19,525
	(4.8)	(17.6)	(31.6)	(46.0)	(100.0)
विदेशी बैंक	21	20	300	1,026	1,367
	(1.5)	(1.5)	(21.9)	(75.1)	(100.0)
कुल	7,155	18,082	24,062	25,206	74,505
	(9.6)	(24.3)	(32.3)	(33.8)	(100.0)
	[37.7]	[24.9]	[21.8]	[21.7]	[23.9]

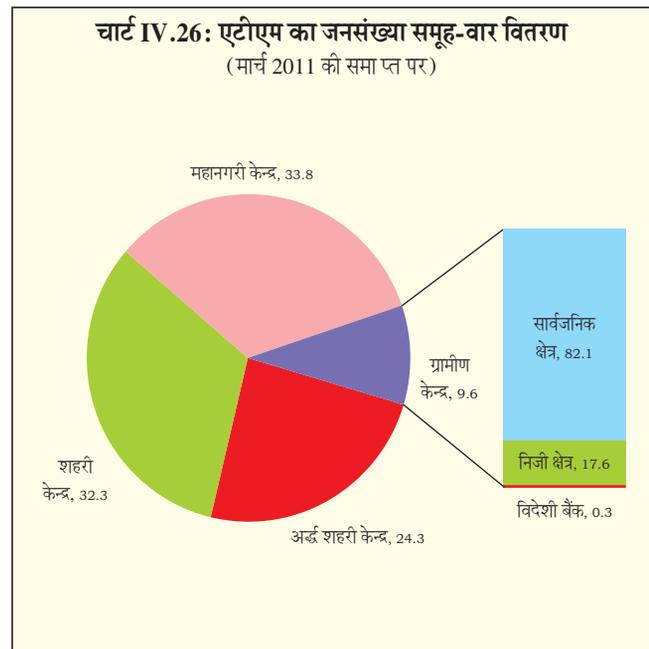
*: आईटीबीआई बैंक लि. सहित।

टिप्पणी: 1) कोष्ठक के आंकड़े प्रत्येक बैंक समूह के तहत कुल एटीएम के प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।
2) बड़े कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत घट बढ़ दर्शाते हैं।

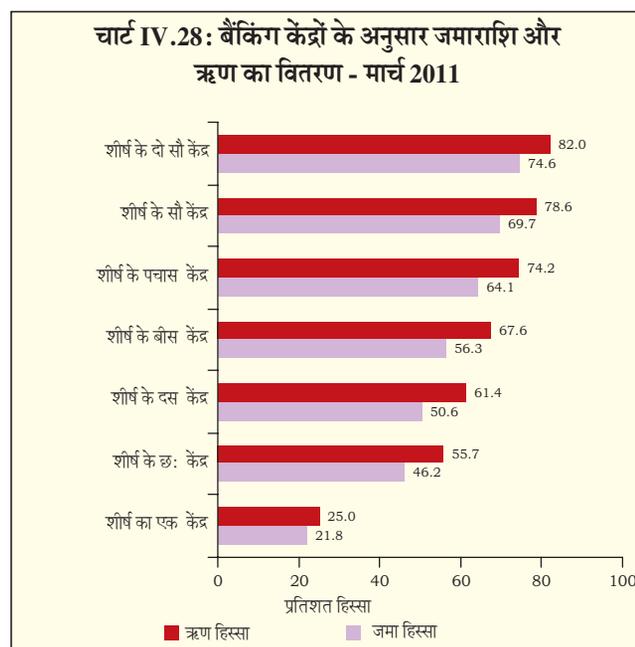
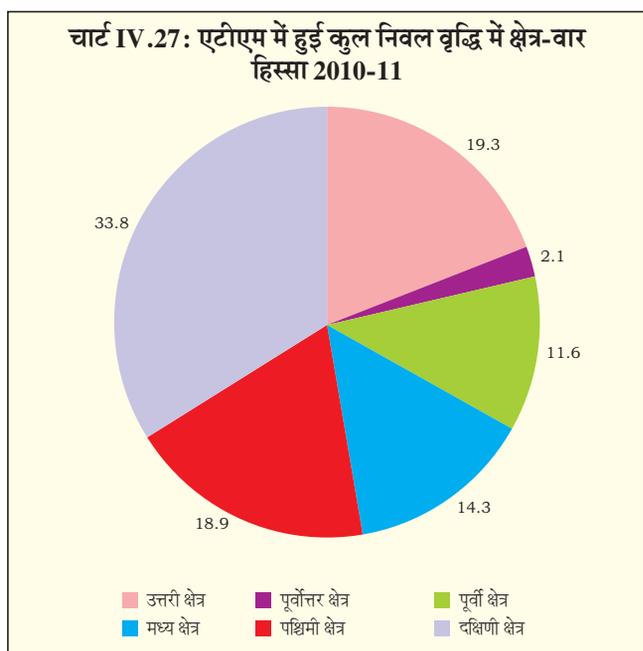
बैंक ऋण और जमाराशि का विवरण¹²

बैंकिंग कारोबार महानगरीय क्षेत्रों में संकेंद्रित है

4.99 ऋण और जमाराशि का स्थान-वार विवरण महानगरीय क्षेत्रों में अधिक संकेंद्रन दर्शाता है। 2010-11 में एकेले बृहमंबई क्षेत्र ने कुल जमाराशि का 22 प्रतिशत और कुल ऋण का 25 प्रतिशत



¹² आंकड़े एससीबी की मार्च 2011 की जमाराशि और ऋण पर तिमाही सांख्यिकी से लिये गये हैं।



हिस्सा दर्शाया। इसके अलावा श्रीलंका के छह केंद्रों अर्थात् बृहमंबई, दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बंगलुरु और हैदराबाद का 2010-11 में संयुक्त हिस्सा जमाराशि में 46 प्रतिशत और कुल ऋण में 56 प्रतिशत था। इन क्षेत्रों में जमाराशि की तुलना में ऋण का संकेन्द्रन अधिक था (चार्ट IV.28)।

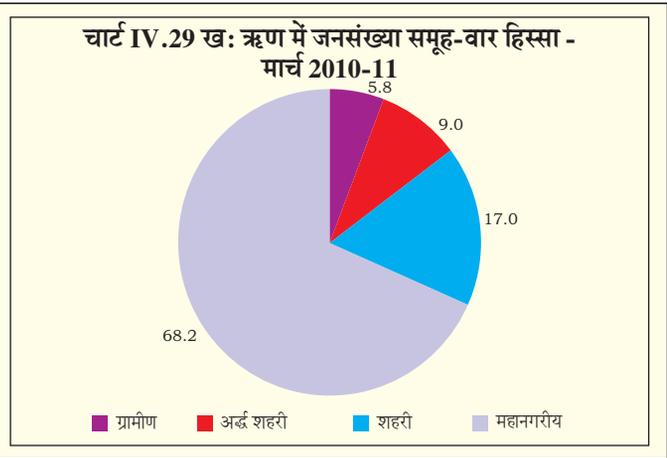
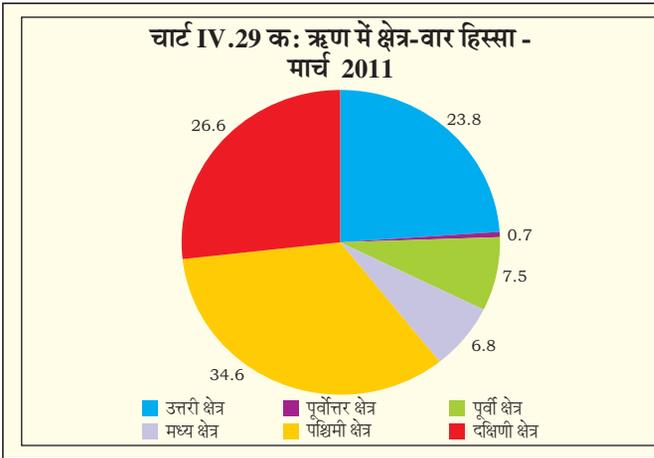
4.100 ऋण के भौगोलिक क्षेत्र-वार विवरण ने दर्शाया कि एक तिहाई से अधिक कुल ऋण पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित था। मार्च 2011 के अंत में कुल ऋण में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का हिस्सा काफी कम था ऋण का जनसंख्या-वार श्रेणीकरण दर्शाता है कि मार्च 2011 के अंत में कुल ऋण में 68 प्रतिशत महानगरीय क्षेत्रों से संबंधित था। जहां मार्च 2011 के अंत में ऋण का 9 प्रतिशत अर्ध शहरी क्षेत्रों का था, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह 6 प्रतिशत था (चार्ट IV.29क और IV.29ख तथा परिशिष्ट सारणी IV.11)।

रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन की सूक्ष्म निगरानी कर रहा है

4.101 वित्तीय समावेशन के अभियान को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि मार्च 2012 तक 2,000 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को कम-से-कम एक बैंकिंग आउटलेट के साथ कवर किया जाए। इसके अलावा 2,000 से कम

जनसंख्या वाले आसपास के गांवों को भी कवर करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया गया। इस योजना की सुगम प्रगति को सुसाध्य करने की दृष्टि से सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बोर्ड-अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) प्रस्तुत करें। बैंकों ने ऐसी योजनाएं तैयार कर ली हैं और रिजर्व बैंक इन योजनाओं के कार्यान्वयन की सूक्ष्म निगरानी कर रहा है। एफआईपी के तहत की गयी प्रगति सारणी IV.40 में दी गयी है।

4.102 कम-से-कम एक बैंकिंग आउटलेट के साथ कवर किये गये गांवों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 82 प्रतिशत बढ़ी। महत्वपूर्ण रूप से 2010-11 में एफआईपी के तहत कवर हुए कुल गांवों में से 47 प्रतिशत 2,000 से कम जनसंख्या वाले गांव थे। सारणी से यह समझा जा सकता है कि एफआईपी के तहत बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए बैंक बीसी पर अत्यधिक निर्भर हैं। 2010-11 में कुल में बी सी के माध्यम से लगभग 77 प्रतिशत गांव कवर हुए थे। "नो फ्रील्स" खातों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 82 प्रतिशत वृद्धि हुई। कुल "नो फ्रील्स" खातों में ओवरड्राफ्ट वाले "नो फ्रील्स" खातों का हिस्सा 2009-10 के 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 6 प्रतिशत हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और जनरल क्रेडिट कार्ड



(जीसीसी) की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में क्रमशः 15 प्रतिशत और 49 प्रतिशत वृद्धि हुई (सारणी IV.40)।

व्यष्टि वित्त

4.103 एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम ने 1992 में प्रायोगिक तौर पर हुई शुरुआत से अपने अस्तित्व के दो दशक पूरे किये हैं। इसे वित्तीय रूप से बाहर रह गये गरीब हाउसहोल्डों, सिविल सोसायटी संगठनों, बैंकों और साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय जैसे अनेकविध जोखिम धारकों से व्यापक समर्थन मिला। 2010-11 में 1.2 मिलियन नये एसएचजी बैंकों से क्रेडिटलिंक हुए और इन एसएचजी को 14,547 करोड़ रुपये का बैंक ऋण (दोबारा दिये गये ऋण सहित) दिया गया। इसके अलावा मार्च 2011 के अंत में 7.46 मिलियन एसएचजी के बैंकों में खाते थे। औसतन प्रति एसएचजी बचत की राशि 2010-11 के 65,180 रुपये के ऋण की तुलना में 9,405 रुपये थी। ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एसएचजी मूमेंट में भारत के बैंक रहित लोगों की वित्तीय सेवा संबंधी आवश्यकता दीर्घकालिक आधार पर पूरी करने की क्षमता है। किंतु इनके संबंध में यह चिंता भी कि ये मितव्ययता और बचत की गुंजाइश बढ़ाए बिना ऋण पर फोकस करते हैं। इसी प्रकार इसने अधिक लचीलापन दिखाने की आवश्यकता है ताकि एसएचजी स्तर पर ऋण उधार लेने की विविधता को समाहित किया जा सके। वर्तमान में नाबार्ड का यह प्रयास है कि विविध पक्षों से प्रकट की जा रही चिंताओं पर ध्यान दिया जाए जिनका लक्ष्य इन्हें बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अधिक लचीला, ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण चिंताओं को दूर करना है (सारणी IV.41)।

4.104 2010-11 में 461 एमएफआई को बैंकों से 7,605 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। 2010-11 में एमएफआई-लिंकेज कार्यक्रम के तहत ऋणों की संख्या और राशि में हुई वृद्धि एमएफआई-लिंकेज कार्यक्रम की तदनुसूची वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी (सारणी IV.41)।

सारणी IV.40: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति

क्रम सं.	विवरण	मार्च अंत की स्थिति के अनुसार		प्रगति: अप्रैल 10-मार्च 11
		2010	2011	
1	2	3	4	5
1	परिनियोजित किए गए कुल ग्राहक सेवा बिंदुओं की संख्या	33,042	58,361	25,319
2	शामिल किए गए कुल गांव	54,757	99,840	45,083
3	कवर किए गए गांव - जनसंख्या >2000	27,743	53,397	25,654
4	कवर किए गए गांव - जनसंख्या <2000	27,014	46,443	19,429
5	शाखाओं के माध्यम से कवर किए गए गांव	21,499	22,684	1,185
6	कारोबार संपर्क के माध्यम से कवर किए गए गांव	33,158	76,801	43,643
7	अन्य माध्यमों (मोबाइल बैं और एटीएम) से कवर किए गए गांव	100	355	255
8	कारोबार संपर्क के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	423	3,653	3,230
9	कवर किए गए कुल हाउसहोल्डों की संख्या (मिलियन में)	50	75	25
10	कवर किए गए कुल ग्रामीण घरों की संख्या (मिलियन में)	4,895	6,566	1,652
11	नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	.13	4	4
12	नो फ्रिल खातों में राशि (करोड़ रुपयों में)	8	199	190
13	ओडी सहित नो फ्रिल खातों की संख्या (मिलियन में)	20	23	3
14	ओडी सहित नो फ्रिल खातों में राशि (करोड़ रुपयों में)	1,07,519	1,43,862	36,343
15	बकाया जीसीसी की संख्या (मिलियन में)	.6	1	.4
16	बकाया जीसीसी की राशि (करोड़ रुपयों में)	814	1,308	494

सारणी IV.41: व्यक्ति वित्त कार्यक्रमों की प्रगति
(मार्च को समाप्त)

मद	स्व सहायता समूह					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (करोड़ रुपये में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	1.61(0.26)	1.59(0.27)	1.20(0.24)	12,254(2,015)	14,453(2,198)	14,547(2,480)
बैंकों के पास बकाया उधार	4.22(0.98)	4.85(1.25)	4.79(1.29)	22,680(5,862)	28,038(6,251)	31,221(7,829)
बैंकों के पास बचतें	6.12(1.51)	6.95(1.69)	7.46(2.02)	5,546(1,563)	6,199(1,293)	7,016(1,817)
	व्यक्ति वित्त संस्थाएं*					
	संख्या (मिलियन में)			राशि (करोड़ रुपये में)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा संवितरित उधार	581	691	469	3,732	8,063	7,605
बैंकों के पास बकाया उधार	1,915	1,513	2,176	5,009	10,148	10,689

*: बैंक ऋण लेने वाली सूक्ष्म -वित्त संस्थाओं की वास्तविक संख्या एक से अधिक बैंकों से ऋण का लाभ उठाने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कारण कम होगी।

टिप्पणी: 1) कोषक के आंकड़े स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत आनेवाले एसएचजी संबंधी ब्यौरे दर्शाते हैं।

स्रोत: नाबार्ड

आंध्र प्रदेश व्यक्ति वित्त अधिनियम

4.105 आंध्र प्रदेश विधान सभा ने 14 दिसंबर 2010 को "अ बिल टू प्रोटेक्ट द विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्राम एक्सप्लोइटेशन बाय द माइक्रो फाइनेन्स इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड फॉर द मॉर्टर्स कनेक्टेड देयरविथ ऑर इंसिडेंटल देयरटू" नामक विधेयक पारित किया। इसने इसी मामले पर 15 अक्टूबर 2010 को जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया। यह अधिनियम भारिबैं अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित व्यक्ति वित्त का कारोबार करने वाली सभी एनबीएफसी पर लागू है। इस विधेयक में अन्य के साथ ही निम्नलिखित बातें निर्धारित की गयी हैं: (i) प्रत्येक एमएफआई को जिले के पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत करना होगा, (ii) किसी एसएचजी का सदस्य एक से अधिक एसएचजी का सदस्य नहीं बन सकता, (iii) बकाया बैंक ऋण की स्थिति में कोई भी एमएफआई किसी एसएचजी/उसके सदस्यों को पंजीकरण प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना और ऋण नहीं दे सकती, (iv) सभी चुकौतियां ग्राम पंचायत या किसी नामित सार्वजनिक स्थल में करनी होंगी, (v) एमएफआई वसूली के लिए एजेंटों का उपयोग या वसूली के दमनकारी माध्यम का उपयोग नहीं कर सकती और (vi) ऋण वसूली मासिक किस्तों के आधार पर ही की जानी है।

4.106 यदि राज्य सरकारें पहले रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित एमएफआई के विनियमन के लिए अपने स्वयं के विधान बनाना शुरू करती हैं तो विनियमों का दोहराव हो सकता है जिससे विनियामक समस्या आ सकती है। एनबीएफसी के विनियमन का दायित्व रिजर्व बैंक को सौंपा गया है जिससे उसे एनबीएफसी-एमएफआई के विनियमन के अधिकार मिले हैं। यदि अन्य राज्य भी आंध्र प्रदेश जैसे अपने विधान बनाते हैं तो न सिर्फ दोहरे विनियमन की समस्या आयेगी बल्कि ग्राहक सुरक्षा की समस्या आयेगी क्योंकि तब उधारकर्ताओं पर विविध विनियमन लागू हो जाएंगे। यदि अलग-अलग राज्यों में एनबीएफसी-एमएफआई के विनियमन के अलग-अलग विधान बनते हैं तो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत एमएफआई का रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन करना और भी कठिन हो जाएगा। इससे उन एमएफआई का कारोबार प्रभावित हो जाएगा जो एक से अधिक राज्यों में कार्यरत हैं।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

समामेलन से हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की संख्या कम हो गयी

4.107 वाणिज्य बैंकों की व्यावसायिकता और सहकारी संस्थाओं के ग्रामीण उन्मुखीकरण को जोड़कर आरआरबी का गठन किया गया

ताकि बैंकिंग क्षेत्र की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता को प्रभावित किये बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ऋण प्रवाह को सुधारा जा सके। आरआरबी के प्रायोजक वाणिज्य बैंक के साथ केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें होती हैं। आरआरबी की वित्तीय सुदृढ़ता सुधारने के लिए उनके निरंतर पुनर्गठन तथा समामेलन के कारण उनकी संख्या 2000 के आरंभ के 196 से कम होकर 82 रह गयी। हाल के वर्षों में अनेक आरआरबी का पुनर्पूजीकरण भी किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक ऋण दे सकें।

4.108 आरआरबी के समग्र जमाराशि संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई। यह वृद्धि विशेष रूप से बचत जमाराशि के संदर्भ में मुखर थी जिसके बाद चालू खाते का स्थान था। आरआरबी के उधार में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई जिसका कारण प्रायोजक बैंक, नाबार्ड और अन्य से अधिक उधार था। आस्ति पक्ष में रिजर्व बैंक में आरआरबी का शेष पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया (सारणी IV.42)।

4.109 आरआरबी का निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में बढ़ गया। परिचालन लाभ में गिरावट के बावजूद प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में गिरावट के चलते निवल लाभ में वृद्धि हुई। किंतु निरपेक्ष संदर्भ में निवल लाभ में वृद्धि के बावजूद आस्ति पर प्रतिलाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी। आरआरबी की प्रति शाखा लाभप्रदता और प्रति कर्मचारी लाभप्रदता में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में वृद्धि हुई (सारणी IV.43)।

4.110 यह महत्वपूर्ण बात है कि 2010-10 में आरआरबी के कुल ऋण का 80 प्रतिशत से अधिक भाग प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र से जुड़ा था। 2010-11 में आधे से अधिक ऋण कृषि क्षेत्र को मिला था हालांकि कुल ऋण में कृषि ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कुछ कम हो गया था। कृषि के भीतर उधार का लगभग 74 प्रतिशत भाग फसल ऋण था। कृषेतर क्षेत्र में 2010-11 में अधिकतर ऋण अन्य प्रयोजनार्थ दिया गया था (सारणी IV.44)।

सारणी IV.42: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मद	मार्च के अंत में		प्रतिशत घटबढ़
		2009-10	2010-11अ	
1	2	3	4	5
1	शेयर पूंजी	197	197	-
2	आरक्षित निधियां	8,065	9,582	18.8
3	शेयर पूंजी जमा	3,985	4,060	1.9
4	जमाराशियां	1,45,035	1,66,232	14.6
	4.1 चालू	8,065	9,190	13.9
	4.2 बचत	75,906	91,136	20.0
	4.3 सावधि	61,064	65,906	7.9
5	से उधार	18,770	26,491	41.1
	5.1 नाबार्ड	12,500	15,240	21.9
	5.2 प्रायोजक बैंक	6,186	9,602	55.2
	5.3 अन्य	84	1,649	1,863.0
6	अन्य देयताएं	8,041	8,797	9.4
	कुल देयताएं/ आस्तियां	1,84,093	2,15,359	17.0
7	नकदी	1,784	2,119	18.8
8	आरबीआइ के पास शेष	8,145	9,853	21.0
9	अन्य बैंक शेष	39,102	44,080	12.7
10	निवेश	47,289	55,280	16.9
11	ऋण और अग्रिम (निवल)	79,157	94,715	19.7
12	अचल आस्तियां	379	457	20.6
13	अन्य आस्तियां #	8,237	8,855	7.5
<i>जापन मद</i>				
1	ऋण - जमा अनुपात	57.1	59.69	
2	निवेश - जमा अनुपात	32.6	55.48	
3	(ऋण + निवेश) - जमा अनुपात	87.2	115.17	
अ: अर्न्तम।				
#: संचित हानि सहित।				
- : नही नगण्य।				
स्रोत: नाबार्ड।				

13. स्थानीय क्षेत्र के बैंक

स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की आस्तियों में कम वृद्धि दर्ज हुई

4.111 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का बहुत छोटा घटक है। छोटे आकार के होने के बावजूद इन संस्थाएं स्थानीय उन्मुख हैं जिससे वे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से आने वाले स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं बेहतर रूप से पूरी कर सकते हैं। इस समय भारत में चार एलएबी कार्यरत हैं जिनमें से एक एलएबी नामतः कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. के पास सभी एलएबी की कुल आस्तियों का दो तिहायी से अधिक भाग है।

4.112 एलएबी की कुल आस्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में कम वृद्धि हुई। समग्र गिरावट के अनुरूप एलएबी के

सारणी IV.43: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये से)

क्र. सं.	मद	2009-10 (82)	2010-11अ (82)	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4	5
क. आय (i + ii)		13,835	16,220	17.2
i	ब्याज आय	12,945	15,225	17.6
ii	अन्य आय	890	995	11.8
ख. खर्च (i+ii+iii)		11,951	14,232	19.1
i	खर्च किया गया ब्याज	7,375	8,612	16.8
ii	परिचालन व्यय	3,547	4,905	38.3
	जिसमें से: वेतन बिल	2,676	3,825	42.9
iii	प्रावधान और आकस्मिक व्यय	1,029	715	(-)30.5
ग. लाभ				
i	परिचालन लाभ	2,913	2,703	(-)7.2
ii	निवल लाभ	1,884	1,988	5.5
ङ. कुल आस्तियां		1,84,093	2,15,359	17.0
च. वित्तीय अनुपात				
i	परिचालन लाभ	1.7	1.3	
ii	निवल लाभ	1.1	0.9	
iii	आय (क+ख)	8.3	7.5	
	क) ब्याज आय	7.7	7.1	
	ख) अन्य आय	0.5	0.5	
iv	व्यय (क+ख+ग)	7.1	6.6	
	क) खर्च किया गया ब्याज	4.4	4.0	
	ख) परिचालन व्यय	2.1	2.3	
	जिसमें से: वेतन बिल	1.6	1.6	
	ग) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.6	0.3	

अं: अनंतिम

टिप्पणी: 2. वित्तीय अनुपात औसत कुल आस्तियों के संबंध में है।

3. कोष्ठक के आंकड़े आरआरबी की कुल संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: नाबार्ड।

सकल अग्रिम की पिछले वर्ष की 22 प्रतिशत की वृद्धि दर 2010-11 में कम होकर 21 प्रतिशत रह गयी। इसके विपरीत जमाराशि संग्रह वृद्धि पिछले वर्ष के 20 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 2010-11 में 22 प्रतिशत हो गयी (सारणी IV.45)।

4.113 एलएबी की आस्ति वृद्धि में गिरावट आने के बावजूद उनका आस्तियों पर प्रतिलाभ 2009-10 के 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 1.8 प्रतिशत हो गया जिसका मुख्य कारण निवल ब्याज आय में वृद्धि होना था। प्रावधानीकरण और आकस्मिक व्यय में 2010-11 में उच्च वृद्धि होने के बावजूद निवल लाभ में हुई वृद्धि परिचालन लाभ वृद्धि से कम थी (सारणी IV.46)।

14. निष्कर्ष

बैंकों के निष्पादन में सुधार हुआ किंतु अब भी चिंताएं बनी हुई हैं

4.114 सिंहावलोकन से पता चलता है कि परिचालनात्मक वातावरण की आवश्यकता के बावजूद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने

सारणी IV.44: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण का प्रयोजन-वार वितरण

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रयोजन	मार्च को समाप्त		
	2010	2011अ	
1	2	3	4
I कृषि (i से iii)	46,282	55,067	
	(55.9)	(54.9)	
i	अल्पकालिक कर्ज (फसल ऋण)	33,663	40,663
ii	मीयादी ऋण (कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए)	12,619	14,404
iii	अप्रत्यक्ष अग्रिम	-	-
II कृषि से इतर (i से iv)	36,537	45,231	
	(44.1)	(45.1)	
i	ग्रामीण कारीगर	810	881
ii	अन्य उद्योग	1,598	2,625
iii	खुदरा व्यापार	5,234	5,082
iv	अन्य प्रयोजन	28,895	36,643
कुल (I+II)	82,819	1,00,298	
ज्ञापन मदें:			
(क)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	68,823	82,643
(ख)	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	13,956	17,655
(ग)	कुल ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा	83.1	82.4

अ : अनंतिम

- : नहीं नगण्य।

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल ऋण में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत: नाबार्ड

2010-11 में हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रसारित अनुवर्ती प्रभाव से निरंतर पुनरुज्जीवन दर्शाया है। यह अन्य बातों के साथ ही उच्च ऋण वृद्धि, जमाराशि वृद्धि, आस्ति पर बेहतर प्रतिलाभ, सुदृढ़ सीआरएआर और जीएनपीए अनुपात में सुधार में देखा जा सकता है। किंतु सकारात्मक बातों के बावजूद भारतीय बैंकिंग में कुछ चिंताएं निरंतर बनी हुई हैं।

कार्यकुशलता में और सुधार की आवश्यकता है

4.115 विशेष रूप से उच्च प्रतियोगिता और उच्च ब्याज दर वातावरण में लाभप्रदता बनाये रखना एक चुनौती ही है। फिर भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में आस्ति पर प्रतिलाभ में कुछ सुधार किया। किंतु विस्तृत विश्लेषण दर्शाता है कि एनआईएम, जो कि कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में पहले से ही अधिक है, में और वृद्धि हुई। इस प्रकार कार्यकुशलता और लाभप्रदता के हित में एनआईएम कम करने, "अन्य आय" बढ़ाने और परिचालन व्यय कम करने की आवश्यकता है।

सारणी IV.45: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की प्रोफाइल
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	आस्तियां		जमा		सकल अग्रिम	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	651 (68.8)	750 (67.8)	532 (72.2)	648 (72.2)	347 (65.0)	420 (65.2)
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	127 (13.4)	158 (14.3)	101 (13.7)	122 (13.6)	84 (15.7)	100 (15.5)
कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	120 (12.7)	138 (12.5)	75 (10.2)	93 (10.4)	78 (14.6)	88 (13.7)
सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड	48 (5.1)	61 (5.5)	29 (3.9)	34 (3.8)	25 (4.7)	36 (5.6)
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक	946 (100.0)	1,107 (100.0)	737 (100.0)	897 (100.0)	534 (100.0)	644 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े कुल में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

स्रोत: परोक्ष विवरणियों (देशों) पर आधारित है।

आस्ति-गुणवत्ता की सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है

4.116 नीतिगत दरों में निरंतर वृद्धि के बीच आस्ति-गुणवत्ता बनाये रखना चुनौतीपूर्ण कार्य था। पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में जीएनपीए अनुपात में सुधार होने के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र में

आस्ति-गुणवत्ता संबंधी कुछ चिंताएं निरंतर बनी रहीं। पिछले दो वर्षों के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा खाते डालने का अनुपात अधिक रहा है जो लाभप्रदता की कीमत पर तुलनपत्र की स्थिति अच्छी दर्शाने का प्रयास है। इसके अलावा पुनर्गठित मानक खातों के संबंध में हमेशा चिंता बनी रही है, अर्थात् यह कि उनमें से कितने पुनः एनपीए श्रेणी में चले जाएंगे। साथ ही एक चिंता यह भी है कि 2010-11 में देशी बैंकों के कुल वृद्धिशील एनपीए का एक बड़ा भाग कृषि के एनपीए से आया था।

सारणी IV.46: स्थानीय क्षेत्र के बैंकों का वित्तीय निष्पादन

(राशि करोड़ रुपये)

विवरण	2009-10	2010-11	प्रतिशत घटबढ़
1	2	3	4
क. आय (i+ii)	104	124	19.2
i) ब्याज आय	86	107	24.4
ii) अन्य आय	18	17	-5.6
ख. खर्च (i+ii+iii)	91	105	15.4
i) खर्च किया गया ब्याज	51	55	7.8
ii) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	8	13	62.5
iii) परिचालन व्यय <i>जिसमें से:</i>	32	37	15.6
वेतन बिल	14	17	21.4
ग. लाभ			
i) परिचालन लाभ / हानि	21	32	52.4
ii) निवल लाभ / हानि	13	19	46.2
घ. निवल ब्याज आय	35	52	48.6
ड. कुल आस्तियां	946	1,107	17.0
च. वित्तीय अनुपात			
i) परिचालन लाभ	2.4	3.1	
ii) निवल लाभ	1.5	1.9	
iii) आय	12.0	12.1	
iv) ब्याज आय	9.9	10.4	
v) अन्य आय	2.1	1.7	
vi) व्यय	10.5	10.2	
vii) खर्च किया गया ब्याज	5.9	5.4	
viii) परिचालन व्यय	3.7	3.6	
ix) वेतन बिल	1.6	1.7	
x) प्रावधान और आकस्मिक व्यय	0.9	1.3	
xi) स्प्रेड (निवल ब्याज आय)	4.0	5.1	

टिप्पणी: 'च' के तहत सभी अनुपात कुल औसत आस्तियों के संबंधित हैं।

स्रोत: ऑफ-साइट विवरणियों (घरेलू) पर आधारित।

वित्तीय समावेशन को और सुदृढ़ करने का कार्य जारी रखने की आवश्यकता है

4.117 बैंकिंग क्षेत्र द्वारा किये गये प्रयासों के बावजूद वित्तीय समावेशन में कमी रहना गंभीर मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगामी वर्षों में इस मामले को सुलझाने पर बैंकिंग क्षेत्र को अधिक ध्यान देना होगा। इसके साथ ही उन बाधाओं पर ध्यान देना भी आवश्यक है जो कि हाल के वर्षों में बैंकिंग सेवाएं देते समय देखी गयी थीं। इनमें अन्य बातों के अलावा शाखाओं की तुलना में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना, अब तक बैंक रहित रहे क्षेत्र में नयी शाखाएं खोलने का कम प्रतिशत, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खोली गयी शाखाओं का कम प्रतिशत और ओवरड्राफ्ट वाले "नो फ्रील्स" खातों का कम प्रतिशत।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है

4.118 भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के वर्तमान कारोबारी दृश्य की एक असंतोषजनक विशेषता यह है कि बैंकिंग कारोबार कुछ ही महानगरीय केंद्रों में सेंकेंद्रित हो गया है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का लगभग आधा बैंकिंग कारोबार शीर्ष 6 महानगरीय केंद्रों में सेंकेंद्रित हो गया है। अधिक चेतावनीपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों का ऋण अनुपात बहुत कम है। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग में काफी पीछे हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे ऋण-जीडीपी अनुपात, जो कि भारत जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में कम स्तर पर है, के संदर्भ में ऋण पहुंच बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को अधिक ऋण वृद्धि ऋण गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है

4.119 अर्थव्यवस्था में ऋण तेजी का कोई सबूत न होने के बावजूद एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी ऋण और स्थावर संपदा जैसे कुछ क्षेत्रों में देखी गयी उच्च ऋण वृद्धि के कारण निगरानी आवश्यक हो गयी है। एनबीएफसी को ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई जिसकी सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण में भी पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में उच्च वृद्धि हुई किंतु इसका मुख्य कारण दूरसंचार कंपनियों को 3जी स्पेक्ट्रम नीलामी में सहभागी होने के लिए दिया गया ऋण था। इस प्रकार यह आगामी वर्षों में कम होने की संभावना है। फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण और निजी ऋण में देखी गयी वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिमपूर्ण है क्योंकि ये ऋण आस्ति देयता असंतुलन बढ़ा सकते हैं। इन्हीं कारणों से वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण में हुई वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है

4.120 दूसरी ओर 2010-11 के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य और कृषि क्षेत्र के अग्रिमों का लक्ष्य पूरा न होना

अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र को समान ऋण वितरण की दृष्टि से चिंता उभारता है। बैंक समूहों ने रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य समग्र स्तर पर पूरे करने के बावजूद बैंक स्तर पर ऐसे अनेक बैंक हैं जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लिए समग्र रूप से निर्धारित उधार और कृषि ऋण का लक्ष्य पूरा करने में समर्थ नहीं थे। कृषि उधार का लक्ष्य पूरा न कर सकने वाले बैंकों की उच्च संख्या चिंता उभारती है क्योंकि भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग उनकी जीविका के लिए अब भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है।

वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की आवश्यकता है

4.121 परिचालन पक्ष में, बैंकिंग सेवाएं देने में एटीएम से प्राप्त सुविधा के बावजूद डेबिट कार्ड का प्रयोग निरंतर कम बना रहा क्योंकि 30 प्रतिशत जमा खाताधारकों के पास ही डेबिट कार्ड थे। क्रेडिट कार्ड के प्रयोग की स्थिति बदतर थी क्योंकि 2 प्रतिशत से भी कम जनसंख्या के पास क्रेडिट कार्ड थे। इसके अलावा बकाया क्रेडिट कार्डों की संख्या में भी हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गयी। ये प्रौद्योगिकीय साधन बैंकिंग सेवाओं की गति और गुणवत्ता बढ़ाते हैं, अतः देश में कार्डों का प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है।

बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता है

4.122 बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता एक अन्य क्षेत्र है जिसमें निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है ताकि औपचारिक बैंकिंग माध्यम में अधिकाधिक ग्राहकों को लाया जा सके। यह एक स्वागत योग्य बात है कि समग्र स्तर पर विभिन्न बैंकिंग लोकपालों के कार्यालयों में प्राप्त शिकायतों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2010-11 में गिरावट आयी है। किंतु विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों को डीएसए द्वारा दी जा रही सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने की आवश्यकता है क्योंकि डीएसए संबंधी प्राप्त 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें इन बैंकों से संबंधित थीं। इसके अलावा इन दो बैंक समूहों को ग्राहकों पर लगाये जाने वाले प्रभारों की जानकारी उन्हें देकर पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए। इसका कारण यह है कि छुपे प्रभारों संबंधी अधिकतर शिकायतें भी

इन्हीं दो बैंक समूहों के विरुद्ध प्राप्त हुई थीं। पीसीबी द्वारा जिस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है वह है पेंशन संबंधी सेवाएं। सामान्यतः सभी बैंक समूहों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्रस्तावित करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि लगभग एक चौथाई शिकायतें कार्डों से ही संबंधित थीं।

विदेशी बैंकों के परिचालनों की समीक्षा की आवश्यकता है

4.123 इस समय एक मामला जो चिंताएं उत्पन्न करता है वह विदेशी बैंकों के परिचालनों का है। यह वस्तुस्थिति है कि इन बैंकों की उपस्थिति मुख्यतः महानगरीय क्षेत्रों में ही है जिससे विशेष रूप से बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने में इनकी भूमिका सीमित है। इसके अलावा यह भी वस्तुस्थिति है कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का इनका लक्ष्य कम होने के बाद भी इनमें से बहुत से बैंक इसे पूरा नहीं कर

पाते हैं। साथ ही निर्यात ऋण का निर्धारित लक्ष्य भी इनमें से बहुत से बैंक पूरा नहीं कर पाते। अन्य पक्ष में संवेदनशील क्षेत्र को ऋण, विशेष रूप से स्थावर संपदा को ऋण अधिक था। इसके अतिरिक्त विदेशी बैंकों का तुलनपत्रेतर एक्सपोजर विशेष रूप से अधिक था जो कि प्रणालीगत जोखिम उभारता है।

4.124 निष्कर्ष के रूप में बैंकिंग क्षेत्र द्वारा सामना किये जा रहे मामलों पर ध्यान केंद्रित करना अर्थव्यवस्था में वृद्धि और साम्यता प्राप्ति के व्यापक हित में अनिवार्य है। ये मामले सुलझ जाने के बाद भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और गहन और सुदृढ़ होने की क्षमता है। इन मामलों पर अधिक ध्यान देने से अर्थव्यवस्था का बेहतर वित्तीयकरण होने में सहायता मिलेगी जिससे मध्यावधि से दीर्घावधि में व्यापक-आधारित आर्थिक वृद्धि होगी।